सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा 25 मार्च, 2017 ई0

------------- शनिवार, तिथि-------------------

पंचम सत्र 04 चैत्र, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बिजली के दर में.........

अध्यक्ष : समय पर उठाइयेगा न । यह क्या तरीका है ? क्या आपलोग चाहते हैं कि प्रश्नकाल नहीं चले ? यही बता दीजिए तो हमलोग एजेन्डा से ही निकाल देंगे । आप को मालूम है नेता प्रतिपक्ष कि इन सब बातों को उठाने का क्या समय होता है ? तब अनावश्यक अगर 5 मिनट भी इस में समय जाया कीजिएगा तो किसी माननीय सदस्य का प्रश्न मारा जायेगा । आप जानते हैं कब उठाने की स्थिति होती है । आप समय पर उठाइयेगा हम आप की सुनेंगे।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप समय पर उठाइयेगा आसन जरूर सुनेगा आपकी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार की साढ़े 11 करोड़ जनता का सवाल है और निजी कंपनियों के द्वारा.........

अध्यक्ष : ठीक है, आप समय पर उठाइयेगा।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-12(श्री भाई वीरेन्द्र)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य में प्रत्येक वर्ष औसतन कैंसर के 90 हजार नये रोगी पाये जाते हैं, परन्तु मृत्यु संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन रोगियों की चिकित्सा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं ट्रस्ट के अधीन संचालित महावीर कैंसर संस्थान, पटना में उपलब्ध है । कैंसर के रोगियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 60 हजार से 80 हजार रूपये तक दिये जाते हैं, जिसमें दवा भी उपलब्ध कराया जाता है।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 90 हजार कैंसर के नये रोगी प्रत्येक साल होते हैं, लेकिन हमने कहा है

कि 90 हजार में 40 हजार रोगी चिकित्सा अभाव और दवा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य के मुख्य चिकित्सा संस्थानों पी0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0, आइ0जी0आई0एम0एस0 और एम्स में कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु रीजनल सेंटर को उन्नत बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य से हमने कहा कि लगभग 90 हजार कैंसर के रोगी पाये जाते हैं, लेकिन मृत्यु के सन्दर्भ में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने दो केन्द्रों के अलावे विभिन्न केन्द्रों पर माननीय सदस्य की चिंता को अपने नोटिस में लिया है, आगे उसपर विचार किया जायेगा। वैसे कैंसर की रोकथाम के उपाय में भी सरकार काफी आगे है और विभिन्न तरह के रोकथाम के कार्यों पर भी सरकार अपना कदम बढ़ायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने रीजनल सेंटर को उन्नत बनाने हेतु बिहार के चिकित्सालय के लिए मांग किया है कि आइ0जी0आई0एम0एस0, डी0एम0सी0एच0 एवं एम्स में कैंसर रोगियों के उन्नत इलाज के लिए क्या सरकार रीजनल सेंटर खोलना चाहती है ?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, आइ0जी0आई0एम0एस0 में 120 करोड़ की लागत से स्टेट कैंसर संस्थान स्थापित किया जाना है। उसकी प्रक्रिया शुरू होनेवाली है।

श्री भाई वीरेन्द्र : पी0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0 में ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब सरकार ने जवाब दे दिया।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13(श्री सचीन्द्र प्र0सिंह)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया।)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम आसन की तरफ से आपसे आग्रह करते हैं कि अभी सारे माननीय सदस्यों का यह प्रश्नकाल होता है। आपके भी सदस्य हैं, सत्ताधारी दल के भी सदस्य हैं । इस तरह के मामलों को उठाने के लिए अपनी नियमावली में एकदम सुसंगत प्रावधान है और उस समय आपको आसन की तरफ से भरपूर मौका दिया जायेगा । फिर इस तरह से सदस्यों के प्रश्नों को बाधित करने का हमारी समझ से कोई औचित्य नहीं है।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय......

अध्यक्ष : अब इनको बैठाइयेगा तब न बोलियेगा । ये बीच में खड़े हैं और आप बोलना चाहते हैं। आप बोलिये कि आप ही के सदस्य वेल में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हमको बोलने दीजिए। ये बैठ जाएं, तब आप बोलिये।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : मजबूरी है सर।

अध्यक्ष : कहां मजबूरी है ? उस दल के नेता को आसन इजाजत दे रहा है, फिर मजबूरी क्या है ? हम आपको यह भी सूचना देना चाहते हैं कि आज ही सरकार की तरफ से माननीय मंत्री, ऊर्जा ने बताया है कि वह बिजली दर की बढ़ोत्तरी के संबंध में सरकार की तरफ से वक्तव्य इस सदन में देना चाहते हैं। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मेरा आसन की तरफ से आग्रह होगा कि यह समय माननीय सदस्यों का होता है। आप जो बात उठाना चाहते हैं जिसका आपने जिक्र किया है, आपके सदस्यों की तरफ से सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं और सरकार ने भी इच्छा जाहिर की है इस संबंध में अपना वक्तव्य देने के लिए, तो आपसे आग्रह यही होगा कि आप समय पर उसको उठायें और सरकार जो वक्तव्य देना चाहती है उसको भी सुन लें । फिर आपको जो स्टैंड लेना होगा वह निर्णय कीजिएगा।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से अगर कोई बात कही जा रही है तो नेता प्रतिपक्ष को बैठना तो चाहिए, आसन तो ग्रहण करना चाहिए।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर चले गये)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य का मामला है, साढ़े 11 करोड़ लोगों का सवाल है- गांव, शहर, गरीब और महोदय निजी, प्राइवेट जो कंपनी बिजली का बिहार में है उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार इतना बढ़ावा देने का काम कर रही है।

अध्यक्ष : यह उस समय कहियेगा।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार इसको वापस ले।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, इसका मतलब यही हुआ न कि आपको जब बोलना हुआ तो आपके सदस्य सीट पर रहेंगे और दूसरे बोलेंगे तो ये लोग वेल में चले जायेंगे। आप ही कहिये क्या यह न्यायसंगत है ? आप को जब बोलना होगा तो आपके सदस्य सीट पर आ जायेंगे और कोई दूसरा बोलेगा तो...........

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले उनको आसन तो ग्रहण करना चाहिए अगर स्पीकर साहब का कुछ रूलिंग हो रहा है तो उनको बैठना तो चाहिए।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-9(श्री अजीत शर्मा)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : यह उद्योग विभाग को स्थानान्तरित है।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी उद्योग विभाग विभाग में आया था और वहां से स्थानान्तरित हुआ था।

अध्यक्ष : मंत्री जी, सरकार की तरफ से इस बात को अच्छे तरीके से यह देख लीजिए कि आखिर इस प्रश्न का जवाब उद्योग विभाग देगा या स्वास्थ्य विभाग देगा।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, यह उद्योग विभाग का ही सब्जेक्ट है इसलिए उद्योग विभाग में स्थानान्तरित है।

तारांकित प्रश्न सं0-1404(श्री राम विशुन सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है।

2-वस्तुस्थिति यह है कि पोस्टमार्टम की सुविधा जिला स्तर पर ही की गयी है।

3- तत्काल अनुमंडल स्तर पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि जगदीशपुर जो है- हमारे बिहिया, शाहपुर, पीरो बीच सेंटर है तो वहां सरकार एक पोस्टमार्टम का व्यवस्था करावे जगदीशपुर अनुमंडलीय हॉस्पीटल में जो एन0एच0-30 पर है।

तारांकित प्रश्न सं0-1405(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा एक अल्पसूचित प्रश्न था।

अध्यक्ष : अब आगे चला गया, देखेंगे।

टर्न-2/अशोक/25.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या-1406(श्री विजय कुमार खेमका)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1407(श्री राम विलास पासवान)

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, प्रश्नगत प्रखण्ड और गांव में वस्तुस्थिति यह है कि कहलगांव प्रखण्ड के 272 और पिरपैंती प्रखण्ड के 386 घर जले थे, सभी को 9800 रूपया सहहाय राशि दे दी गई है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूरा गरीब सब का घर जला था तथा उसमें इन्दिरा आवास देने की बात थी वह भी एक भी परिवार को नहीं मिला हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस परिवार को इन्दिरा आवास भी....

अध्यक्ष : आप प्रश्न में तो मुआवजा की बात किये हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मुआवजा की बात है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस तिथि को इन जले हुये घर के गृहवासियों को भुगतान किया गया ?

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : ये जिला से जो प्राप्त प्रतिवेदन आया है, उन्होंने मूल रूप से, प्रश्नकर्त्ता ने तो 100 घर की बात कही है, इन्होंने तो टोटल 386 घर की बात कही हैं दो प्रखण्ड का तो वर्ष 2016 में और तिथि जिला ने नहीं दिया है, तिथि की जानकारी जिला से प्राप्त करके आपको दे देंगे लेकिन मिल गया है 9800 रूपया और जहां तक इन्दिरा आवास का सवाल, इन्दिरा आवास हम नहीं देते, हमारा विभाग गृहक्षति अनुदान देती हैं ।

अध्यक्ष : जो प्रश्न ही स्वीकृत नहीं हुआ है, जिस पूरक की इजाजत ही नहीं मिली, उसका उत्तर आप क्यों दे रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1408(श्री विद्या सागर केशरी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

पोस्टमार्टम की सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों में ही की गई है तत्काल रेफरल अस्पताल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था की योजना नहीं है ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, 40-50 कि.मी. की दूरी हैं नरपतगंज से और कई एक ग्रामीण क्षेत्र से लोग बाढ़ के समय में खास करके 40-50 कि.मी. की दूरी तय कर बाढ़ के समय, इतना दूरी तय कर जाना....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य केशरी जी, इसके पहले श्री राम विशुन सिंह के प्रश्न के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था अभी जिला स्तर पर ही है, अनुमण्डल स्तर पर अभी कोई नीति या योजना नहीं है सरकार की इसे बनाने की ।

श्री विद्या सागर केशरी : तो इसका क्या मापदंड है स्थापित करने का ? पोस्टमार्टम हाऊस बनाने का क्या मापदण्ड है माननीय महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ । आखिर कोई तो मापदण्ड होगा इसका ? माननीय मंत्री महोदय जी बताये कि पोस्टमार्टम हाऊस बनाने का क्या मापदण्ड है ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, यह नीतिगत मामला है, अभी तक की व्यवस्था के हिसाब से जिला में एक पोस्टमार्टम हाऊस, जिला मुख्यालय जो है वहां पर स्थापित किया गया है। माननीय सदस्य की चिन्ता को विभाग ग्रहण करती है और उस पर आगे भविष्य में विचारा किया जायेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अनुमण्डल स्तर पर, महोदय अनुमण्डल स्तर पर बनाया जाय चूंकि एस.एस.बी. का बोर्डर एरिया है, एस.एस.बी. का सात हजार वहां जवान रहते हैं और पूरे नेपाल के क्षेत्र से भी बहुत सारे मरीज आतें है जिनको बहुत सारी प्रोब्लम होती हैं, मैं माननीय मंत्री...

अध्यक्ष : नेपाल से जो आते हैं उनका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है ?

श्री विद्या सागर केशरी : जो मरेगा तो उसका पोॅस्टमार्टम तो होना ही है ..

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं पोस्टमार्टम के बारे में, आप कहते हैं कि नेपाल से भी मरीज आते हैं, जो मरीज आये अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होता है ?

श्री विद्या सागर केशरी : नहीं, मरीज नहीं जो शव है, उसका पोस्टमार्टम होता है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1409(श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक हैं ।

मधुबनी जिला के पण्डौल एवं रहिका प्रखण्ड में कमशः 33, 25 गांवों का विद्युतीकरण करना था, जिनमें 29, 25 गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया हैं, पण्डौल प्रखण्ड के शेष 04 गांवों का विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना के 12 वीं योजना के तहत प्रगति पर हैं, कार्य पूर्ण का लक्ष्य जून, 2017 है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, यह पहले 2016 तक करना था और अब जून,2017 किया गया है, पहले 66 गांव चिन्हित किये गये थे, 66 गांव का टोला था, अब कितने बच गये हैं और कब तक सब तरह से बनाया जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा है कि महोदय चार गांव बच गये हैं, जिसको जून, 2017 तक कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1410(श्रीमती भागीरथी देवी)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड रामनगर में नियमित दो चिकित्सक, संविदा पर एक चिकित्सक एवं एक दंत चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनसे रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप शेरवादोन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय कार्य कराया जाता हैं ।

2- स्वीकारात्मक नहीं है । प्रसव जननी सुरक्षा का लाभ पदस्थापित चिकित्सक के द्वारा दिया जा रहा हैं ।

3- सभी सिविल सर्जनों को सभी रिक्त पदों पर संविदा के आधार नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी बता रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट एकदम गलत हैं, रामनगर क्षेत्र दोन हैं, जंगल है, थारूअट इलाका हैं महोदय, वहां पर आज तक कोई महिला डाक्टर नहीं है, उसके लिए हम पहले से, पांच साल पहले से मैं हल्ला कर रही हूॅ लेकिन आज तक कोई महिला डाक्टर या कोई भी पदाधिकारी, समूचा लोग रहते हैं बेतिया में, वहां जाकर हाजरी बनाते हैं, यह पता कर लिया जाय महोदय, यह एकदम सत्य बात हैं, बेतिया में सारा लोग रहते हैं, हाजरी बनाते हैं वहां, खाली सब सी.एस. से मिलकर, सी.एस. के द्वारा मिलकर ये सभी काम होता है.....

अध्यक्ष : आप जो चाहती हैं, वह प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्रीमती भागीरथी देवी : वहां डाक्टर भेज दिया जाय । वहां डाक्टर रहे । वहां रहने की व्यवस्था सब है महोदय, वहां डाक्टर रहे महोदय ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री :महोदय, नियमित चिकित्सकों में डाक्टर डा0 चन्द्रभूषण, प्रभारी चिकित्सक वहां पदास्थपित हैं जो 19 सितम्बर, 2015 से कार्यरत हैं, डा0 दयाशंकर आर्या, चिकित्सा पदाधिकारी 24 मई, 2016 से कार्यरत हैं, उसी तरह से संविदा चिकित्सकों में डा0 पाण्डेय शुशांत कुमार 30 जुलाई,2013 से कार्यरत हैं, डा0 अनुपमा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकरी हैं, जो 2 मार्च, 2007 से कार्यरत हैं और यह बात सही है कि महिला चिकित्सकों की कमी है और उनकी बहाली की प्रक्रिया विगत दिनों में शुरू हुई थी, काफी बड़ी संख्या में ज्वायन भी किये....

अध्यक्ष : आपने जो बताया डा0 अनुपमा कुमारी के बारे में, वे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं? अभी आपने 2 मार्च, 2007 से बताया कि डा. अनुपमा का हुआ है, वह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं क्या ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : इसकी जानकारी लूंगा । मैं बताना चाह रहा हूॅ कि महिला चिकित्सक भी हैं लेकिन ओभरऑल पूरे बिहार में महिला चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है, और जो बचे हुये पद हैं उस पर जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं तो उनको निश्चित रूप से संविदा के आधार उनकी नियुक्ति की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक । तारांकित प्रश्न संख्या-1411 ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, बात गंभीर है महोदय, माननीय विधायिका घर-घर घूमने वाली हैं, गांव-गांव घूमने वाली हैं, जनता से सीधा सम्पर्क हैं, थारूअट क्षेत्र का जिक्र कर रहीं हैं, उस क्षेत्र में डाक्टर नहीं है, ये कह रहीं है, लोगों ने शिकायत किया हैं और मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं चार डाक्टर का हवाला दे रहे हैं कि वहां पदस्थापित हैं, तब तो यह और भी गंभीर विषय है । रेकार्ड में वहां पदस्थापित होना एक अलग विषय है महोदय लेकिन सरजमीन पर डाक्टर को उपस्थित होना

एक अलग विषय है, सच्चाई यह दिख रहा हैं माननीय सदस्या के प्रश्न के आलोक में कि वहां डाक्टर जाते नहीं हैं महोदय, सिविल सर्जन के कार्यालय में उस अस्पताल में पदस्थापित हो सकते हैं कागज में और इनको जो रिपोर्ट होगी विभाग से उस कागज के आधार पर आई होगी, सर जमीन पर डाक्टर नहीं हैं लोगों को कठिनाई हो रही हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका हैं, उन गरीबों के इलाज का क्या होगा ? इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूॅ कि क्या उच्चस्तरीय जांच करा कर के वहां डाक्टर सुनिश्चित कराने का काम करेंगे ?

अध्यक्ष : नहीं, इसकी तो जांच करा ही लीजिये कि डाक्टर जाते हैं कि नहीं ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : जांच करा दी जायेगी ।

टर्न-3/ज्योति

25-03-2017

तारांकित प्रश्न संख्या 1411 (श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुवनी एवं पिपरासी प्रखण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डायबिटीज एवं खून की जॉच की सुविधा उपलब्ध है, अन्य जॉच की सुविधा नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में करायी जाती है । उप स्वास्थ्य केन्द्रो में पैथोलॉजिकल जॉच की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूॅ कि अभी जो इन्होंने जवाब दिया कि अन्य जो जॉच की सुविधााएं हैं, अन्य जगह से करायी जाती है तो बताना चाहेंगे कि कहॉ से करायी जाती है, किस पैथोलॉजी से हमारे बिहार के किस अस्पताल से करायी जाती है ?

अध्यक्ष : बताये थे मंत्री जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : मरीजों को पैथोलॉजिकल जॉच की सुविधा नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मधुबनी एवं पिपरासी में उपलब्ध है । सेमी औटो एनालाईजर के द्वारा दी जा रही है ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : ऐसा नहीं होता है । जो भी इनको जानकारी दी गयी है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूॅंगा कि जो भी इनको जानकारी दी गयी है, वो गलत जानकारी दी गयी है । चूॅंकि हमारा जो क्षेत्र है, वह बौर्डर से सटा हुआ है, उसकी जो भी जॉच की प्रक्रिया होती है, वहॉ जो भी डौक्टर बैठे रहते हैं ।..

अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं उस संबंध में पूरक पूछ लीजिये ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : जॉंच उत्तर प्रदेश में करायी जाती है । हम इनसे कहना चाहेंगे कि जो भी जॉंच की सुविधा हो हमारे बिहार में मधुबनी और पिपरासी में करायी जाय ।

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1412 (श्री मुंद्रिका प्रसाद राय)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । भवन निर्माण विभाग को मामले की जॉंच करते हुए शीघ्र भवन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है भवन उपलब्ध होने पर उसे शुरु करा दिया जायेगा ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : कबतक ?

अध्यक्ष : भवन निर्माण विभाग इस भवन को बना रहा है । मंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस विभाग को कहा गया है ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : काफी समय लग चुका है तो अब कबतक ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : जल्द ही करा दिया जायेगा , माननीय सदस्य ने बताया है कि 20 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया है, चिन्ता का विषय है इसलिए जल्द से जल्द इसे कराने का प्रयास किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1413 (श्रीमती भागीरथी देवी)

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने अपने पत्रांक 25 दिनॉंक 1-3-17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है बाल्मिकीनगर व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणी में सोमेश्वर पहाड़ की ऊंचाई लगभग 2884 फीट है जिसका अपना धार्मिक महत्व है परन्तु उसके ऐतिहासिक/ पुरातात्विक महत्व के संबंध में कोई अभिलेख या जानकारी नहीं है । वन कक्ष संख्या आर- 50, अधिसूचना संख्या एसओ-136 दिनॉंक 06-03-90 द्वारा बाल्मिकी वन्य प्राणी आश्रयणी के रुप में अधिसूचित है, यह स्थान/ वन कक्ष कोर क्रीटिकल टाईगर हैबिटैट में है । पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं दिया जाता है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बोल रही हैं कि वहॉं पर जो सोमेश्वर पहाड़ी है वहॉं केवल थारु लोगों का ही मेला लगता है । वह इतना ऊंचा पहाड़ है और वह तीन हजार फीट ऊंचा पहाड़ है जब कि हमलोग माननीय सदस्य होकर मीठा और चना अपना आदमी रखकर चलवाते हैं और जाने के लिए रास्ता भी अच्छा नहीं है इसलिए उसको पर्यटक स्थल में घोषित किया जाय, माननीय मंत्री जी उसको पर्यटक स्थल घोषित करें ।

अध्यक्ष : अलग से लिखकर दे दीजिये ।

श्रीमती भागीरथी देवी : उसको पर्यटक स्थल बनवा दिया जाय ।

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष : एक और पूरक सुन लीजिये फिर एक साथ जवाब दे दीजियेगा ।

श्री नंदकिशोर यादव : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है और माननीय मंत्री महोदया ने स्वीकार किया है कि यह 2800 ऊंचाई पर है और बड़े पैमाने पर थारु समाज के लोग वहॉ बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं । महोदय, पर्यटन विभाग ने पहले भी निर्णय लिया है कि जिन ऐसे स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं तो उनकी सुविधा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था पर्यटन विभाग करता रहा है और पहले का इतिहास रहा है विगत जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो बहुत सारे पर्यटन स्थलों पर पर्यटको की सुविधा के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण का काम, पीने के पानी की सुविधा के लिए निर्माण का काम, शौचालय आदि, माने कई प्रकार के निर्माण के काम किए गए थे ताकि पर्यटकों को सुविधा हो सके, पर्यटक स्थल घोषित करे, न करे यह अलग विषय हो सकता है लेकिन सामान्य रुप से जो पर्यटन विभाग का जो पहले का निर्णय है कि जहॉ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए निर्माण का काम करेंगे तो क्या यहां भी जहॉ आदिवासी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए वहॉ कुछ सामुदायिक भवन या उनके पीने के पानी की व्यवस्था और कुछ व्यवस्था या सुविधा देने का विचार सरकार रखती है ?

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग में पंचवर्षीय रोड मैप बन रहा है जिसके तहत जो भी प्राथमिक तौर पर मंदिर है, मस्जिद हैं, जो भी हैं उसको पहले प्राथमिकता के तौर पर बनाया जायेगा चाहें वहॉ जो भी काम है किए जायेंगे । अभी रोड मैप बनकर आने वाला है जैसे ही आयेगा प्राथमिकता के तौर पर जो भी पौराणिक धर्मस्थल है, मंदिर -मस्जिद उसपर काम किया जायेगा ।

श्री नंदकिशोर यादव : महोदय, ये इस प्रश्न को विस्तारित कर रही है । फिर कई सवाल और खड़े होंगे मैं जो पर्टिकुलर इस विषय के बारे में जो प्रश्न है ।

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : ठीक है, इनका देखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1414 (श्रीमती रेखा देवी)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3- धनरुआ पावर सब स्टेशन की घेराबंदी सही अवस्था में है। सब-स्टेशन से बाहर खाली पड़ी विभागीय जमीन की घेराबंदी का कार्य प्रक्रियाधीन है अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर इसको करा दिया जायेगा ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी क्वेश्चन की थी, मंत्री जी ये बता दें कि कबतक कार्रवाई होगी और घेराबंदी की प्रक्रिया शुरु होगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रील से जो प्रारम्भ होगा उसमें करवा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1415 (श्री महबूब आलम)

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु एक रोड मैप का निर्माण किया जा रहा है । तदोपरान्त चरणबद्ध तरीके से निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, वह सीमांचल क्षेत्र का बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहॉं गए थे और वहॉं की जनता को काफी आशा है कि मुख्यमंत्री जी गए थे तो लाखों लोग आते हैं तो पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए निश्चित बात होनी चाहिए ?

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : ठीक है, दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1416 (श्री सुधाांशु शेखर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम विशनपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो स्वीकृत और संचालित है ।

2- राशि उपलब्ध होने पर भवन की मरम्मती एवं चहारदिवारी के निर्माण का काम कराया जायेगा ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय । भवन नहीं रहने के कारण वहॉं बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से इलाज हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1417 (श्रीमती समता देवी)

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 1418 (श्री सदानंद सिंह)

श्री सदानंद सिंह : अध्धक्ष महोदय, उत्तर दिया हुआ है । उत्तर दी हैं माननीय मंत्री जी कि बिहार के विभिन्न जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों के पर्यटन के दृष्टिकोण से गांधी

सर्किट रुप में विकसित करने का निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया है । हम तो पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछे हैं कि हम यह जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या जो ये स्थल है जहॉं 11-12 फरवरी 1948 को कोशी और गंगा के संगम पर महात्मा गांधी की अस्थि को विसर्जित किया गया था उस स्थल को आपने गांधी सर्किट में शामिल किया है कि नहीं ?

श्रीमती अनीता देवी, मंत्री : दिखवा लेते हैं इनको ।

श्री सदानंद सिंह : क्या देखवायेंगी ?

अध्यक्ष : संज्ञान में इसको ले लीजिये ।

टर्न-4/25.3.2017/बिपिन

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, देखिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है । संपूर्ण बिहार में और पूरे देश के पैमाने पर ग्यारह स्थलों में गांधी की अस्थि विसर्जित की गई थी और बिहार का यह सौभाग्य है कि कोसी और गंगा के संगम पर कुरसेला में यह अस्थि विसर्जित की गई थी और इस स्थल को नहीं इसमें शामिल किया जाना, फिर शताब्दी समारोह मना रहे हैं गांधी की, उसमें इसको तो महत्व देने की आवश्यकता है । इस संबंध में न बताइए ! क्या देखवा लेंगी आप ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो पुराने सदस्य हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं । वो सूचना दे रहे हैं कि प्रवाहित किया गया था उनके अस्थि कलश को, तो आपने कहा है कि गांधी सर्किट में उन स्थानों को जोड़ रहे हैं, गांधी से जुड़े स्थल को ।

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री: ठीक है, इसको जुड़वा देंगे ।

अध्यक्ष : अब स्पष्ट आ गया कि इसको जुड़वा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1419 (श्री फैसल रहमान)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल ढाका में 6 चिकित्सक कार्यरत हैं एवं घोड़ासाहन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर 3 चिकित्सक कार्यरत हैं । सभी सिविल सर्जनों को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1420 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री: महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

विभागीय पत्रांक 531 दिनांक 15.3.2010 के द्वारा 14,19,480/-रूपए मात्र की योजना स्वीकृत कर क्रियान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को प्रदान किया गया था । जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने पत्रांक 74 दिनांक

7.3.2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि 13,38,600/-रूपए से चाहारदीवारी एवं मुख्य द्वार का निर्माण किया गया है ।

2. अस्वीकारात्मक है । तत्काल उक्त परिसर में कोई अन्य कार्य करना विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, इसमें इतना, थावे के बाद से जो महत्व का यह मंदिर है और इसमें काफी लोग आते हैं । पैसा का दुरूपयोग हुआ है, आवंटन का । जांच करा दिया जाए । और उसी तरह शेड है, पैसा दिया गया और उसी तरह शेड टूटा हुआ पड़ा है । मेरा यही आग्रह है कि किसी भी वरीय पदाधिकारी से या किसी भी स्तर से इसका पैसा जो गया है आवंटन, उसका जांच करवा दें । यही मेरा आग्रह है ।

श्रीमती अनीता देवी: ठीक है, इसकी जांच करवा लेते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 1421 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिले के कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है । तीन माह में सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने समय तो निर्धारित कर दिया कि तीन महीने में मूलभूत सुविधा, लेकिन उस मूलभूत सुविधा में क्या-क्या ये उपलब्ध करा देंगे ?

अध्यक्ष : आपने पूछा है क्या-क्या सोच कर ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: हमने पूछा है महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इसको उन्नत कर दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए मैंने पूछा है । तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जो मानक है, उस मानक के अनुरूप ..

अध्यक्ष : मतलब, आप चाहते हैं कि मानक के अनुरूप सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो जाए, यही न ! तो वह सरकार दिखवा ले ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: जी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: जवाब दिलवा दीजिए महोदय ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: मानक के अनुरूप होगा, अतिरिक्त नहीं होगा, कम नहीं होगा, मानक के अनुरूप होगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 1422 (श्री मिथिलेश तिवारी)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

श्रवण कुमार साह, पिता-स्व0 शिवपूजन साह, ग्राम-देवकुली, थाना-महम्मदपुर, जिला-गोपालगंज बिंदिया टोली टेली लिंक कंपनी के संवेदक के अधीन 7.2.2016 को बिना शट डाउन लिए बिजली का कार्य कर रहे थे । कार्य के कम में 11000 के0भी0ए0 क्षमता के तार से इनके साथ संपर्क हो जाने के कारण श्री शाह को स्पर्शाघात हुआ । इसमें कंपनी का दोष नहीं है । बिंदिया टोली लिंक कंपनी द्वारा उन्हें एक लाख रूपए का मुआवजा अदा किया गया है । साथ ही कंपनी द्वारा इन्हें प्रतिमाह 8000/-मासिक का भुगतान भी किया जा रहा है । कंपनी में निहित प्रावधान, यथा, पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना के पत्रांक 1953 दिनांक 2.8.2012 के अनुसरण में विद्युत स्पर्शाघात से मानव के अपंग होने की स्थिति में अपंगता का मानक प्रतिशत 50 से कम होने पर मुआवजा 25 हजार, पचास से अधिक होने पर अधिकतम मुआवजा एक लाख राशि का भुगतान किया जाता है । चूंकि श्रवण कुमार बिंदिया टेली कंपनी के लिए लिंक कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे, उन्हें उचित मुआवजा उक्त कंपनी द्वारा दे दिया गया है । इसलिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के स्तर से श्री शाह को अधिक मुआवजा राशि नहीं दिया जाना है ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बिहार की सरकार बिहार के लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ जनता को ही करेंट मार रही है, जो करेंट कल इन्होंने मारा है और आज माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दिया है इस सदन में, यह मामला मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और अध्यक्ष महोदय, बिना पावर शट किए हुए कोई व्यक्ति अपने जान की बाजी लगाकर काम करने जाएगा क्या ? माननीय मंत्री जी इसकी जांच की घोषणा करें सदन में कि आखिर यह किस व्यक्ति ने जब वहां काम चल रहा था तो उसमें बिजली किस व्यक्ति ने दिया, यह किसका दोष है, एक गरीब व्यक्ति, पूरा परिवार उसी के उपर डिपेंड है और एक गरीब व्यक्ति का हाथ कट गया और माननीय मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि गलती उसकी है कि वह बिना शट डाउन कराए काम कर रहा था । लेबर काम कर रहा था, कंपनी करा रही थी काम तो गलती लेबर का हो गया क्या ? इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से सदन में जानना चाहूंगा कि पूरे राज्य में ऐसी परिस्थिति है महोदय । यह मेरे यहां दूसरी घटना है । माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहेंगे कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जिस ..

अध्यक्ष : तिवारी जी, इसके लिए तो एफ.आई.आर. दर्ज है । एफ.आई.आर. के आलोक में जाो पुलिस अनुसंधान करेगी, उसमें सारे तथ्य उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारीः लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक साल से वह एफ.आई.आर. ज्यों-का-त्यों पड़ा हुआ है और जब मैंने प्रश्न ..

अध्यक्ष : आप एफ.आई.आर. की जांच या उसका इन्वेस्टिगेशन जो है उसे त्वरित गति से कराने का अनुरोध करिए न !

श्री मिथिलेश तिवारी: ठीक है अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक विषय और है अध्यक्ष महोदय कि जब यह प्रश्न मैंने किया है तो जो लोग उसके संवेदक हैं, वो उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि आपने प्रश्न क्यों करा दिया ? तो ऐसी परिस्थिति में यह मामला थोड़ा और भी विस्तृत हो गया । यह गरीब आदमी है अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हम माननीय मंत्री जी कोई ठोस घोषणा करें और 8000 रूपया की जो राशि उसको मिल रही है, यह कब से मिल रही है और कितना दिन मिलेगी, यह तो मंत्री जी बताएं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वह इम्प्लाई प्राइवेट कंपनी का था । जो रिपोर्ट आया है कि आठ हजार रूपए प्रतिमाह और एक लाख उनको मुआवजा दे दिया गया है । जो नियम है कि फिफ्टी परसेंट से नीचे अगर इंजूरी होगा तो उसको पच्चीस हजार मिलेगा, उससे अधिक होने पर उसको एक लाख मिलेगा । वह भी दे दिया गया । माननीय सदस्य अगर कहते हैं कि नहीं मिला है तो निश्चित तौर से इसको हम देखवा लेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, एक मेरा और पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति का इलाज आज भी चल रहा है और मुआवजा उसको नहीं दिया है कंपनी ने । यहां पर पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है ....

अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं । आप कह रहे हैं कि नहीं दिया है, तो उसकी जांच करा देंगे।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताए, कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी कर रही है । काम तो सरकार का कर रही है । तो माननीय मंत्री जी उस प्राइवेट कंपनी को निदेशित करें ।

अध्यक्ष : तिवारी जी, लेकिन सबके नियम अलग-अलग होते हैं न ! कोई सरकारी कर्मचारी होता है, कोई प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी होता है । तो सबके लिए अलग-अलग नियम है न !

श्री मिथिलेश तिवारी: लेकिन अध्यक्ष महोदय, मूल विषय यह है कि बिजली विभाग के अधिकारियों.

अध्यक्ष : नहीं, सरकार ने जो जवाब दिया है, आप कह रहे हैं कि नहीं मिला है तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच करा देंगे तो अब आगे तो कोई बात बचती नहीं है ।

श्री मिथिलश तिवारी: लेकिन अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0 1423, श्री मो0 नवाज आलम ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0 1423 (श्री मो0 नवाज आलम)</u>

श्री चन्द्रशेखर,मंत्री आपदा: महोदय, प्रश्नगत् पंचायत में 4644 परिवारों को राहत राशि दे दी गई है और बाकी आवंटन के आलोक में 9869.89 लाख रूपए दिए गए हैं जिला को । आगे राहत राशि बांटने की कार्रवाई जारी रहेगी ।

श्री नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन आंकड़ों को पेश किया है, मेरी समझ से पूरी तरह जो है, इसी तरह से भेग है । हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी पंचायत में, अभी हमलोग कई गांव का दौरा किए और वहां के तमाम ग्रामीणों ने इस बात को रखने का काम किया कि कहीं भी लाभुकों को जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए था, नहीं मिला है । सदन के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप एक कमिटी गठित कर दें और उसकी जांच करा लिया जाए । अगर सही पाया जाएगा तो माननीय मंत्री जी उन दोषी जो पदाधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी ।

टर्न: 05/कृष्ण/25.03.2017

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन के इलाके का मामला है । वह भ्रमण में पाये हैं कि नहीं मिला है तो इसकी जांच जरूर करा दीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : जांच जरूर करा देंगे । माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप जिला के अधिकारी से कहें या विभाग से कहें, मैं बता देता हूं कि आवंटन आप के जिला को लगभग शत-प्रतिशत दे दी गयी है । राहत राशि के वितरण काम चल रहा है । जिला से प्रतिवेदन आया है, उसमें 4694 है । आप चाहेंगे तो विभागीय स्तर से जांच करा देंगे ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर सदन की कमिटी नहीं बनती है तो कम से कम कमिशनर लेवेल पर इसकी जांच करा दी जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सरोज यादव : महोदय, माननीय सदस्य यह सही कह रहे हैं । अंचलाधिकारी चेहरा चिन्हित कर के मुआवजा देने का काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय । खवासपुर मेरा एक पंचायत है ।

श्री चन्द्र शेखर ,मंत्री :आदेश हो गया है, इस की जांच करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1424 (डा0 मेवालाल चौधरी)

अध्यक्ष : मानानीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1425 (श्री संजय सरावगी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, क. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पी0एम0सी0 में चिकित्सकों के स्वीकृत 574 पदों में से 298 पदों पर चिकित्सक शिक्षक कार्यरत हैं । दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय में चिकित्सकों के स्वीकृत 206 पदों में से 69 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं । इन्दिरा गांधी हृदयरोग संस्थान,पी0एम0सी0एच0,पटना में चिकित्सकों के स्वीकृत 96 पदों में से 58 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं । राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों के 1,171 सहायक प्रध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है । चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी प्राचार्य, अधीक्षक एवं निदेशक को संविदा के आधार पर वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का निदेश दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, डी0एम0सी0एच0 में 206 पदों के विरूद्ध 69 चिकित्सक कार्यरत हैं और पी0एम0सी0एच0 में 574 के विरूद्ध 295 और आई0जी0आइ0एम0एस0 में 96 के विरूद्ध 58, इस प्रकार बड़ी संख्या में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और चार वर्षों से खाली हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में जब-जब हमलोग प्रश्न पूछते थे तो विभाग का जवाब यह आता था कि बी0पी0एस0सी0 से 2400 कुछ चिकित्सकों की बहाली हो रही है, जैसे ही वह बहाली होगी, इन सभी रिक्त पदों को भर दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो तीन साल पहले बी0पी0एस0सी0 से जो चिकित्सकों की बहाली हुई थी क्या अभी तक वह पूर्ण नहीं हुई है क्या ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, बी0पी0एस0सी0 द्वारा दिये गये चिकित्सकों की बहाली हुई है, बहुत बड़ी संख्या में चूंकि चिकित्सकों की कमी है, बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक जहां अपनी पदस्थापना चाहते थे, यह जरूरी नहीं था कि सरकार उस के मनोनुकूल उन्हें पदस्थापित करे तो उस आधार पर बहुत सारे चिकित्सकों ने जिन को नियुक्ति पत्र दिया गया, चिकित्सकों ने ज्वाईन ही नहीं किया । जिन्होंने ज्वाईन नहीं किया, वैसे पद अभी भी रिक्त हैं । तो अभी जो बी0पी0एस0सी0 को अधियाचना दी गयी है, उसकी प्रक्रिया पूरी होने तक सभी चिकित्सा महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, जो अधीक्षक हैं तथा जो निदेशक हैं, इन सबों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो डाक्टर चाहते हैं, उनकी नियुक्ति वहां संविदा के आधार पर कर ली जाय, जब तक की परमानेन्ट नियुक्ति न हो जाय । 3 हजार विशेषज्ञ चिकित्सकों के विरूद्ध 600 की अनुशंसा प्राप्त हुई थी, 3 हजार विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग की गयी थी, बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से लेकिन मात्र 600 की अनुशंसा प्राप्त हुई थी । महोदय,

तात्कालिक व्यवस्था के लिये सरकार बिल्कुल गंभीर है और बिल्कुल स्वतंत्रता दी गयी है, सी0एम0ओ0 स्तर पर जिला में जहां चिकित्सकों की कमी है, वहां संविदा पर बहाली का निर्देश दिया गया है और चिकित्सा महाविद्यालयों में भी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, तीन महत्वपूर्ण अस्पताल हैं राज्य के, जिन पर प्रश्न किया गया है और इसके पहले भी यही प्रश्न किया गया था ।

अध्यक्ष : अभी पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : वही मैं पूरक ही पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहाली हुई लेकिन चिकित्सक मनोनुकूल पदस्थापन की जगह चाहते थे । महोदय, विधान सभा में कहा हुआ मामला है और बड़ी संख्या में बहाली हुई, माननीय मंत्री जी उलटा कर के जांच करा लें, दो साल, तीन साल जितने पद रिक्त थे तीनों अस्पतालों में, वहां आज भी उतने ही पद रिक्त हैं । इसका मतलब विधान सभा में कोई मामला आता है, इतना गंभीर मामला आता है, सरकार उस पर गंभीर नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं यह पूरक पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : आप एक चीज सुन लीजिये । सरकार ने बता दिया है । सरकार ने जो कहा था उस के बाद तो आगे की कारवाई हुई कि बी0पी0एस0सी0 में रीक्वीजीशन भेजा गया है, बहाली की प्रक्रिया हो रही है । ऐसा नहीं कि बहाली की प्रक्रिया वहीं रह गयी । बहाली की प्रक्रिया हुई । उस में से बहुत सारे चिकित्सकों ने योगदान नहीं दिया । सरकार ने उस की भी वैकल्पिक व्यवस्था की है, सारे सिविल सर्जन से लेकर मेडिकल कॉलेजों के जो प्रशासन हैं, उन को स्थानीय स्तर पर नियुक्ति की छूट भी दे दी है, अब आप क्या चाहते हैं, वह बताईये ।

श्री संजय सरावगी : हम यह चाहते हैं महोदय कि सरकार कोई समय-सीमा तय कर दे क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं । जरा अस्पतालों में चिकित्सक चले जायं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवा दिया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, बिल्कुल विस्तारपूर्वक सारी बातों को बताया गया कि फिलवख्त ऐरेंजमेंट के तहत संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया ।

अध्यक्ष : उस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करायें ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है । इस प्रक्रिया को और तेज किया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 1426(श्री अजीत शर्मा)</u>

श्री चन्द्र शेखर,मंत्री : महोदय, यह प्रश्नगत पुनर्वास की प्रक्रिया जो माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में किया है, यह सचीदानन्द नगर भूमि वाद संख्या- 6/1969-70 का यह मामला है, जिस के तहत 20 एकड़ जो जिला से प्राप्त प्रतिवेदन है, 20 एकड़ 2 डिसमिल जमीन पर्चाधारियों के बीच बांटी गयी है और 366 पर्चाधारियों को दे दी गयी है, बाकी जिन का डिमांड है, जो झौआ कोठी लोक निर्माण विभाग के मकान में बसा हुआ है कच्चा, पक्का मकान बना कर के, उन को पर्चा देने की कार्रवाई जारी है । मामला 1969-70 का है । हमारी सरकार न तो झांसा बेचती है और न बहकाती है । हमारी सरकार मुकम्मल काम करती है । इसलिए जो प्रतिवेदन आया है, उस पर विश्वास करें पर्चाधारियों को पर्चा दी जायेगी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये सच्चीदानन्द नगर की बात कर रहे हैं और झौआ कोठी की बात कर रहे हैं । मैं इन को बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग रेलवे लाईन के किनारे और सड़क के किनारे रहते हैं, जिन को प्रशासन जा कर हटाती है और फिर दो-चार दिनों के बाद आ कर बस जाती है । आप उन को जांच करा कर देखिये, जो मैं कह रहा हूं । मैं उसी इलाके से आता हूं, आप का रिपोर्ट बिल्कुल आधा है और आधा छूटा हुआ है । मंत्री जी उस की जांच करवा कर इस को कराने का काम करें ।

अध्यक्ष : इसको दिखवा लीजिये ।

श्री चंद्र शेखर, मंत्री : जी, इसको दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1427 (श्री बशिष्ठ सिंह)

श्रीमती अनिता देवी,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । करगहर पोखरा का सौन्दर्यीकरण की कोई योजना पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब स्पष्ट है कि विचाराधीन नहीं है तो अब क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वहां बहुत पुराना मंदिर है, पोखरा है, नहर का तट है और बहुत पहले जब हम बच्चा थे तो वहां मेला देखने जाते थे, आज हम चाहते हैं सरकार से कि उस को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय । माननीया मंत्री महोदया हमारे जिले से ही हैं । इसलिए अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगी तो उन को भी पूण्य मिलेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि उस को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय ।

अध्यक्ष : दोनों एक जिला के होते हुये आप इन से सदन में क्यों अनुरोध कर रहे हैं ?

टर्न-6/राजेश/25.3.17

तारांकित प्रश्न संख्या: 1428 (श्री राघव शरण पाण्डेय)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । निगम को भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार प्रश्न देने के बाद 9 मार्च, 2017 को बिहार मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के द्वारा टेंडर नोटिस इशू हुआ है..............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: तब तो आपका प्रश्न प्रभावकारी रहा ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: प्रभावकारी तो रहा लेकिन क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब पैसा था, जब सैंक्सन ऑर्डर 9 अप्रैल, 2016 को इशू हो गया था, तो 11 महीने का विलंब इसमें क्यों कराया गया, इसका क्या औचित्य है ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, इसको मैं दिखवा लेता हूँ ।

अध्यक्ष: ठीक ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: महोदय, मेरा दूसरा पूरक यह है कि इस स्वास्थ्य केन्द्र को एडिशनल पी0एच0सी0 में कब से कार्यान्वित किया जायेगा, न तो इसमें डाक्टर हैं और न ही इसमें दवा है, भवन निर्माण के लिए पुराना भवन तो है, नये भवन के लिए निविदा इशू की गयी है लेकिन इसको चालू ठीक ढंग से कब तक कराया जायेगा ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, भवन निर्माण के बाद सभी व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1429 (श्रीमती प्रेमा चौधरी)

(माननीय प्रश्नकर्ता सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 1430 (श्री अरुण कुमार सिन्हा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या-86.18 लाख है । साउथ बिहार पावर डिसट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 31.94 लाख एवं नॉर्थ बिहार पावर डिसट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 54.24 लाख, मीटर रहित उपभोक्ताओं की कुल संख्या-9.52 लाख है । साउथ बिहार पावर डिसट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 3.17 लाख एवं नॉर्थ बिहार पावर डिसट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 6.35 लाख ।

खण्ड 2: वर्तमान में मीटर अधिष्ठापित कर उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है । पूर्व में दिए गए मीटर रहित उपभोक्ताओं का मीटर अधिष्ठापित किया जा रहा है । मीटर रहित उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ में निहित प्रावधानानुसार किया जाता है ।

खण्ड 3: मीटर रहित उपभोक्ताओं के परिसर में कंपनी द्वारा शत-प्रतिशत मीटर लगाने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2017-18 तक निर्धारित किया गया है ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी यह स्वीकार किया की मीटर बड़ी संख्या में नहीं लगा है, मेरा एक तरफ यह कहना है कि सरकार को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ ये टेरिफ में 55 प्रतिशत दर बढ़ाकर, तो क्या इसको जो समय सीमा दिया गया है, तो उसको और जल्दी एवं जितनी जल्दी करने का और यह जो दर बढ़ा हुआ है, इसको इसमें कंपेनसेट करने का विचार रखती है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, 2017-18 वित्तीय वर्ष निर्धारित किया गया है । कोशिश की जायगी, यह तो हमलोगों के फायदे में है कि और द्रुत गति से मीटर को लगाने का अभियान चलाया जाय ताकि यह काम जल्द पूरा कर लिया जाय ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा: महोदय, अगर समय सीमा तय हो जाता ।

अध्यक्ष: अगला वित्तीय वर्ष बता दिये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1431 (श्री सुनील कुमार)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । लगमा पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र, लगमा का भवन निर्मित है परन्तु भवन निर्माण विभाग द्वारा इसे हस्तगत नहीं कराया गया है । भवन निर्माण विभाग को शीघ्र हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री सुनील कुमार: महोदय, पिछले 10 वर्षों से भवन बनकर तैयार है और पिछले 10 वर्षों से यह क्यों नहीं हस्तान्तरित किया गया और वहाँ का स्वास्थ्य उप-केन्द्र बगल के एक मकान में चल रहा है, अब तो उस भवन की हालत भी खराब हो रही है और अभी तक उसको हस्तगत नहीं किया गया है, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, भवन को पूर्ण रुप से फिनिसिंग करके हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया है, तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ कि अगर इसमें कोई देरी हुई है, तो क्या तथ्य है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1432 (श्री विजय कुमार सिन्हा)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 3: वस्तुस्थिति यह है कि इन आयुर्वेद महाविद्यालयों में भारत सरकार द्वारा नामांकन पर रोक लगायी गई थी । यह रोक पी0जी0 डिग्री धारक शिक्षकों की कमी, पद सृजन का अभाव एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण

लगायी गई थी । वर्ष 2007 में सरकार के निर्णय के आलोक में इन महाविद्यालयों को बंद किया गया था ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इस विषय पर शीघ्र ही समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रविन्द्र यादवः महोदय, पटना आयुर्वेद कॉलेज जो चल रहा है सर, उसमें चिकित्सक हैं लेकिन पारा मेडिकल स्टाफ के नहीं रहने के कारण कार्य में बहुत बाधा हो रही है, चूंकि पटना कैपिटल टाउन है, वहॉ हमलोग भी जाते हैं, तो सरकार वहॉ ड्रेसर की पोस्टिंग करना चाहती है और अगर करना चाहती है तो कब तक ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः महोदय, महाविद्यालय प्रशासन से वहॉ की जो अद्यतन स्थिति है, उसको मॅगाकर सरकार कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्षः ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 1433 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । इस केन्द्र का निर्माण जिला स्तर से कराए जाने की सूचना है । जिला पदाधिकारी को मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ताः कब । माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के शिकारगंज स्थित स्वास्थ्य केन्द्र के भवन मरम्मती में घोर अनियमितता बरती गयी है । यदि हॉ है तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ....

(व्यवधान)

अध्यक्षः यह तो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसका तो जवाब दे दिये कि डी0एम0 को कहे हुए हैं।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ताः महोदय, कब तक कमिटी बना करके इसकी जांच करा देंगे ।

अध्यक्षः डी0एम0 को कहे हैं जांच कराने के लिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ताः कब तक सर इसको ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः जल्द से जल्द ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ताः जल्द का मतलब कितना ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 1434 (श्री प्रकाश वीर)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: राज्य के किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है ।

नवादा जिलान्तर्गत रजौली अनुमंडल में संप्रति न्यायालय स्थापना हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है । आधारभूत संरचना यथा-भूमि, भवन आदि उपलब्ध होने पर माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया जाएगा ।

आधारभूत संरचना उपलब्ध होने/पूर्ण होने एवं पदों के सृजनोपरान्त ही माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से रजौली अनुमंडल में न्यायालय स्थापित किया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1435 (श्री अरुण कुमार)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । दवा उपलब्ध है । दो चिकित्सक कार्यरत है । सभी सिविल सर्जनों को सभी रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1436 (श्रीमती अरुणा देवी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है ।

खण्ड 3: जमीन उपलब्ध होने पर राशि के आधार पर भवन निर्माण की जाएगी ।

श्रीमती अरुणा देवी: अध्यक्ष महोदय, 1990 से वहॉ स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है लेकिन अपना भवन नहीं रहने के कारण मरीजों को कठिनाई होता है, वहॉ पर जमीन है । इसलिए माननीय मंत्री जी बता दें कि कब तक वहॉ पर अपना भवन बना देंगे ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/25-3-17

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, जमीन की उपलब्धता का पता कर लिया जायेगा और राशि उपलब्ध होने के बाद उसका निर्माण करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं: श्री मिथिलेश तिवारी, श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री राणा रणधीर, श्री ललन पासवान, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री संजीव चौरसिया, श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री विजय कुमार सिन्हा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: शून्यकाल हो जाने दीजिये न । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी कहना चाह रहे थे और सरकार भी कुछ कहना चाह रही है इसलिए आसन चाहता है कि शून्यकाल भी माननीय सदस्यों का हो जाय, ध्यानाकर्षण तो छोटा है हो जाय फिर आप कहेंगे, सरकार कहेगी ।

दूसरी एक और बात माननीय सदस्यों से अनुरोध है, खास तौर से जो शून्यकाल सूचनाओं को देने में या जमा करने में सक्रिय रहते हैं, वैसे हमारी कोशिश होती है कि जितने माननीय सदस्य प्रासंगिक सूचनाएं देते हैं, मैं सब को सम्मिलित कर लूं लेकिन अब संख्या उनकी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है । जैसे आज 40-42 हो गयी है तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप सूचनाएं दीजिये जरूर लेकिन उसमें कम से कम एक चीज जिसकी पहली आवश्यकता होती है कि वह विषय हाल का होना चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ कभी कभी शून्यकाल की सूचना में भी कोई दस वर्ष से काम नहीं हो रहा है, कोई पांच वर्ष से नहीं हो रहा है, वैसे मेरी कोशिश होती है आसन की तरफ से कि कोई माननीय सदस्य उस पर मेहनत कर के किसी समस्या को ला कर के सदन के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो आसन उसमें सहयोग करता है लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित करनी होती है । आज तो हम कोशिश कर के उसको, सब को सामंजित करेंगे इसमें भी आपका सहयोग चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़िये क्योंकि दोनों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को अपनी बात कहनी है इसलिए आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह होगा कि संक्षेप में और शीघ्रता से अपनी सूचना पढ़ेंगे ।

श्री नीरज कुमार: अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत एस0एच0-77 के नरैहिया से खैरा, समेली एन0एच0-31 को पार करते हुए मधेली, मरघिया, बरारी, नौनिया, सिकट, सेमापुर होते हुए एन0एच0ए0आई0-131 ए0 शरीफगंज तक जो ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है । उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने की मांग करता हूँ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के महम्मदपुर निलानी पंचायत में धमई नदी में स्थानीय मछली व्यवसाय में लिप्त माफिया के द्वारा मार्च माह में पानी को बहाकर मछली मारते हैं जिससे पानी की भीषण किल्लत होती है एवं पान की खेती पटवन के अभाव में पूर्णरूपेण बर्बाद हो जाती है । अत: सरकार वर्णित स्थल पर पानी की बर्बादी पर रोक लगाये ।

श्री अमीत कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत एन0एच0-107 गौशाला से खेरेवा तक का पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन रहने के कारण उसका समय समय पर जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है जिससे उक्त पथ का हालत जर्जर हो चुकी है । अतएव जनहित में उक्त पथ का स्थानांतरण पी0डब्लू0डी0 विभाग में किया जाय ।

डॉ0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 पैकेज नं0 बी0आर011आर0-089 जटवा लिंक रूट नं0 23 चिचुरहिया वर्ष 2008-09 बी0आर011आर0-088 जटवा लिंक रूट नं0 23 जनरेवा, बी0आर011आर-086 मोतिहारी छपवा एन0एच0 28 ए रोड-पचरूखा वर्ष 2008-09 बी0आर011आर-085 में वर्ष 2008-09 में कार्य कराना था जो नहीं हो पाया है । अत: इसका निर्माण कार्य शीघ्र करावे ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के महकमपुर से पड़री झारखंड सीमा तक 04.5 कि0मी0 आवागमन की सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है । जनहित में महकमपुर से पड़री झारखंड सीमा तक नाबार्ड योजना से सड़क निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूॅं ।

श्री फैसल रहमान: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड अन्तर्गत चैनपुर बाजार से पूण्देव चौक तक जाने वाली सड़क में जो पुल है वह क्षतिग्रस्त हो गया है । अत: पुल बनाने की सरकार से मांग करता हूॅं ।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के भगवानपुर-संजात पथ में निर्मित लोहापुल गत रात अचानक धंस जाने से उत्तर बिहार के चार पांच जिलों का यातायात पूर्णत: ठप्प है। जनमानस में आक्रोश है । जनप्रतिनिधिगण आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं । अतएव सरकार से शीघ्र समाधान की मांग करता हूॅं ।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के प्रोजेक्ट गंगोत्री बालिका उच्च विद्यालय, चेनारी में फर्जी छात्रवृत्ति निकालकर घोटाला किया गया था जिसका मॉडल थाना सासाराम कांड संख्या 183/17 है । अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अत: सरकार से मांग करते हैं कि उक्त घोटाले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई एवं गिरफ्तारी करावें ।

श्री रामविशुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में 18 वर्षों से चौकीदार के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद रिक्त है। पूर्व से चौकीदार के पद पर पिछड़ा एवं महादलित समुदाय के व्यक्तियों को ही सरकार द्वारा नियुक्त करने की परम्परा रही है । अत: जनहित में चौकीदार के पद पर सेवानिवृत्त चौकीदार के परिवार के ही व्यक्तियों को नियुक्त करने की मांग सरकार से करता हूॅं ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, बिहार में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार से रिसोर्स गैप ग्रांट अनुदान की अनुपलब्धता के कारण बिहार विनियामक आयोग द्वारा आगामी 1 अप्रैल 2017 से राज्य के नागरिकों पर 55 प्रतिशत विद्युत बिल में बढ़ोत्तरी का फैसला किया गया है । सरकार अविलम्ब बिल वृद्धि का प्रस्ताव वापस करे ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आरा के अंबेदकर छात्रावास में 11-2-17 को 10वीं की महादलित छात्रा नीतू कुमारी की इलाज के अभाव में मौत हो गयी, मृत छात्रा के परिजन

को 10 लाख का मुआवजा तथा विद्यालय की नारकीय स्थिति ठीक कर बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग करता हूॅ ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, वैशाली डीका बलात्कार हत्याकांड में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही बलात्कार की धारा 376 और पोक्सो ऐक्ट लगायी गयी 90 दिन होने को है, चार्जशीट दाखिल नहीं कर अपराधियों को जेल से बाहर निकालने की साजिश हो रही है, उक्त धाराएं लगाकर चार्जशीट दाखिल करें ।

श्री सत्येदव राम: अध्यक्ष महोदय, आरा स्थित चांदी दलित छात्रावास को सरकारी अभियंता ने जर्जर घोषित कर दिया लेकिन अभी भी मजबूरी में वहां छात्र रह रहे हैं, यही हाल महादेवानंद महिला कल्याण छात्रावास की है, छात्र व लोकहित में तत्काल दोनों छात्रावासों की जगह 2 हजार बेड वाले छात्रावासों का निर्माण कराया जाय ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में 10 इंटर उच्च विद्यालय एवं 10 उच्च विद्यालय है । 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा केन्द्र नवीनगर से बाहर रहने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है । मैं नवीनगर में 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा केन्द्र बनाने की सरकार से मांग करता हूॅ ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अनु0जाति/जनजाति के लिए नर्सरी तालाब, ट्यूबवेल तथा पम्पसेट के अधिष्ठापन की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी मधुबनी के लोगों तक प्रचार प्रसार के अभाव में पहुंच नहीं पा रही है । लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं । अत: उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के रतनीफरीदपुर प्रखंड के ग्राम उचटा में अतिरिक्त प्रा0स्वा0 केन्द्र स्वीकृत है किन्तु भवन का निर्माण नहीं होने से संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । जमीन उपलब्ध है । अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की मांग करता हूॅ ।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर नगर निगम के नाथनगर में स्थित एस0एस0बालिका इंटर स्कूल, नाथ नगर में वर्ग 9 एवं वर्ग 12 तक कुल 2711 छात्राएं नामांकित है । विद्यालय कक्ष के अभाव में छात्राओं को पठन पाठन में कठिनाई होती है । उक्त विद्यालय कक्ष में 10 अतिरिक्त कमरा निर्माण की सूचना देता हूॅ ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत ओबरा प्रखंड में एन0एच0-98 उबभट्टी से रामबाण ललारो ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क का निर्माण किया गया है लेकिन बीच बीच में पुल पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है जिससे आवागमन बहुत बाधित है । अत: प्रश्नाधीन सड़क के बचे हुए कार्य को तत्काल कराने की मांग करता हूॅ ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड के उच्च विद्यालय, पताही के सरकारी जमीन को अवैध कब्जा किया जा रहा है । लोगों में आक्रोश एवं तनाव है । कभी-भी अप्रिय घटना घट सकती है ।

सरकार अविलम्ब उच्च स्तरीय जॉच कराकर कार्रवाई करे ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखण्ड के कोचस बाजार में NH-30 और सासाराम-चौसा पथ का चौराहा है । रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं आरा का केन्द्र बिन्दु है। इस चौक पर अक्सर जाम लगा रहता है ।

मैं मॉग करता हूँ कि कोचस चौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस या अन्य पुलिस की व्यवस्था की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत विगत कई वर्षों से एक भी प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया गया है । सरकार इस पर नियम संगत कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करावे ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बेतिया जिला के प्रखण्ड रामनगर एवं गौनाहा दोनों प्रखंडों के प्रखंड एवं अंचल में 3 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण करने की मैं मॉग करती हूँ जबकि सरकार का नियम है कि एक स्थान पर कोई भी कर्मी 3 वर्षों तक ही रह सकता है ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सरकार के निर्णय के आलोक में ज्ञापांक-899 देसी चिकित्सा स्वास्थ्य, पटना दिनांक-28.11.1996 पत्र निर्गत कर डॉ0 मो0 ग्यासुद्दीन, प्रभारी चिकित्सक, अखगॉव भोजपुर को सूचित किया गया था कि दान्तव्य होमियोपैथिक औषधालय, अखगॉव भोजपुर के सरकारीकरण हेतु निधि का उपबंध होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

अतएव मैं सदन के माध्यम से इसके सरकारीकरण की मॉग करता हूँ ।

श्री चंदन कुमार : महोदय, खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली प्रखण्ड के लदौड़ा-मछड़ा REO पथ में घानाघाट में कल्भर्ट पथ की सीधी लाईन से 200 मीटर अलग पुलिया बना हुआ है ।

जिसके कारण उक्त मुख्य पथ से बड़ी गाड़ी का आवागमन नहीं हो पाता है । जनहित में नये सिरे से पुलिया बनाने की माँग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखण्ड के ग्राम-मंजूरखा, देव प्रखण्ड के ग्राम-चतरा, हजारी में पेयजल की समस्या के निजात के लिए टंकी एवं पाईप-लाईन की योजना विगत तीन वर्षों से अपूर्ण है ।

अतः आग्रह है कि इन योजनाओं को जल्द पूर्ण कराकर ग्रामीणों की पेयजल की समस्या से निजात दिलाया जाय ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल के चामुटोला पुल का एप्रोच रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसपर प्रतिदिन ढ़ाई से तीन हजार लोगों का आवागमन होता है । यह पुल कई प्रखण्डों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है ।

अतः जनहित में सरकार से चामुटोला पुल के एप्रोच रोड के यथाशीघ्र निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पूर्णिया सहित कोसी के 30 प्रखंडों में संचालित बाल विकास परियोजना कई महीनों से बगैर सी0डी0पी0ओ0 के प्रभारी द्वारा संचालन किया जाता है । इससे 5874 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लगभग 2.5 लाख बच्चों का पोषाहार प्रभावित हो रहा है ।

अतः मैं सरकार से तत्काल प्रत्येक प्रखंड में सी0डी0पी0ओ0 को स्थाई प्रभार देने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, निम्न सड़क जो कि सरकारी मार्गदर्शिका के अनुरूप है, को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहित किये जाने की मैं माँग करती हूँ :

पथ का नाम - जिला मुजफ्फरपुर एन0एच0 57 काजीइंडा चौक से ग्राम-रघुनाथपुर, मनशाही, नवादा, मणिका, रजवाड़ा और रोहुआ होते हुए जिला सड़क मुजफ्फरपुर पूसा पथ मार्ग तक स्थित सड़क ।

डॉ0 रंजु गीता : महोदय, सीतामढ़ी में लालू राय की 13 वर्षीय पुत्री विपाशा प्रिया को हत्या कर पंखे से लटका दिया । उसकी दक्षता के आधार पर सरकारी स्तर से पढ़ाई हो रही थी । काण्ड संख्या 132/17 मृतक का पूरा परिवार आमरण अनशन पर है । दोषियों की गिरफ्तारी एवं कड़ी कार्रवाई हेतु सरकार से माँग करती हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के हरिपुरकला पंचायत के ग्राम नवटोलिया लक्ष्मीपुर वार्ड नं0-5 के पश्चिम हरि मड़र के आड़ा के पास फॉका में बराबर छिनतई और लूट-हत्या पर नियंत्रण के लिए एक पुलिस चौकी स्थापित करने की मॉग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सोनवर्षा के विराटपुर चण्डी स्थान से खजुराहा भबड़ा, मोतिपोखर-गोलमा घोघनपट्टी होते हुए पतरघट मेन सड़क काफी जर्जर स्थिति में रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ।

मैं सरकार से मॉग करता हूँ कि उक्त जर्जर सड़क का पक्कीकरण करावें ।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत शरीफगंज कंतनगर से बड़ी बथना, मनसाही चौक होते हुए चॉदनी चौक मरंगी तक ग्रामीण कार्य विभाग की जर्जर सड़क रहने के कारण नित्य प्रतिदिन बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं ।

अत: इस सड़क का पूर्ण जीर्णोद्धार करने की मॉग सरकार से करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार राज्य में TET,2011 में लगभग 1 लाख 44 हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये, जिसमें 82 हजार के लगभग की बहाली हुई, बाकी लोग अभी सड़क पर भूखमरी की स्थिति में हैं ।

सरकार से सभी उत्तीर्ण छात्रों को शिक्षक में बहाली करने की मॉग करता हूँ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, सदर अस्पताल कटिहार में स्वीकृत 300 बेड का अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से अस्पताल में मरीज बरामदे पर सोने पर विवश हैं । रोगियों एवं चिकित्सकों को इलाज में भारी कठिनाई हो रही है ।

अत: भवन का निर्माण तुरंत प्रारंभ सरकार करे ।

श्री सरोज यादव : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग में फर्जी प्रमाण-पत्र वाले संवेदकों को टेन्डर दिया जा रहा है । जिसमें रामजी सिंह एण्ड को0 15 माह पहले फर्जी पाया गया, उसे भी टेन्डर दिया गया । अनिम कंस्ट्रक्शन हिलसा डिवीजन का T.D. फर्जी होने पर भी नोडल पदाधिकारी एवं अभियंता प्रमुख द्वारा टेन्डर दिया गया और रामजी सिंह एण्ड को0 प्रक्रिया में है ।

अत: सरकार फर्जी संवेदकों की जॉच कर ब्लैक-लिस्टेड करे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, 24 मार्च, 2017 की रात्रि में दरभंगा जिला में भारी ओला-वृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों के फसल की भारी क्षति हुई है ।

सरकार अविलम्ब टीम भेजकर सर्वेक्षण कराये और किसानों को मुआवजा दे।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड से गुजरने वाली परमान नदी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के कारण किसानों द्वारा लगाये गये हजारो एकड़ की खेती बर्बाद हो जाती है । बरसात के तीन माह छात्र-छात्राएँ एवं आम नागरिक को बेहद कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

नदी के दोनों किनारे रिंग बॉध बनाने एवं बॉध के उपर पक्कीकरण कराने की मॉग करता हूँ ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड के मरीचा चौक से छपकी होते हुए गोढ़नी तक नून नदी पर पुल नहीं रहने और जर्जर सड़क रहने से दर्जनों गॉव के लोगों को 10 कि0मी0 घूमकर प्रखण्ड जाना पड़ता है, जनहित में पुल एवं जर्जर सड़क बनाने की मॉग करता हूँ ।

डॉ0 संजीव चौरसिया : महोदय, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट-2003 की धारा 43 के तहत परिसर के मालिक या दखलकार द्वारा विद्युत कनेक्शन आवेदन देने की तिथि से एक महीने के अंदर विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश एवं मा0 पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद दीघा के 1024.52 एकड़ में बसे लोग नये विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं ।

अतएव सरकार से वर्णित क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन देने की मॉग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, पूरे राज्य में बिजली बिल को 1.10 पैसा से बढ़ाकर 5.75 पैसा करना यहॉ के गरीब किसानों के साथ मजाक है, जबकि दूसरे कई राज्यों में सरकार के द्वारा किसानों का बिल माफ कर दिया जाता है ।

अत: सरकार राज्य के गरीब किसानों की बढ़े बिजली बिल पर फिर से विचार करे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

डॉ0 रंजु गीता : महोदय, सीतामढ़ी जिला का मामला अत्यंत संवेदनशील है, सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ......

अध्यक्ष : वह तो आपने सूचना पढ़ दी है, उसको सरकार देखेगी ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री निरंजन कुमार मेहता, रामसेवक सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी विश्वविद्यालय यथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागपुलर, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर आदि विश्वविद्यालयों के लगभग सभी विषयों में व्याख्याता का पद वर्षों से रिक्त है । व्याख्याता का पद लम्बे समय से रिक्त रहने से अध्यापन कार्य में काफी कठिनाई होती है जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक पद भी वर्षों से रिक्त हैं । मधेपुरा के अधीन अंगीभूत हरिहर साहा महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) में हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, तर्क शास्त्र, उर्दू एवं अर्थशास्त्र के व्याख्याता तथा प्रधान सहायक, लेखापाल, लिपिक, आदेशपाल एवं टंकक के पद रिक्त हैं ।

अतएव राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त व्याख्याता एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-9/आजाद/25.03.2017

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मेरा क्या हुआ ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए न, सरकार ने समय ले लिया । माननीय सदस्य श्री रामनारायण मंडल ।

सर्वश्री रामनारायण मंडल, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, ‘‘पूरे राज्य में गरीबों के इलाज के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकृत चिकित्सालयों में से 98 प्रतिशत में इलाज नहीं हो रहा है, जिससे गरीब मरीजों को भारी कठिनाई हो रही है । इलाज नहीं होने का कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार, अधिकृत चिकित्सालयों को इलाज किये गये पैसों का भुगतान नहीं कर रही है ।

अतएव अधिकृत चिकित्सालयों, जिनका कार्यकलाप ठीक है उन्हें अभी तक किये गये इलाज के पैसों के भुगतान के साथ-साथ गरीब मरीजों का इलाज शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निविदा के माध्यम से जिलों के लिए बीमा कम्पनियों का चयन किया गया था । वर्ष 2015 में यह योजना सरकार के निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दी गई । बीमा कम्पनियों द्वारा चयन किये गये निजी अस्पतालों को इलाज पर हुये खर्च की राशि का भुगतान किया जाता है । सरकार संबंधित बीमा कम्पनियों को कार्ड की संख्या के आधार पर प्रिमियम राशि का भुगतान करती है । सरकार द्वारा 14 जिलों के लिए संबंधित बीमा कम्पनियों को प्रिमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है, शेष जिलों में बीमा कम्पनियों पर जॉचोपरान्त नियमानुसार देय प्रिमियम की भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, इसे जून, 2017 तक कर दिया जायेगा । सरकार द्वारा सीधे चिकित्सा संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता है । निजी चिकित्सालयों के भुगतान करने की जवाबदेही बीमा कम्पनियों की है ।

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों से जुड़ा सवाल है और बी0पी0एल0 परिवार का सवाल है । मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार यह इलाज कराने का काम कब प्रारंभ कर देगी, इसकी समय सीमा हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से ?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, सरकार की यह भी जिम्मेवारी है कि जो कार्य-कलाप हो रहे हैं, उसकी समय-समय पर आवश्यकतानुसार जॉच करायी जाय । जॉच का कार्य लगभग पूरो हो गया है, दो माह में सारे भुगतान कर दिये जायेंगे ।

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भुगतान की बात कही, यह तो मैं सेकेन्ड में पूछते । फर्स्ट पूछना चाहते हैं कि ये इलाज का काम कब से प्रारंभ करा देंगे, यह हम जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : असल में उन्होंने आपकी सूचना से ही कुछ इन्फ्रेन्स ड्रा कर लिया है । आपने सूचना में लिखा है कि जल्दी भुगतान कर दीजिए, नहीं भुगतान के कारण ही इलाज बन्द है तो वे कह रहे हैं कि हम भुगतान कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आपने ही कारण बताया है कि भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए इलाज बन्द है, वो भुगतान कर देंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, भारत सरकार 31 मार्च, 2017 के बाद एक नई योजना शुरू की जा रही है, इस योजना के बदले एक नई स्कीम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हो रही है, जिसमें लाभार्थियों के इलाज पर 30हजार के बदले एक लाख रू0 खर्च किया जायेगा ।

इसे भी इन्सयोरेंस कम्पनी के माध्यम से इम्पलीमेंट किया जायेगा । यह कोई भारत सरकार या बिहार सरकार की बात नहीं है । चावल के मामले में, फसल बीमा के मामले में भी जो सवाल हुआ प्रधानमंत्री ....

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, सवाल इलाज का है तो ये चावल पर चले गये ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : जब सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए ।

महोदय, यह स्कीम जो शुरू की जा रही है, उसमें एक लाख रू0 तक का इलाज का प्रावधान है । उससे पहले पूर्व योजना से संबंधित सारे कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके सारे बैकलॉग को खतम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता की चिन्ता है कि चाहे पुरानी योजना या एक अप्रील से नई योजना शुरू हो रही है, जो गरीब हैं, उनका इलाज बाधित नहीं होना चाहिए, यह माननीय सदस्य की चिन्ता है ।

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, ठीक ही आपके द्वारा कहा गया है । मेरी चिन्ता है कि इलाज कब प्रारंभ कराईयेगा, यह मेरी चिन्ता है और पेमेन्ट करने का जहां तक सवाल है, जिनका कार्य संतोषजनक रहा है, ठीक-ठाक रहा है, उसको राज्य सरकार पेमेन्ट करे ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता यह भी थी कि प्राइवेट होस्पीटल को कब पेमेन्ट किया जायेगा तो इनकी ....

श्री रामनारायण मंडल : महोदय, मैंने यह नहीं कहा है, मैंने कहा है कि आपने ऑथोराईज किया है।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : प्राइवेट होस्पीटल को भुगतान करने की जिम्मेवारी बीमा कम्पनियों की है । इसमें भारत सरकार की सहमति लेना बाकी है, स्वीकृति लेना बाकी है । इसलिए महोदय, माननीय सदस्य जिन लोगों ने प्रश्न किया है, उनको निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो सारी चीजें प्रक्रियाधीन है और समय सीमा के अन्दर ही इन सारे कार्यों का सम्पादन करते हुये इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा और आगे जो नई स्कीम है, उसमें उसे कन्भर्ट किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सूचना में भी माननीय सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि जिन अधिकृत चिकित्सालयों का क्रिया-कलाप ठीक है, उन्होंने उसी के संबंध में कहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : सर, उसी की न जॉच हो रही है ।

अध्यक्ष : चलिए, माननीय सदस्य पूछिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में 600 होस्पीटल को इमपैनल किया गया है । इस योजना के अन्दर पूरे बिहार राज्य में 600 होस्पीटल में इलाज कराने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया था और इसमें 4 बीमा कम्पनियों से एग्रीमेंट किया था, जिसमें एक बीमा कम्पनी को 20 जिला, दूसरे को 9 जिला, तीसरे को 7 जिला एवं चौथे को 2 जिला दिया गया था । भारत सरकार 2015 में 34 करोड़ रू0 दे दिया तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ आपके

माध्यम से कि जो भारत सरकार ने 34 करोड़ रू0 दिया 2015 में तो इसमें से इन्होंने कितना पैसा खर्च किया । नई योजना की जो ये बात कर रहे हैं कि मार्च के बाद भारत सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है, जिसमें सिनियर सिटिजनशीप को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक लाख रू0 तक की राशि को इलाज में देना है तो क्या इस नई योजना को भारत के अन्य राज्यों ने एडोप्ट कर लिया, जहां इलाज शुरू हो गया है तो क्या बिहार की सरकार इस योजना को एडोप्ट करेगी और उसके अनुसार इलाज शुरू करायेगी ? तीसरा महोदय है कि 2015 तक केन्द्रांश की राशि आ गई है, उन पैसों को भी इन्होंने बीमा कम्पनियों को नहीं दिया है और ....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि जिनका पैसा बाकी है, उनका हम शीघ्र भुगतान करा रहे हैं । इन सब प्रश्नों का जवाब दे दिये तो आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं यह भी उनसे जानना चाह रहा हूँ कि 2014-15 से अब तक कितने मरीजों का इलाज कराया है और कितने को इन्होंने पैसा दिया है ?

अध्यक्ष : चलिए अब इसके बारे में कुछ बताना है ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, यह पहले जो भी सेलेक्शन हुआ करता था, वह श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से हुआ करता था । बाद में इसे ट्रांसफर किया गया और यह योजना मार्च, 2017 के बाद बन्द होगी । माननीय सदस्य को जानकारी में बताना चाहता हूँ कि नेशनल इन्सयोरेंस कम्पनी को 9 जिले प्रदान किये गये थे, न्यू इंडिया इन्सयोरेंस कम्पनी को 7 जिले और 20 जिले यूनाईटेड इंडिया इन्सयोरेंस कम्पनी को, रिलायंस जियो को 2 जिले दिये गये थे और इन तमाम जिलों में कार्य-कलाप जो इन प्राइवेट कम्पनियों के रहे हैं, जो इन्सयोरेंस कम्पनी है, उसकी गतिविधि की जॉच करते हुये और इसमें भारत सरकार की सहमति के साथ इनके पैसे दिये जायेंगे, अगर माननीय सदस्य की चिन्ता है कि इन कम्पनियों को पैसे क्यों नहीं मिले, सारे पैसे दिये जायेंगे, पैसे की कमी नहीं है और जो आगे की स्कीम है, वह मार्च के बाद लागू की जायेगी तो यह तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है । इसमें कोई दूसरा, तीसरा बात कहां है । महोदय, इसमें माननीय सदस्य का यह सरकार ने सूचना के तौर पर बताया कि मार्च के बाद से दूसरी योजना शुरू होगी, वह माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण का विषय नहीं था, यह इस काम पर बताया गया, चूँकि यह योजना चेंज होने वाली है ।

टर्न-10/अंजनी/दि0 25.03.2017

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें 30 रूपया लेकर एक बी0पी0एल0 का रजिस्ट्रेशन करना है, तो राज्य सरकार बताये कि कितने लोगों से 30 रूपया लेकर....

अध्यक्ष : अब तो नयी योजना ...... सचीन्द्र जी, अब आप बैठ जाइए, प्रमोद जी को पूछने दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम रूपया भुगतान कर देंगे तो अबतक कितना रूपया भुगतान किये हैं और कितना रूपया भुगतान करना है, 34 करोड़ रूपया माननीय सदस्य ने बताया ? दूसरी बात यह कि जिन बीमा कम्पनियों को इंश्योरेंस का पैसा दिया जायेगा और उनकी लापरवाही के कारण उन गरीबों का बिना इलाज कराये हुये पैसा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाओं का काल समाप्त हुआ । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाह रहे थे ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष : अब नेता बोल रहे हैं तो उत्तर कहां से आयेगा ? नेता जब बोल रहे हैं तो आप बैठ जाइए न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिजली दर में 55 फिसदी की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इससे राज्य के किसान, गांव के गरीब किसान, उद्‌मी, बुनकर, शहरी-ग्रामीण उपभोग्ता प्रभावित होंगे और यह बिहार के साढ़े ग्यारह करोड़ जनता पर बोझ पड़ेगा । इससे बिहार में महंगाई बढ़ेगी । एक ओर जो बिजली कम्पनी है बिहार में बिजली का बिल भेजने में बिल को बढ़ाकर देने का काम कर रही है, फिर अगर बिजली का दर बढ़ जायेगा तो दोहरा मार पड़ेगा उपभोग्ता पर । एक ओर केन्द्र की सरकार बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर घर और हर गांव में प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली पहुचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वहां पर सरकार के द्वारा रेट बढ़ने से गांव के गरीब किसान बिजली से वंचित हो जायेंगे, इसलिए इस इशू पर हमारे 12 माननीय सदस्यों ने आज काम रोको प्रस्ताव लाया था और एक माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी ने इसे शून्य-काल में लाया था । महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि दर बढ़ जाने से बिहार में महंगाई बढ़ेगी, बिहार की साढ़े ग्यारह करोड़ जनता पर तथा कृषि और उद्योग पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं और सभी माननीय सदस्यों की मांग है कि इस अप्रत्याशित वृद्धि की बात जो हमलोगों ने अखबारों में देखा है, उससे सारा बिहार चिंतित है । हम बिहार की जनता के हित में सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बढ़े हुए दर को सरकार वापस ले ताकि आने-वाले समय में बिहार की जनता पर बोझ नहीं पड़े ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय....

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार को सूचना देना चाहते हैं या स्मरण दिलाना चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में एक संचिका में यह आदेश था कि पांच एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली बिल माफ कर देंगे । आज जो विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा विद्युत दर में जो बढ़ोत्तरी की बात की गयी है तो हम यह कहना चाहते हैं कि कहीं का डेफिसिट कहीं से पूरा करने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है तो यह उनकी बात है लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग गरीब हैं, गरीबी स्थिति में हैं तो हमारा मानना यह है और हम अनुरोध करना चाहते हैं कि बिजली बिल में बढ़ोत्तरी के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए और किसानों को पांच एकड़ जमीन तक के बिजली माफ करने के लिए हम समझते हैं कि सरकार को इसपर पहल करना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्त्ति के लिए कहीं दूसरे जगह स्थापित होना चाहिए, यही मैं सूचना देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : महबूब जी, सुन लीजिए न सरकार का । माननीय सदस्यगण, ...आप क्या कहना चाहते हैं, आप जल्दी से बोलिए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, हमारा यही कहना है कि बिहार की जनता से दिल्ली की जनता की आर्थिक आमदनी सात गुणा ज्यादा है महोदय । दिल्ली की सरकार ने बिजली का बिल आधा कर दिया और यहां बिहार में 28 प्रतिशत् बिजली दर बढ़ा दिया गया...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन प्रारम्भ होने से पहले सरकार ने सदन में बिजली की बढ़ी दरों के संबंध में वक्तव्य देने की इच्छा की सूचना दी थी और मैंने सदन के प्रारम्भ होते ही आपको भी यह बताया था । अब माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग से अनुरोध है कि अगर सरकार वक्तव्य देना चाहती है तो वह दे सकती है ।

बिजली दर में बढ़ोत्तरी पर सरकार का वक्तव्य

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी जानकारी और अपनी-अपनी इच्छा के अनुरूप विभिन्न बातों को रखा । उससे मेरा कोई, सरकार की ओर से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा दिनांक 24.03.2017 को वर्ष 2017-18 के लिए बिजली के टैरिफ की घोषणा की गई है, जो राज्य सरकार के अनुदान रहित है । पिछले वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को सीधे अनुदान दिया जाता था, जिसमें सम्मिलित करने के बाद टैरिफ संबंधित याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर किया जाता था । इस वर्ष नीतिगत निर्णय के तहत अनुदान रहित टैरिफ याचिका दायर किया गया

था। टैरिफ आदेश 2017-18 की प्रति आज प्राप्त होगी, कल केवल सिर्फ घोषणा हुई थी महोदय, जिसके गहन अध्ययन एवं पड़ोसी राज्यों के टैरिफ से तुलना कर राज्य सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को दिये जाने वाली अनुदान पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी । वर्त्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि अनुदान की राशि विद्युत वितरण कम्पनियों को नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को सीधे राज्य सरकार देगी। इसलिए इसी चलते सत्र में सरकार एक-दो दिनों में गांव, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सभी टैरिफ दरों का एक समुचित संतुलन तैयार करके सरकार निर्णय लेकर इसी चलते सत्र में सरकार घोषणा करेगी । क्योंकि महोदय, यह 1 अप्रील से लागू होने का नियम है, इसलिए कोई बहुत जल्दीवाजी नहीं है, दो-तीन दिनों में इसका निर्णय हमलोग कर लेंगे ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुदान मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आइ0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 43,35,01,21,000/-(तैंतालीस अरब पैंतीस करोड़ एक लाख एक्कीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री नितिन नवीन, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय
राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श
करने के लिये ।''

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या राज्य में जो शहर होता है वह उसका ड्राइंग रूम के समान होता है, लेकिन जहां शहर की हालत खास्ता हो तो गांव और दूसरे जगहों की बात अपने आप समझ में आती है। उसकी बेहाली का जवाब नहीं होता है। महोदय, यह कहते हुए निराशा होती है कि सरकार ने अन्य विभाग की तरह इस विभाग में बजट की राशि तो बढ़ायी है, अगर प्रत्येक वर्ष का हिसाब देखें तो लेकिन खर्चा नहीं कर पायी और पैसा सरेंडर होता है। महोदय, बिहार में अगर एक शहर को ले लिया जाय, राजधानी को ही ले लिया जाय तो राजधानी की बात करता हूँ। जो केवल राजधानी ही नहीं है, पूर्व में पुरातन में यह देश की राजधानी होती थी, बहुत ही इसका गरिमा रहा है, इतिहास रहा है, परन्तु वर्तमान में जब इसका स्मार्ट सिटी में चयन भी नहीं हो सका यह बहुत दुख का विषय है। पटना शहर में पेयजल, जल जमाव, सड़कों पर भीड़भाड़, ट्रैफिक अव्यवस्था, विधि व्यवस्था, अतिक्रमण, गन्दगी सहित सभी मूलभूत जो इंसान की समस्याएं हैं पटना शहर के लोग उसको भोग रहे हैं, जो विकराल मुंह बाए खड़ी है। महोदय, सरकार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत नाला, नाली का काम जो आम गलियों में होता है उसको भी समाप्त कर दिया, यह शहरवासियों के साथ भयंकर अन्याय और एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय है। महोदय, नुरूम योजना के तहत 2010 से 2012 में जब काम शुरू हुआ तो 420 करोड़ रूपये की लागत से पूरे शहर में पेयजल बिछाने की बात हुई, जल मीनार लगने की बात हुई। दीघा स्थित वाटर ट्रीटमेंट का कुछ काम भी हुआ, लेकिन पता नहीं उसको सरकार ने क्यों बंद कर दिया, पहले कहा धीमा चलता है। ये किया है, लोग त्रस्त हैं और यह सरकार जिस तरह से रोम जल रहा था और बांसुरी बज रहा था वही कहावत चरितार्थ हो रही है। महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना 2015-16 के द्वारा पटना जिला कुम्हरार विधान सभा में 2 करोड़ लागत के 6 पार्कों का निर्माण किया जाना था, अभी तक वह कार्य आरंभ नहीं हुआ है। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि एक तरफ पटना शहर का बहुत बड़ा हिस्सा बरसात के तीन महीने तक जलमग्न रहता है। जिसकी वजह से महामारी की स्थिति हो जाती है, मुहल्लावासी भागने पर मजबूर हो जाते हैं और दूसरे तरफ आबादी बढ़ने से सिवरेज पहले से कम हो गया है और वह भी ध्वस्त हो चुका है, गलियों में पानी पसरा रहता

है। यही नहीं एन0डी0ए0 के जमाने में सरकार द्वारा इसपर काम कुछ तेजी से जरूर हुआ था और अभी धीमाधीमी चलता है। महोदय, मैं इस काम में चुस्ती की बात इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहता हूॅ। महोदय, हमने सरकार को लिखित और मौखिक बैठकों में कई बार कहा है कि जो सन्दलपुर हो या पीरमुहानी हो या कदमकुऑं का इलाका हो, इन सब इलाकों में या पूरा कंकड़बाग का इलाका है और इन सब इलाकों में जो जल-जमाव होता है उसके लिए मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर बाजार समिति में जो अधूरा संप है उसके निर्माण के लिए सैदपुर नहर कंकड़बाग मीठापुर से नन्दलाल छपरा तक कच्चे नाले का गहरीकरण, चौड़ीकरण और पक्कीकरण का आग्रह किया था। यही नहीं महोदय, बादशाही पैन का भी गहरीकरण और चौड़ीकरण की बात कही थी। महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करता हूॅ कि बरसात में जो छोटे बड़े नालों की उड़ाही, मेन हॉल कैचपीटों की सफाई का मानक रूप से नहीं होता है, डूर टू डूर कचरा उठाव एवं ठोस कचरा से बिजली उत्पादन का कार्य भी अभी आरंभ नहीं हुआ है। शहरों की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने की आवश्यकता है। इन सारे कारणों से महोदय मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यह शहर के विकास में शहर विकास का जो मंत्रालय है यह पूरी तरह असफल हो रहा है। इसलिए मैंने 10 रूपये का कटौती प्रस्ताव लाया है। आपने हुजूर, बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं चाहता हूॅ कि माननीय मंत्री जी इसपर त्वरित कार्रवाई कुछ करें।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा प्रस्तुत नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूॅ। महोदय, आज आदरणीय अरूण कुमार सिन्हा जी के कटौती प्रस्ताव के निश्चित तौर पर विपक्ष में हूॅ जबकि हमें दुख हो रहा है कि जहां एक तरफ शहरी क्षेत्र के भाजपा के सारे विधायक मैक्सिमम रूप से आते हैं। शहरों में यह काम किया जाय, वह काम किया जाय, सदन हमेशा इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। वहीं दूसरी तरफ इस मांग पर कटौती प्रस्ताव भी इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया- दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। कटौती होगी तो योजनाओं में भी कटौती होगी और काम करने हैं तो फिर बजट न सिर्फ सर्वसम्मति से पारित करना होगा, बल्कि और राशि बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध करना चाहिए था। क्रमशः

टर्न-12/अशोक/25.03.2017

श्री समीर कुमार महासेठ : क्रमशः महोदय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय के तहत शहरी क्षेत्रों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलया जा रहा है इस निश्चय के अन्तर्गत खुले में शैच से मुक्त स्वस्थ्य, स्वस्थ्य बिहार के लिये नगर एवं आवास विभाग के द्वारा क्षत्रों में 7 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 29 सामुदायिक

शौचालय का निर्माण कराया जा चुका हैं । हर घर नल का जल निश्चय के तहत 140 नगर निकायों के सामूहिक प्रयास से पाईप के माध्यम से पेयजल की आपूर्त्ति की जाने वाली है । शहरी क्षेत्रों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 304 वार्डो में योजना प्रारम्भ हो चुकी है, 7534 घरों को पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है। घर तक पक्की गली, नालियां निश्चय के तहत शहरों में गली–नली का निर्माण कराया जाना है । हमें आश्चर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सात निश्चय के द्वारा जो सरकार का सोच है और जहां पर शहरों में हमारे विरोध के सभी लोग आते हैं, मैक्सीमम उसी क्षेत्रों से आते हैं और अगर इसमें सरकार अच्छे ढ़ंग से काम करेगी तो हमको लगता है कि शायद आने वाले समय में जो ये दिव्य सपना देख रहे हैं उसमें शायद प्रश्न चिन्ह लगने वाला है इस बात के लिए अभी से हमलोगों के साथ मिलकर करके और बिहार का अगर ये चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आगे काम बढ़े तो उस प्रकार जैसे अभी आदरणीय अरूण बाबू ने कहा कि एक छोटी योजना जो भारत सरकार की जितनी भी योजना थी क्या कारण है कि पूर्व से जितनी संख्या पर मिलती थी आज उसको आपने संख्या को बढ़ा दिया । आज हमारे मधुबनी 68 हजार आबादी है उस योजना में पहले लागू था लेकिन आज भारत सरकार ने नई सरकार आने के बाद आप कह रहे हैं अब एक लाख से ज्यादा आबादी होगी तब ही देंगे नहीं तो फिर इसको दूसरा नाम डाले । तो पता नहीं चल पा रहा है कि किन कारणों से भारत सरकार हमलोग के साथ इनजस्टीस कर रही है और इस इनजस्टीस में आगे किनको लाभ होगा, किनको नुकसान होगा, इस बात का सोच और उस सोच के तहत कैसे यह ठीक हो इसमें अभी से सारे विरोधी पक्ष लग जायेंगे शायद हमारा सभी शहर नगर निकाय हो नगर परिषद् हो नगर पंचायत हो, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा, यह हम उम्मीद करते हैं चूंकि आज तक मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत नगर निकाय द्वारा मुहल्ला में पक्की सड़क का निर्माण कराई जा रही है । 678 वार्डो में कुल 47 कि.मी. गलियों का निर्माण कराया जा चुका है, इतने सारे कार्यो के बावजूद कुछ कमियां है जो स्वभाविक है । एक ही बार में सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता हैं । इन कमियों के लिए सरकार दोषी है ऐसा नहीं मानना चाहिए । गांव सदैव उपेक्षा का शिकार रहा है जिसके कारण गांव की बड़ी आबादी का पलायन शहर की तरफ चला आता हैं और बेतरतीब ढंग से शहर का दायरा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है जिसको अगर ढंग से लोग के आधारभूत संरचना के बिना शहरों के नजदीक में खेतों में घर बनाना शुरू कर देते हैं, बांस बल्ला पर बिजली के तार ले जाते है, हमारी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया हैं अब शायद ही किसी जगह उस तरह के बांस बल्लों पर नजर दो चार साल के अन्दर

यह पूर्णत: समाप्त हो जायेगा और जो आप देंख रहे हैं उसमें परिवर्त्तन भी हर एक साल आपको उत्तरोत्तर देखने को मिलेगा । शहरों के बेतरतीब विकास को भी हमारी सरकार ने ध्यान में रखा और ऐसी आबादी के लिए जल निकासी, सड़क, पेयजल आदि की व्यवस्था कर रही है । शहरी क्षेत्र में जल निकासी एक मुख्य समस्या है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । कचड़ा निष्पादन शहरीकरण का मूल आधार हैं और इसके लिए इन्सलेटर प्लांट की आवश्यकता होती है, राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र के कचड़ा के निष्पादन के लिए इन्सलेटर प्लांट स्थापित नहीं किया जा सका है । पूर्व से पटना जैसे जगह में भी इसमें कितने बार चर्चा हुई और आपदा प्रबन्धन से लेकर के सबों ने इस पर ध्यान देने का कोशिश किया लेकिन उस तरफ ध्यान अभी तक उस रूप में नहीं गया हैं । एक और समस्या शहरों को है कि महत्वपूर्ण है और वह है मेडिकल कचड़ा, नर्सिंग होग, अस्पताल, क्लिनिकों के बाहर मेडिकल कचड़ा फेंका रहता है अथवा नाला में डाल दिया जता है । जिससे गंभीर इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इस मेडिकल कचड़ा काभी शहरों क्षेत्रों के अन्दर निष्पादन की व्यवस्था नगर निकाय को करनी चाहिए । मैं शहरी क्षेत्र से चुन कर आता हूँ । वहां की मौलिक समस्याओं से अवगत हूँ इसलिए मैं कुछ सुझाव सरकार को भी देना चाहता हूँ, जिस पर ढंग से कार्रवाई करने की आवश्कता है । महोदय, किसी भी बाजार में हमलोग जाते हैं, जहां कुछ मॉल हैं वैसी जगहों को छोड़कर सबसे बड़ी समस्या है शौचालय और मूत्रालय का । उदाहरण के लिए पटना शहर के न्यू मार्केट हो, बोरिंग रोड हो, अशोक राज पथ हो इन सब बाजारों में सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय की बहुत बड़ी आवश्कता हैं, कई बार महिलाओं को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता हैं । अब अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे कुछ उल्लेख करते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वर्णित समस्याओं का निदान करने में जो पहल जिस ढंग से चल रहा है, परन्तु साथ में पूरे प्रदेश के लिए जो जिस तरह से पटना शहर के लिए महायोजना तैयार की गई हैं उसी प्रकार बिहार के अन्य शहरों के लिए भी महायोजना तैयार करने हेतु ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ताकि शहर के साथ गांव भी स्मार्ट बने । कुछ शिकायत मिली है जिस अनुपात में पटना के शहर निकायों में लोग नक्शा स्वीकृति के लिए जमा कर रहे हैं, परन्तु उसके मुकाबले स्वीकृति की रफ्तार काफी धीमी है, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है, यह पूरे प्रदेश में इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता हैं, हर निकाय क्षेत्रों में सड़कों की की चौड़ाई के आधार पर ही नक्शे को पारित करने की विधि बनी हुई हैं इसके लिए भी सारी सड़कों की नापी कराकर उसको औसत चौड़ाई और लम्बाई निर्धारित कर दी जाय और सड़कों

के शुरूआत में ही बोर्ड लगाकर उस सड़क के नाम के साथ यह लिख दिया जाय, उससे नागरिकों को भी जानकारी मिलेगी और गलत प्रक्रिया करने पर रोक लगेगी । हर निकाय क्षेत्र में सड़कों की ऊंचाई निश्चित किया जाय, हमारे बाप, दादा के टाईम में जो बिल्डिंग्स हैं वह कहीं न कही बिना कारण रोड लेभल निर्धारित नहीं होने के कारण करोड़ो, अरबों रूपये की क्षति हो रही है, जिसमें हम चाहेंगे कि उसके बारे में एक गाईड लाईन स्पष्ट हो सके प्रत्येक नगर पंचायत में, नगर परिषद्.

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हम चाहेंगे कि एक्ट में परिवर्त्तन कर डायरेक्ट चैयरमैन का एलेक्शन कराया गया हैं चूंकि हार्स ट्रेडिंग होता है, उसमें मुख्य कारण इस पर हैं अगर दो तरह का बैलेट पेपर दिया जायेगा तो पूरे प्रदेश में चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, इसमें आरिक्षत क्षेत्र पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और जिले के अच्छे व्यक्ति सलेक्ट हो सकेंगे .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य समीर जी अब आप समाप्त करिये, समय आपका समाप्त हुआ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, दो मिनट केवल ।

अध्यक्ष : दो मिनट नहीं, एक मिनट में खत्म करिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मधुबनी की शहर की आबादी है 68 हजार है, एक लाख से ज्यादा करने के लिए ग्रेटर मधुबनी बनाने के लिए डायरेक्शन दिया गया, सकरी हो पण्डौल हो , भगवतीपुर हो सरसोपाई हो चारों नगर पंचायत का कुछ न कुछ अर्हता रखता है सरकार का गाईड लाईन उस तरफ है, हम चाहेंगे उस तरफ ध्यान दिया जाय और 100 वर्ष से ज्यादा का हमारे यहां कैनाल हैं जो रोड लेभल से ऊपरए चला गया है हम चाहेंगे कम से कम विशेष परिस्थिति में बनाया जाय ताकि मधुबनी का जो है यह सबसे बड़ा सौ वर्ष पहले का जो सोर्स था, आने वाला समय में उसको हम बना सकें । इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ ।

टर्न-13/ज्योति

25-03-2017

श्री अभय कुमार सिन्हा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो माननीय सदस्य अरुण कुमार जी के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं माननीय विश्वास एवं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और महागठबंधन सरकार को

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री मो0 इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

हार्दिक बधााई देता हूँ कि महागठबंधन की सरकार 16-17 महीने बीत जाने के बाद आज नगर विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम विभागों में तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है । महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पिछले वर्षों नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायतों में पड़ने वाले क्षेत्रों को सुन्दर बनाने के लिए अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया गया है । मूलभूत सुविधा नागरिकों को उपलब्ध हो, इसपर विशेष ध्यान दिया गया है । हम नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पंचायतों में हम कैसे मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ रखें, इसपर आपने पैनी नजर रखने का काम किया है। विगत वर्षों में सड़क, गली, नाली, पेयजल, भवन निर्माण इत्यादि निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है । हम पुनः एक बार माननीय विकास पुरुष और विश्वास पुरुष को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए जो पद 50 प्रतिशत आरक्षित करने का काम किया है यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य है। महोदय, उनके नेतृत्व में न्याय के साथ सुशासन के मार्ग पर यह बिहार चल रहा है और इसका प्रतिकूल असर सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में हमारे लोग जो व्यवसाय करते थे उनपर बहुत ही ज्यादा पड़ा है । हमारे व्यवसाय करने वाले बंधु हरेक क्षेत्रों में व्यवसाय में बेतहासा उछाल आया है चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पंचायत का क्षेत्र हो या नगर परिषद् का क्षेत्र हो व्यवसायों में एक बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है और उछाल ही नहीं देखा गया है बल्कि एक विश्वास का माहौल भी बना है जिसमें भयमुक्त होकर लोग व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है और इसमें नगर विकास और आवास विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाने का काम कर रहा है । हम धन्यवाद देना चाहेंगे महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी का और सरकार का सबसे पहला सोच भी यही है न्याय के साथ विकास सुशासन के मार्ग पर चलने का और जहां पर न्याय के साथ यह शब्द जुड़ता है, जब न्याय के साथ विकास हो रहा है और उसी पद चिन्हों पर हमारी सरकार चल रही है तो मैं समझता हूँ महोदय, यह जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कटौती का तो कोई प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था । चूँकि निश्चित तौर पर हमारे साथी बता रहे थे कि हमारे विपक्ष के साथी माननीय जो सदस्य हैं तकरीबन सभी मैक्सिमम साथी शहरी क्षेत्रों से बिलौंग करते हैं । शहरी क्षेत्रों से आते हैं और मैं यह दावे कह सकता हूँ कि जब बिहार में माननीय विकास एवं विश्वास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सत्ता आयी उसके बाद से उन तमाम क्षेत्रों का अभूतपूर्व उसमें परिवर्तन आया है, अभूतपूर्व विकास का रास्ता खुला है । इसलिए महोदय, हम कहना चाहेंगे महागठबंधन सरकार की चुनाव के पहले 7 निश्चय की

घोषणा थी । मैं इसके पहले भी कह रहा था कि बिहार की यह पहली महागठबंधन की सरकार होगी जिसने चुनाव के पहले किए गए घोषणा को बारह महीनों के अंदर सरजमीन पर उतारने का काम किया है । बिहार का पहली महागठबंधन की सरकार होगी। 7 निश्चय में लोहिया स्वच्छता मीशन के तहत हर घर शौचालय का निर्माण, सामुदायिक शौचयालय का निर्माण , ठोस कचरा प्रबंधन सूचना क्षमता वृद्धि अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है । महोदय, नगर विकास में 7 लाख 52 हजार 863 परिवारों को 2019 तक शौचालय उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है जिसमें राज्य सरकार प्रति परिवार 12 हजार रुपया अनुदान उपलब्ध करा रही है । शहरी क्षेत्रों में ही नहीं इस योजना का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ा है । आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी अनुदान मांग है महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का जिम्मा है और मैं यह आपके माध्यम से विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रतिकूल असर आम लोगों पर पड़ा है और एक दूसरी जागृति आने का काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि स्वच्छता में यह क्रांतिकारी कदम होगा । अबतक शहरी क्षेत्रों में 55258 व्यक्ति का शौचालय निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 96703 इकाई निर्माणाधीन है । माननीय मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पॉच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में कुल 89 नगर निकायों में शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । हमारे विपक्ष के साथी बोलते रहते हैं । स्मार्ट सिटी की बात आयी, स्मार्ट सिटी के लिए राज्य सरकार ने चयनित करके मुजफ्फरपुर और भागलपुर को भेजने का काम किया है और उसकी स्वीकृति मिल गयी है । पॉच वर्षों तक प्रति वर्ष केन्द्र की सरकार 100 करोड़ रुपया और राज्य सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी इन जिलों को जाती रहेगी । उसी तरह बिहार शरीफ को भी स्मार्ट सिटी योजना के प्रक्रिया में बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर शहर का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है । भागलपुर शहर का चयन कर लिया गया है । माफ करेंगे । चयनित प्रत्येक शहर को केन्द्र स रकार द्वारा 100 करोड़ एवं राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ पॉच वर्षों तक दिया जाना है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य अब एक मिनट आपका समय है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : मैं महोदय, पुनः एक उपलब्धि और ..

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): अपने क्षेत्र की भी कुछ समस्या रखिये ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : हमलोगों के क्षेत्र में कुछ समस्या ही नहीं है । 7 निश्चय जो लागू हो गया तब कही कुछ समस्या रह गयी है । कहीं कोई समस्या नहीं है महोदय, खाली हमारे विपक्ष के साथी सदन को दिग्भ्रमित करते रहते हैं । कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या

नहीं है । हॉ, एक समस्या जरुर है महोदय , वह समस्या यह है कि हमारे विपक्ष के साथी गंभीरता पूर्वक थोड़ा समझे और जब कटौती प्रस्ताव लाते हैं और सरकार जब बोलने के लिए उत्तर देने लगती है तो आप अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं गंभीरतापूर्वक जब आपकी बात ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, सदन में कोई भी माननीय सदस्य बिना गंभीरता के नहीं बैठते हैं । यह कमेंट मत पास कीजिये व्यक्तिगत । समाप्त कीजिये अपना भाषण ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : आप गंभीरतापूर्वक सरकार की बातों को सुने और मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि आने वाले समय में विगत चार वर्षों में जो 7 निश्चय अनेक विभागों के माध्यम से जो बिहार की सरजमीन पर उतारा गया है वह निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति माननीय सभापति महोदय, आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जयहिंद , जय बिहार ।

टर्न-14/25.3.2017/बिपिन

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा । दस मिनट ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, आज आपने सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तीव्र गति से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है जिसका श्रेय इनके दूरदर्शितापूर्ण और जनहितकारी नीतियों को जाता है ।

मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिहार के विकास के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए सात निश्चय को माध्यम बनाया है । सात निश्चय राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ इसे देश के एक विकसित राज्य के श्रेणी में लायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा गॉवों में निवास करती है । वगैर ग्रामीण एवं शहर के विकास के प्रदेश और राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण एवं शहर के जीवन को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए इन निश्चयों के माध्यम से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरूआत की है जो आने वाले पॉच वर्षों में हमारे राज्य की

तस्वीर और तकदीर बदलने का माद्दा रखती है । इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि गॉंव के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के विकास के लिए भी बराबर की तवज्जो देने का कार्य किया है । प्रत्येक घर में स्वच्छ जलापूर्त्ति हेतु घर-घर नल, गॉंव एवं शहर की हर गलियों में सड़क और नाला का निर्माण, 24 घंटे बिजली आपूर्त्ति, स्वच्छता के लिए शौचालय का निर्माण जैसी अनेकों योजनाएं हैं जो ग्रामीण एवं शहरी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्त्तन का वाहक बनेगा और हमारे प्रदेश को पिछड़े प्रदेश की उपमाओं से निजात भी दिलायेगा ।

ग्रामीण विकास के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरों के विकास के लिए समान योजनाओं की शुरूआत की है जो शहर और गॉंव के बीच की खाई को पाटने का काम करेगी । इस योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को स्वच्छ जलापूत्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम चरण की योजना के लिए 290 करोड़ एवं द्वितीय चरण की योजना के लिए 310 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है । प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ है तथा द्वितीय चरण का टेंडर अप्रैल 2017 में होने जा रहा है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं ।

सदन में स्मार्ट सिटी की चर्चा बहुत होती है, भाजपा के नेता इस स्मार्ट सिटी का श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के लिए पूरे देश के कई शहरों के बीच स्पर्धा हुई, जो शहर स्मार्ट सिटी के मापदण्डों पर खरा उतरा, उसी का चयन हुआ । माननीय मुख्यमंत्री के सतत् प्रयास और निजी पहल पर अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी की तमाम शर्त्तों को पूरा किया, तब जाकर भागलपुर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ । ऐसे में इसका श्रेय भाजपा या केन्द्र सरकार को नहीं जाकर, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार को जाता है । इसके लिए स्थानीय विधायक की हैसियत से भागलपुर की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । आने वाले वर्षों में आपके निर्देशन में भागलपुर देश के अग्रणी शहरों में शुमार होगा । ऐसे में स्मार्ट सिटी केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई उपहार नहीं है बल्कि राज्य सरकार ने इसकी सारी शर्त्तें पूरी कर हासिल किया है । साथ-ही-साथ बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संगठन संवर्द्धन द्वारा लगातार किए गए संस्थागत सुधार जैसे- ई-म्यूनिसिपैलिटी, ऑनलाइन प्रोपर्टी टैक्स आदि जिसके कारण निगम के आंतरिक संसाधन में लगातार वृद्धि हुई तथा निगम में विभिन्न जनसुविधाओं का कम्प्यूटरीकरण हुआ । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित स्व्च्छता अनुदान योजना जिसके तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अभूतपूर्व सुधार हुआ । राज्य सरकार द्वारा गैर-योजना मद में पर्याप्त आवंटन जिससे स्थापना संबंधी भुगतान नियमित हुए । शौचालय निर्माण योजनान्तर्गत राज्य सरकार का प्रति युनिट 8000/- का अंशदान, केन्द्रीय भाग का दूना, जिससे स्वच्छता कार्यों में तेजी आई । राज्य सरकार द्वारा

नगरपालिकाओं को पर्याप्त कार्य एवं दायित्व डेलिगेट किया जाना, जिससे नगरपालिकाओं के कार्यकलापों में मजबूती आई, जमीन स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से कार्य निष्पादन हुआ। परिणामत: विभिन्न मानकों पर भागलपुर शहर राष्ट्र स्तर पर मान्य मानदण्डों पर मजबूती से उभरा । इसकी तैयारी के मद में राज्य सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए भागलपुर नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कुल 58,10,55,437.00 रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी माननीय सभापति महोदय, लेकिन हमें खेद है कि भागलपुर में जलापूर्त्ति और इसकी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जिस संवेदक पैन इंडिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है उसके कार्य की धीमी गति और लचर रवैया हमारी योजनाओं पर तुषारापात कर सकती है । इस कम्पनी को ही भागलपुर में जलापूर्त्ति हेतु कुल 470 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने एवं कुल 19 ओवर हेड वाटर टैंक का निर्माण करना है, लेकिन विगत् दो वर्षों के अंदर यह कंपनी अब तक महज 11 कि.मी. तक ही पाईप लाईन बिछा पाई है जो उनके कार्य की गति को दर्शाता है । यह कंपनी वहॉ जल संग्रह के लिए बने चार टैंकों का भी सफाई नहीं कर पायी है जिसकी वजह से भागलपुर शहर के वासियों को गंदे जल की आपूर्त्ति की जा रही है ।

महोदय, आपको विदित होगा कि प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में गंगा के जलस्तर में कमी की वजह से जल संग्रह संयंत्र तक पर्याप्त पानी नहीं पहुॅंच पाता है । कम्पनी को गंगा की मुख्य धारा से पानी लाकर जलापूर्त्ति की मुकम्मल व्यवस्था करने की आवश्यकता है लेकिन मुख्य धारा से चैनल बनाकर संयंत्र तक पानी लाने के कम में लापरवाही की वजह से लोगों को दूषित जल की आपूर्त्ति होती है ।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूॅंगा कि पैन इण्डिया को आदेश निर्गत करें कि वह मुख्य धारा से जलापूर्त्ति हेतु फ्लोटिंग इंजेक्ट उपकरण का इस्तेमाल करे । साथ-ही-साथ बरारी पुल घाट से इंटकवेल तक ड्रेजिंग कर पानी को मुख्य धारा से संयंत्र तक पहुॅंचाया जाए जिससे पर्याप्त जलापूर्त्ति के साथ शहर के लोगों को स्वच्छ जल की भी आपूर्त्ति हो सके । ज्ञातव्य हो कि भागलपुर शहर में वर्ष 1860 ई0 में ही जलापूर्त्ति के लिए पाइप लाईन बिछाई गयी थी जो अब तक पूरी तरह जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है । कम्पनी इसकी भी मरम्मति नहीं कर पा रही है जो उनकी संविदा के शर्त्तों में भी शामिल है जिस वजह से आम लोगों को नालों का पानी फटे हुए पाईपों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है जबकि इसके लिए मात्र संवेदक पैन इंडिया कंपनी ही पूरी तरह जिम्मेदार है ।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा संवेदक कंपनी को तय सीमा के अंतर्गत अपना कार्य पूरा करने हेतु सख्त रूप से निदेशित किया जाय जिससे भागलपुर शहर के हर घर तक नल पहुॅंचाया जा सके जिसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री ने बार-बार सदन और

सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है । मेरा विश्वास है कि सरकार इस समस्या पर त्वरित संज्ञान लेकर कंपनी के लचर रवैये पर अंकुश लगाएगी ताकि घर-घर नल जैसी सरकार की संकल्पना को मूर्त्त रूप दिया जा सके । माननीय मंत्री जी ने कई बार सदन में प्रश्न के जवाब में कहा है कि सड़क एवं नाला बनाने के लिए नगर निगम के स्थाई समिति यानि निगम पार्षद के द्वारा योजना पारित होने के उपरान्त ही आवंटन दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर निगम के पार्षद अपने वार्ड में किसी कारणवश कार्य नहीं कराना चाहते हैं तो उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाएगा । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि वहाँ उस क्षेत्र के जो विधायक हों उनकी अनुशंसा लेकर भी सड़क एवं नाला को बनवाने का कार्य करना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय क्षेत्र की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी का अधिकार नगर निगम को निहित है । पूर्व में नगरपालिका एवं नगर निगम में स्थानीय विधायक पदेन सदस्य होते थे । मौजूदा प्रावधानों में स्थानीय विधायक का प्रतिनिधित्व नहीं है । इसके लिए आवश्यकतानुसार नगर निगम ऐक्ट में संशोधन किया जाए या सरकार अधिसूचना के माध्यम से विधायकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करे । नगर निगम की स्थाई समिति, सामान्य बोर्ड एवं अन्य निर्णायक समितियों में वोटिंग राईट के साथ प्रतिनिधित्व दिया जाए । सात निश्चय में नगर निगम को ही सड़क नाला इत्यादि के निमार्ण की जिम्मेदारी दी गई है । ऐसे में विधायक की कोई सहभागिता नहीं होने की वजह से विकास कार्यों में विधायक की उपेक्षा होती है । स्थानीय विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं को नगर निगम में कार्यान्वित किये जाने का भी प्रावधान किया जाय। इसके अभाव में जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण में विधायक असमर्थ हो जाते हैं जिसका सीधा असर विकास योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन पर पड़ता है । मैं माननीय नगर विकास मंत्री के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि जब से उन्होंने विभाग का प्रभार ग्रहण किया है उस समय से राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के विकास योजनाओं में गति आई है ....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

टर्नः 15/कृष्ण/25.03.2017

श्री अजीत शर्मा : एक मिनट में बोल कर समाप्त करते हैं । जो पदाधिकारी, कर्मचारी नगर निगम में नौकरी पाते हैं, वे वहीं से रीटायर करते हैं । इसलिए उनको एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में स्थानान्तरण जबतक नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा । अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा जिस की वजह से अपराध में कमी आने के साथ-साथ राज्य का

सम्मान पूरी तरह दुनिया में बढ़ा है । इस के लिये राज्य की भावी पीढ़ी माननीय मुख्यमंत्री के प्रति शुक्रगुजार रहेगी । धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : भाजपा, माननीय सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद । आप का समय 6 मिनट है ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : सभापति महोदय, नगर विकास विभाग के अनुदान मांग के विरूद्ध जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है, मैं उस के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, नगरों का विकास उस प्रांत या देश की संपन्नता का प्रतीक है । नगरों के मौलिक आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं के विकास राज्य के आर्थिक विकास में महती भूमिका अदा करती है । शहरी आर्थिक व्यवस्था को गतिशील बनाकर समेकित रूप से राज्य में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिकि परिवर्त्तन का कारण बनती है । साथ ही स्वस्थ्य मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है । महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन 11 नगर निगम, 42 नगर पर्षद् और 86 नगर पंचायत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित कर एवं शहरों को सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूल रूप से सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग को है । बिहार सरकार की नगर विकास एवं आवास विभाग पूर्ण रूप से उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने में संपूर्ण रूप से विफल रही है । महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के निम्नलिखित प्राथमिकतायें हैं :

पहला, जलापूर्त्ति । इस जलापूर्त्ति के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की मदद से जल मीनार, हर नगर परिषद् नगर पंचायत और नगर निगमों में अवस्थित है । लेकिन बिहार सरकार ने नगर निगम को को छोड़कर नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के अन्तर्गत जितने भी जल मीनार लगे हुये हैं, उस के संचालन की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, जिस का परिणाम है कि वे बेकार पड़े हुये हैं और नगर में बसनेवाले लोगों को शुद्ध जल की आपूर्त्ति नहीं हो पा रही है । गिनती से ये गिना सकते हैं कि इतने जल मीनार लगाये गये, इतना किलोमीटर पाईप लाईन बिछा दिया गया । लेकिन वास्तविकता यह है कि जितने भी इनके पाईप लाईन बिछाये गये हैं, सब में रिसाव होता है । जब भी पम्प स्टार्ट किया जाता है, सब जगह से लीकेज होने लगता है और अंत में उस मशीन को बंद कर देना पड़ता है । इसलिए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की त्रुटियों को दूर करें और हर जल मीनार के लिये एक ऑपरेटर और एक मेठ की बहाली निश्चित रूप से करें, पाईप लाईन का सुधार करें और सात निश्चय में मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, उस के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में शुद्ध जल पहुंचाने की व्यवस्था करे ।

दूसरा, इन का काम है नाले का निर्माण करना । महोदय, मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पूरे बिहार में नाला तभी सफल हो सकता है जब उस शहर का नगर विकास विभाग के पास कंटूर उपलब्ध हो या नगरपालिकाओं के पास उपलब्ध हो । किस तरफ से किधर पानी जायेगा, किधर जमीन ढाल है, उस दिशा में कंटूर मैप के द्वारा उस को सुनिश्चित किया जा सकता है कि नाला इस रास्त से जायेगा और फलां स्थान पर गिरेगा । महोदय, यह कंटूर मैप इन के पास कहीं नहीं है । नाले बनते हैं केवल कमाई करने के लिये । नाले का आप एस्टीमेट देखेंगे 4 फीट गहरा, जबकि ऊचाई से ढलान की ओर धीरे-धीरे गहराई बढ़ानी चाहिए । यह प्रारंभ से ले कर के अंत तक नाले की गहराई 4 फीट रखते हैं । इसलिये रखते हैं कि इस में अधिक खर्च होगा, एस्टीमेट बढ़ेगा, इसमें ज्यादा कमाई होगी, 4 नंबर के इंटे लग जायेंगे, खप जायेंगे, इसके लिये काम होता है । महोदय, मैं इस को नगरपालिकाओं में देखता रहा हूं क्योंकि मैं नगर क्षेत्र से ही आता हूं । इसलिये इसका हमको अनुभव है ।

तीसरा, इनको नागरिक सुविधा प्रदान करना है । तालाब, नदी, घाट का निर्माण एवं जिर्णोद्धार, पार्क निर्माण, लाईट की व्यवस्था इनको करनी है । महोदय, ये तालाब, नदी, घाट का जिर्णोद्धार मैं समझता हूं कि कहीं भी हुआ नहीं है । इस में बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं । जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना था, उसमें अधिक पैसे मिलते थे, जनसंख्या के आधार पर पैसे का आवंटन होता था, इसलिए जितने भी नगर परिषद् हैं, उन को पैसा मिल जाता था कि लंबे-लंबे काम को, अधिक खर्च होनेवाले काम को वे करा सकें । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नगर विकास और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास दोनों पर विधायकों की अनुशंसा से काम होता था, उस काम को इस बिहार सरकार ने रोक लगा दिया और बड़े-बड़े काम नगरपालिकाओं के अंदर होने बंद हो चुके हैं । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत ...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : बस, मैं खत्म करता हूं । इस विधान सभा में मुख्यमंत्री नगर विकास पर प्रश्न आया था और इस विधान सभा के अंदर तय हुआ था कि जितनी योजनायें पहले स्वीकृत हो चुकी है, उस का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के पैसे से कराया जायेगा । लेकिन विडम्बना यह है कि मुख्यमंत्री नगर विकास का जितना पैसा था उन सारे पैसे को सरकार ने पाई-पाई वापस कर लिया और जो काम बाकी रह गया, वह जैसे के तैसे पड़ा हुआ है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन पैसों को पहले लौटाया जाये और जो विधान सभा में तय हुआ था...

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : राष्ट्रीय जनता दल मा0स0 श्री महेश्वर प्रसाद यादव । आप का समय 10 मिनट है ।

टर्न-16/राजेश/25.3.17

श्री महेश्वर प्रसाद यादवः माननीय सभापति महोदय, पटना में रहा हुआ व्यक्ति अगर कुछ दिनों के बाद पटना आया होगा, तो उन्हें पटना को देखकर इतनी खुशी हुई होगी, जिसका वर्णन नहीं है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा से जो आज पटना का चमक है, वह पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी से या देश की राजधानी से जरा भी कम नहीं है, जहॉ भी आप जाइये, चारों तरफ पटना आज चमक रहा है, जब पटना चमक रहा है, तो हमारे प्रदेश का एक-एक शहर चमक रहा है, बिहार चमक रहा है, इसलिए मैं अपने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री अरुण बाबू को कहूंगा कि जिस विधान सभा में आप बैठे हुए हैं, यह विधान सभा पूरे देश में इस दर्जे का नही है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आपने 10 रुपये की कटौती का जो प्रस्ताव किया है, उसको आप वापस ले लीजिये ।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्राधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद् एवं 87 नगर पंचायत हैं, इन्हें राष्ट्रीय मानक के रुप में विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाऍ उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । महोदय, राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में बासित परिवारों को पक्की नाली, गली से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली, गली, निश्चय योजना का आरंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पॉच वर्षों में शहरी क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की नाली, गली से जोड़ने का लक्ष्य है, उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल दो वर्षों की देनदारी सहित कुल 190 करोड़ रुपया मात्र आवंटित कर दिया गया है, जो योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सभी नगर निकायों को विस्तृत दिशा-निदेश दिये गये हैं तथा इनका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है । महोदय, इतना ही नहीं राज्य के शहरी क्षेत्रों में बासित प्रत्येक परिवारों को शुद्द नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पॉच वर्षों में शहरी क्षेत्र में बासित प्रत्येक परिवार तक शुद्द नल का जल पहुंचाया जायेगा । महोदय, पटना शहर के 70 पार्कों के सुव्यवस्थित विकास के दृष्टिकोण से एक नीति बनायी है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसायटी का गठन किया गया है, जो पार्कों का प्रबंधन कर रही है ।

सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने हेतु भागलपुर शहर का चयन कर लिया गया है, इसके लिए एस0पी0भी0 का गठन किया जा चुका है, इसमें दो शहरों बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है एवं पटना शहर का प्रस्ताव भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रत्येक शहर को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा एवं 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा पॉच वर्षों तक दिया जाना है ।

महोदय, नमामी गंगे योजना राज्य के गंगा तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में कार्यान्वित है, इसके अन्तर्गत हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय एवं मुंगेर में ट्रीटमेंट निर्माण का कार्य, सर्वर निर्माण का कार्य किया जा रहा है । महोदय, ये सारी योजनाएँ राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है । महोदय, ये सारी योजनाएँ जो देश को और राज्य को, जो हमारे पूर्खो ने सपना देखा था, गॉधी, लोहिया, जयप्रकाश एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जैसा भारत बनाने का, जैसा बिहार बनाने का, जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज एक महापुरुष बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवतरित हुए हैं, जो उन सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं महोदय ।

महोदय, 7 निश्चय योजना उन्हीं महापुरुषों ने जो सपना देखा था समाज निर्माण का, गॉव के निर्माण का, शहरों के निर्माण का, यह उसी कल्पना की देन है, हर घर में शौचालय बनवाना, जो बन रहा है, हर घर में शौचालय का निर्माण करना, हर घर में तीन नल पहुंचाना, एक खाना बनाने के लिए, एक शौचालय में और एक स्नान करने के लिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही गरीब हो, सब के घर में, जो तीन नल पहुंचाने की योजना है, हर गली को पक्की, हर नाली को, जो पक्की करने की योजना है, महोदय इसकी गूंज न सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज हो रही है और महोदय जो शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, इसकी धमक, इसकी आहट और इसकी गूंज पूरे देश में है और इसकी वजह से पूरा देश आज नीतीश कुमार जी की ओर देख रहा है ।

महोदय, एक तरफ केन्द्र में बैठी हुई सरकार है, जो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ये कहे थे कि 15 लाख रुपया देंगे और 15 पैसा भी किसी के खाते में नहीं गया और दूसरी तरफ यह नीतीश कुमार जी की सरकार है जो कहा, वही किया.............

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): अब आप बैठ जाइये ।

श्री महेश्पर प्रसाद यादव: इसलिए महोदय आने वाले दिनों में जो 2019 का चुनाव होने वाला है, उसमें पूरे देश की जनता ने नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है, अब विकल्प आ गया है देश में ....

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): अब आप बैठ जाइये, अब ओभर हो रहा है, आप अनुभवी साथी हैं, अब आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: महोदय, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, इनको बोरिंग करना था और राज्य की सरकार को मोटर लगाना था लेकिन कहीं भी बोरिंग नहीं हो रहा है सेन्ट्रल की सरकार के द्वारा । महोदय, एक मिनट और सर ।

महोदय, जमुई जिले में पेयजल के लिए बी0पी0ए0 गठबंधन के समय में अनेक जगह पेयजल के लिए भारत सरकार के माध्यम से नवीनगर, बरहट................

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: महोदय, एक मिनट । महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): बाकी ही था आपका सुझाव । समय समाप्त हो गया है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: आधा मिनट सर । महोदय, नगर निकायों में जो चुनाव हो रहा है, उसमें मेयर का जो चुनाव है, वह जो है जनता के डायरेक्ट वोट से होना चाहिए, जनता के डायरेक्ट वोट से चुनाव नहीं होने के कारण वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

टर्न-17/सत्येन्द्र/25-3-17

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्यगण, आप तमाम साथियों के लिए आपने जो उदगार व्यक्त किया पुराने साथी हैं इसमें तो कोई शक नहीं है ये भाजपा के चाहे आपके सारे लोग मानते हैं कि नीतीश जी की हुकूमत में हम बिहार के बिहारी विहारपूर्वक विहार कर रहे हैं उसको कोई रोक ही नहीं सकता है ।

माननीय सदस्य, जद(यू0), श्री चन्द्रसेन प्रसाद । आसन द्वारा लगाये गये ब्रेक पर ध्यान दीजियेगा, 10 मिनट आपका समय है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग पर अनुदान की मांग पर आज सरकार के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए हम खड़ा हुए हैं । महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए हम इस्लामपुर की जनता की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ । महोदय, आज नगर विकास और आवास विभाग पर चर्चा हो रही है, पूर्व के वक्ताओं ने भी चर्चा करने का काम किया है नगर विकास एवं आवास विभाग पर, हमलोग सुनते थे गांव में लोग जब जाते थे तो घर और बगान दालान कुछ अच्छा बना हुआ रहता था और घर की स्थिति जो भी हो महोदय आज हमारे देश के शहरों की जो स्थिति है आज हम बिहार की चर्चा नगर विकास विभाग पर

करना चाहते हैं । महोदय, माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में और माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व नगर विकास विभाग के द्वारा जो परिवर्त्तन हुआ है उस परिवर्त्तन को देश की जनता उसको नाकार नहीं सकती है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जब पहले पटना में लोग आते थे तो लोग जाम में फंस जाते थे, सचिवालय जाना रहता था 10 बजे पहुंचना रहता था 4 बजे महोदय पहुंचते थे । अगर आज हम पटना का आकलन करते हैं तो पटना में जो परिवर्त्तन हुआ है नगर विकास विभाग की ओर से वह काबिलेतारीफ है। पहले एक भी यहां फलाई ओवर नहीं था और आज स्थिति है कि पटना में जहां भी देखिये स्टेशन जाना है तो फलाई ओवर हवाई अड्डा जाना है तो फलाई ओवर, जहां जाना है गांधी मैदान जाना है तो फलाई ओवर सिर्फ फलाई ओवर यह किसका देन है महोदय, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नगर आवास विभाग का यह देन है इसलिए हम श्री नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री जी को और गठबंधन की सरकार को बधाई देना चाहते हैं,बधाई इसीलिए कि पूरे बिहार में..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):चन्द्रसेन जी, कुदरत ने जो आपको आवाज दिया है वह बड़ा ही मधुर है, मध्यम आवाज में बोलेंगे तो बड़ी मीठी होगी कोयल की तरह, ज्यादा स्वर में जाईयेगा तो फट जाता है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, आज पूरे बिहार में जो आवाज गूंजा है विकास के सवाल पर आज पटना जो नगर है आज उस नगर का हम चर्चा करना चाहते हैं, उसके प्रबंधन पर बिहार में बिहार की राजधानी पटना है । महोदय, हमलोग पटना सुनते थे जब छोटे थे तो पटना चलना है, पटना बिहार की राजधानी है और जब पटना आते थे महोदय तो जब इसकी स्थिति देखते थे तो हमें अजब सा महसूस होता है कल की स्थिति और आज की स्थिति हम बताना चाहते हैं विपक्षी भाईयों से कि जो आज की स्थिति है, बिहार में जब हमारे कुछ रिलेटिभ विदेश से आये हुए थे सिंगापुर से, वह पटना पहुंच गये किसी के साथ, कहिन कि हम कहां पहुंचे हैं दिल्ली तब उन्होंने कहा कि नहीं यह पटना है । पटना पहले भी आये थे महोदय, आज पटना विदेशों में रहने वाले सिंगापुर में मलेशिया में जब वहां के लोग आते हैं तो पटना के दृश्य को देखते हैं तो उनका जो मनोबल और जो विशेष विकास के बारे में सोचते हैं तो नीतीश कुमार का याद उनको आ जाता है । महोदय, बिहार में जो महागठबंधन के नेतृत्व में जो सात निश्चय लागू किया है उस निश्चय की ओर हम जाना चाहेंगे । उस निश्चय में आवास विभाग और नगर विकास विभाग में तीन निश्चय है महोदय, हम कहना चाहते हैं चाहे शौचालय का सवाल हो चाहे अन्य सवाल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सात निश्चय में शौचालय को रखा और उसे लागू किया निश्चय के रूप में महोदय, नगर विकास विभाग में भी माननीय मुख्यमंत्री शौचालय योजना को लागू किया गया है । महोदय उस योजना के तहत शहरों में लोगों के सुख सुविधा के लिए सरकार ने शौचालय बनवाने का काम कर

रही है । शौचालय में कई तरह से महोदय व्यक्तिगत भी, समुदायिक भी, सामुहिक भी सरकार ने बदलाव लाया है महोदय कि जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको सामुहिक शौचालय बनाया जायेगा जिनके पास जमीन है व्यक्तिगत बनाया जायेगा यानी कहने का मतलब है महोदय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू और नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में लालू यादव के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन आया है शौचालय के मुद्दे पर वह काबिलेतारीफ है । महोदय, जहां तक शहरों में पेयजल का सवाल है महोदय, शहरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने, डिप्टी सी0एम0 ने जो व्यवस्था किया है कोई घर ऐसा बाकी 2020 तक नहीं रहेगा जहां नल का पानी नहीं पहुंचेगा । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में 2020 तक शहरों में भी पहुंचने का काम करेगा जहां तक पक्की गली नाली का सवाल है सात निश्चय में पक्की गली नाली है और नगर विकास विभाग ने भी माननीय मुख्यमंत्री पक्की गली नाली योजना को शहरों में भी लागू करने का काम किया है और शहरों में चरणद्ध ढंग से उसको करने का काम हो रहा है और 47 कि.मी.पक्की नाली गली योजना बनाया जा चुका है। महोदय इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को हम बधाई देना चाहेंगे महोदय हम कहना चाहते हैं किसके प्रयास से जो परिवर्त्तन आया है नगर विकास में पटना में जो आया है प्रकाश पर्व यहां मनाया गया गुरू गोबिन्द सिंह जी के जयंती पर पटना जो ऐतिहासिक यह जयंती जो मनाया गया दुनिया के जनता उसको देखने का काम किया है। यह नगर विकास का देन हैं, यहां पर सुख सुविधा के लिए 150 बसें इस पटना के अन्दर चलाई गई और बिना भाड़े के महोदय यह किसका देन है महोदय, यह नगर विकास का देन है महोदय और बिहार में इसकी चर्चा ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो पटना में आये थे इस पर्व में सिरकत करने के लिए उनको जो सुविधा मिला उस सुविधा में उन्होंने जो देखा वे काबिलेतारीफ है महोदय, अन्य जो सुविधाएं शहरों को दी जा रही है महोदय उन सुविधाओं में पटना को जो मेट्रो रेलवे देने का प्रोग्राम है बिहार सरकार ने जो इसका प्रोजेक्ट तैयार कर के केन्द्र को भिजवाने का काम किया लेकिन केन्द्र की सरकार अगर झारखंड का होता तो तुरंत भेजने का काम करता लेकिन बिहार का जो प्रोजेक्ट जो योजना है, दिल्ली में फाईल पड़ा हुआ है महोदय, हम तो इस विभाग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सेन्ट्रल में जो पड़ा हुआ मेट्रो रेलवे का फाईल है उसको अबिलम्ब उसको जो है अनुमति देने का काम करेंगे और जहां तक सुझाव का सवाल है महोदय पूरे बिहार में नगर विकास विभाग चाहे वह मेरे क्षेत्र का सवाल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देंगे । उन्होंने इस्लामपुर के नगर पंचायत को नगर परिषद में बदलने का जो काम किये हैं हम अपने क्षेत्र की जनता की ओर से इनको बधाई देते हैं और एक बार फिर हम इस विभाग के प्रति और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) भारतीय जनता पार्टी, माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया ।
6 मिनट।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय, माननीय श्री अरूण सिन्हा जी द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय, नगर विकास की चर्चा लगातार माननीय सदस्य कर रहे हैं और अच्छाईयों की जो चर्चा कर रहे हैं, यह समझने का है और यहां पर जो लोग सदन के माध्यम से जान रहे हैं कि जो अच्छाईयों का व्याख्यान कर रहे हैं वह जब हमलोग सम्मिलित थे उसी समय का ही व्याख्यान कर रहे हैं । वर्त्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे आवासीय की दृष्टि से भी और नीचे की इकाई कैसे मजबूत हो, इस सरकार को केन्द्र सरकार की योजनाओं की दृष्टि से जिन राशियों का आवंटन किया गया पर वास्तव में कहीं न कहीं दृष्टि की जो दृष्टिदोष है जो स्वाभाविक रूप से एक वृतांत एक स्वरूप से शहरों का जो विकास होना चाहिए था यह शायद वर्त्तमान के सरकार में दिखलाई नहीं दे रहा है (क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/25.03.2017

...क्रमशः...

श्री संजीव चौरसिया : उसी का परिणाम और परिणति है कि करने का विचार शायद रखते हों पर जब फायनेंशियल मैटर इसमें ध्यान दौड़ाते हैं तो बातें ध्यान में आती हैं कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो 18 दिसम्बर को 2100 करोड़ राशि निर्गत किया गया है, वह भी अभी तक वर्त्तमान की सरकार में लगभग नहीं के बराबर खर्च करने की स्थिति में है ।

निचले निकायों की जब बात करते हैं तो निचले निकायों की अलग-अलग प्रकार से सात निश्चय का जो चोला सरकार ने पहन रखा है और जगह-जगह सड़क, नाली-गली, पक्कीरण सब विषय पर चर्चा, अच्छी-अच्छी चर्चाएँ होती हैं पर जमीनी हकीकत यह है कि नीचे के स्तर पर क्रियान्वयन की जब बात करते हैं तो क्रियान्वयन का आधार कहीं दिखता नहीं है । जब सड़कों की बात करते हैं तो वार्डों को जो शुद्धिकरण करने की बात है, वार्डों को जो राशि मुहैया कराने की बात है, अगर देखते हैं तो वह भी निर्गत नहीं है । जब नली की बात करते हैं, हर घर को नल का जल की बात करते हैं तो कौन-सा है, बैठकों में जब जाते हैं, जब उसमें समीक्षा बैठक होती है, उसमें बात ध्यान में आती है कि अभी तक योजना का प्रारंभ भी नहीं हुआ है तो कौन-सी बात करेंगे ? आप पाँच वर्षों में जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो शायद एक वर्ष में अबतक प्रारंभ करने की स्थिति में भी नहीं बन पाये हैं । कहीं न कहीं पूरा योजना का अभाव, दृष्टि का अभाव दिख रहा है कि अच्छी-अच्छी योजना कागजों में, फाईल में निर्माण हो जा रही है, बातें बन जा रही हैं पर नीचे एक्जीक्यूशन में कोई प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, नीचे एक्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है ।

आज ये बातें हुई कि स्वच्छता की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि लेकर, संकल्प लेकर देश भर में जो बनाने की बात की, अगर सबसे निचले पायदान पर हैं तो बिहार खड़ा है । स्वच्छता की दृष्टि पर शौचालय के निर्माण की प्रक्रिया में यह साक्ष्य बोलता है कि शौचालय के निर्माण की दृष्टि से नहीं बन पाया है । कहीं न कहीं व्यवधान और प्रावधान सब दिखाई दे रहा है । आप प्रावधानों की तो बात करते हैं, व्यवधानों की भी बात करनी चाहिये आपको कि व्यवधान ही व्यवधान दिखाई दे रहा है, संकल्प शक्ति में पूरी तरह से व्यवधान दिखाई दे रहा है । आप ही के द्वारा यह कि 22 प्रतिशत की कमी पूरी योजना आकार की दृष्टि से किया गया है ।

नगरपालिका का सबसे पहला अगर योजना की दृष्टि से बनता है तो नगरपालिका के शुद्धिकरण की योजना बनती है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति ।

श्री संजीव चौरसिया : क्या इस बात का द्योतक नहीं है कि नगरपालिका के क्षेत्र में जब नजर दौड़ायेंगे, दृष्टि दौड़ायेंगे तो नगरपालिका की स्थिति क्या है, पूरे बिहार की दृष्टि से, जितने नगरपालिका हैं उनकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, उनकी योजना के आकार का दृष्टिकोण क्या है, तो शायद अपने आप का जब नब्ज टटोलेंगे तो उन स्थितियों का जायजा लेने पर निश्चित तौर पर स्थिति साफ हो पायेगी ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी को तय करना चाहिये कि अलग-अलग प्रकार की समस्याओं के लिये, जल जमाव की स्थितियाँ बनती है कि पटना में जब आते हैं तो शायद कहीं न कहीं पूरा अभाव दिखाई देता है कि जल जमाव की समस्या पूरी तरह से परिलक्षित होती है । कहीं न कहीं लेवेलिंग की दृष्टि से जो कमिटी बननी चाहिये अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिये, सड़कों के निर्माण के लिये जो लेवेल तय होना चाहिये वह नहीं तय होने के कारण, अलग-अलग विभागों के अलग-अलग स्तर पर जो लेवेल तय होते हैं उसी का परिणाम और परिणति होता है कि बनने के लिये तो सड़कें बन जाती हैं पर कहीं न कहीं जल जमाव हो जाता है, कहीं न कहीं घाटा निश्चित तौर पर हो जाता है । आज पटना की दृष्टि से जब देखेंगे तो भाग कर दें पूरब और पश्चिम में, उसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण को बॉटते हैं तो गंगा के किनारे का पूरा दीघा का बेल्ट है, वहॉ जल जमाव अपने आप में दिखाई देता है कि समस्या का प्रकार अलग है । वहीं अनीसाबाद बाइपास की बात करते हैं तो बादशाह पईन के निर्माण से लेकर गहरीकरण, चौड़ीकरण होना चाहिये, वह नहीं हो पाया है, उसी का परिणाम दिखाई देता है कि लम्बे समय तक जल जमाव रहता है, बड़ा क्षेत्र है सरिस्ताबाद, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, जो पुराना क्षेत्र है जहॉ पूरी तरह से दिखाई देता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : Positive comment, I too like.

श्री संजीव चौरसिया : सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि शहरीकरण के लिये आवास की दृष्टि से जब हम चाहते हैं तो इस चीज का निर्माण होना चाहिये कि स्लम एरिया का निर्माण, जो स्लम नीति बनी थी एन0डी0ए0 के कार्यकाल में, उस स्लम नीति का पालन नहीं हो पा रहा है । अगर बड़े लोगों को, अमीरों को जीने का हक है तो गरीबों को भी जीने का हक है । माननीय मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, अपने पीछे जब झांकते होंगे तो बड़ा स्लम एरिया उनके पीछे आबादी की दृष्टि से वहाँ व्याप्त है, तो उनको भी जीने का हक है और पुनर्वास की बात करते हैं कि लम्बे समय से झोपड़ियाँ कबाड़ी जाती हैं, झोपड़ियाँ हटाई जाती हैं तो उनके पुनर्वास की बात कौन करेगा ? यहाँ प्रावधान है कि उनके पुनर्वास की बात हमें करनी चाहिये । मैं माँग करता हूँ कि पुनर्वास की योजना लागू करनी चाहिये । महोदय, रेल की परियोजना जब प्रारंभ हुई उत्तर बिहार के पूरे कनेक्टिविटी के लिये जिस बिंद टोली ने त्याग किया है, उस बिंद टोली का अभी तक पर्चा नहीं मिला है, वह मालिकाना हक की खोज अभी तक जारी रखे हुये है । ऐसे-ऐसे मालिकाना हक के लिये पूरे पटना में शहजादी मस्जिद से लेकर, कमला नेहरू नगर से लेकर, कौशल नगर से लेकर बड़ी आबादी चारो तरफ है, सभी जितने माननीय मंत्री हैं, माननीय सदस्य जितने लोग यहाँ बैठते हैं, जब पीछे ताकते होंगे तो उस स्लम एरिया में शौचालय का अभाव है, पानी का अभाव है । उनके बारे में निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर उनके बारे में विचार करना चाहिये । उनके वेंडिंग जोन के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, सड़कों पर जो रोजगार सृजन का अधिकार जो वेन्डर ऐक्ट के तहत दिये गये हैं, उसके लिये भी हमको योजना निश्चित तौर पर पारित करना चाहिये, उस ऐक्ट को लागू करके पटना में रोजगार के सृजन के लिये सड़कों के द्वारा माननीय मंत्री जी को उसकी ओर दृष्टिकोण आगे करने की बात के लिये मैं आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पर करना चाहिये । बड़े-बड़े सभी योजनाओं को सफलीभूत करते हुये अगर पटना की बात करेंगे तो श्रम की सबसे बड़ी आवश्यकता है, नीतियों का पालन करते हुये आगे बढ़ाने की बात हमको करनी चाहिये । पटना हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, सभी स्थानों पर समान समस्या है कि एक आधार के एक वर्गीकरण का हैव एण्ड हैव नॉट्स का जो अंतर है, उसको दूर करके उनके भी मौलिक अधिकार को, हम उनक भी जीने की बात निश्चित तौर पर करें । आज पटना के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं, सिविल सर्जन का ऑफिस है, वहाँ पर गर्दनीबाग को कूड़े के अम्बार को लेकर कितनी बार हमलोगों ने धरना दिया और हमने कहा कि कूड़ों का अम्बार लगाकर स्मार्ट सिटी की राह देखना चाहती है वर्त्तमान सरकार, कूड़ों के अम्बार से फिर से डंपिंग यार्ड वहाँ पर प्रारंभ कर दिये हैं । आज पटना शहर में आप इंटर करियेगा तो कूड़े से स्वागत होता है । यह

कौन-सा पटना शहर हो गया है जहाँ वैभव की बात करते हैं, वहाँ के कूड़ों के अम्बार के साथ डंपिंग यार्ड शहर के बीच में बनाया जाता है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य ललन पासवान जी, आपका बोलने के समय 2 मिनट में से 1 मिनट कट जायेगा ।

श्री संजीव चौरसिया : कूड़ों के अम्बार की बात करते हैं कि आज पटना को किस ओर हम ले जा रहे हैं । पटना की ओर पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र अगर देखना चाहता है तो पटना की सफाई, पटना के मौलिक अधिकार, पटना में मेडिकल फैसिलिटी हो । पटना में जो वेस्टेज डिसपोजल सिस्टम है, बायो-वेस्टेज पर वर्त्तमान सरकार कोई विचार नहीं कर रही है । उसपर विचार करना चाहिये कि डंपिंग यार्ड बंदकर उसके वेस्टेज मेटेरियल के लिये कुछ योजना बननी चाहिये । वर्त्तमान सरकार से मैं माँग करता हूँ कि यह सब करने की आवश्यकता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री संजीव चौरसिया : बहु प्रकार से विचार करेंगे तो पटना की ओर दृष्टिकोण जायेगा जो पूरे देश को परिलक्षित करता है देश की राजधानी, अगर देश की राजधानी के विकास को परिलक्षित करने की बात करते हैं तो समेकित योजना के साथ आगे बढ़ने का काम करना चाहिये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य जनाब अख्तरूल इस्लाम शाहीन को आमंत्रित करता हूँ । आपका समय 9 मिनट है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हुजूर, जब नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहते हैं तो कितना अनुशासित तरीके से सदन चलता है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, आज मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के माँग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । राज्य के आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है । गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था, समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्त्तन का कारण बनती है । साथ ही, राज्य के मानव विकास संसाधन में अभिवृद्धि करती है ।

वैसे तो जिस दल से हम आते हैं, हमारी सोच है कि नगरों के साथ-साथ गाँव का भी ऐसा विकास हो ताकि लोग नगर की तरफ न जाकर बल्कि अपने गाँव का ही विकास किया जाय, गाँव को ही शहर बनाया जाय, इस विचारधारा के साथ हमलोग काम करते हैं ।

सभापति महोदय, बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत जो क्षेत्राधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद् और 87 नगर पंचायत हैं, उसको राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने और उनके लिये राज्य सरकार लगातार सुविधा उपलब्ध कराने

के लिये प्रयत्नशील है । चाहे पेयजल का मामला हो, लगातार बिहार के तमाम जगहों पर पेय जलापूर्त्ति की योजना चल रही है और अमृत मिशन योजना के तहत 14 निकायों में, पाईप जलापूर्त्ति योजना के तहत 32 निकायों में और राज्य योजना अन्तर्गत 18 नगर निकायों का डी0पी0आर0 बन गया है । भागलपुर और गया में 500 करोड़ रूपये की लागत से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और राज्य सरकार ने सात निश्चय के माध्यम से अभी 713 करोड़ का स्वीकृति दिया है ताकि 290 वार्ड में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके ।

...क्रमशः ....

टर्न-19/आजाद/25.03.2017

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : (क्रमशः) उसी तरह मुख्यमंत्री गली-नली योजना के तहत 190 करोड़ रू0 की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, जिसके तहत 140 नगर निकायों में जो टोले गांव के अन्दर बसते हैं, जो बसावट गांव के अन्दर बसते हैं, उनको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, गली-नली को जोड़ने के लिए 190 करोड़ रू0 स्वीकृत किया गया है। साथ ही अभी भी शहर में शौचालय के लिए लोग बाहर जाते हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार ने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4हजार रू0 की राशि देने का प्रावधान किया गया है, उससे काम चलना नहीं था तो बिहार सरकार 8हजार रू0 प्रत्येक परिवार को देने का निर्णय लिया है और 12हजार रू0 दिया जा रहा है । इसके तहत 55हजार शौचालय का निर्माण कर लिया गया है और 95हजार निर्माणाधीन है । आने वाले 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक शौचालय बनाने की योजना है । 39 बसस्टैंड का काम चल रहा है, जिसमें 10 पूर्ण कर लिया गया है और बाकी काम प्रगतिशील है और 381 करोड़ का इन्टरनेशनल बस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, जो 2018 में पूरा कर लिया जायेगा । शहरों के विकास के लिए नगर भवन की आवश्यकता होती है, उसके लिए 50 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को उपलब्ध करा दी गई है और बड़े पैमाने पर 50 नगर निकायों में इस भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है । विद्युत शवदाहगृह का भी पटना सहित, वैशाली सहित कई जगह जीर्णोद्धार किया गया है । यहां तक की जानवरों के मर जाने से प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है, उसके लिए भी विद्युत शवदाहगृह का निर्माण कराया गया है । इलेक्ट्रोनिक लाईट ट्राफिक की 100 जगह पूरे बिहार में व्यवस्था की गई है, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा करने की सरकार की योजना है । सरकार ने

पटना में आवागमन सुलभ बनाने के लिए मेट्रो ट्रेन की परिकल्पना की है, इसके लिए 31 कि0मी0 शहर में एक योजना बनाकर 16हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है । मुझे लगता है कि पटना शहर और विभिन्न शहरों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समर्थन मिलता है और यहां की जनता को आवागमन सुलभ के लिए मेट्रो ट्रेन के लिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार इसको स्वीकृति दे ताकि पूरे बिहार की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ताकि बिहार का बड़ा विकास हो सके ।

सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी लगातार बता रहे थे कि नगर विकास विभाग अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाया है । निश्चित रूप से साल दो साल में कोई बड़ा कारनामा नहीं किया जा सकता है । पिछले 7 साल से इस सदन में हूँ और मैंने भी देखा है कि विभाग के मंत्री कभी सुशील मोदी हुआ करते थे, कभी चौबे जी हुआ करते थे, कभी विपक्ष के नेता प्रेम कुमार हुआ करते थे, हम भी सदन में अपनी समस्याओं को रखने का काम करते थे, लेकिन उतनी तवज्जो से नहीं सुना जाता था । आज जिस तरह से आदरणीय महेश्वर हजारी जी के नेतृत्व में जो नगर विकास का काम हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरे शहर का विकास हो रहा है । निश्चित रूप से यह कार्य बहुत सराहनीय है । अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है कि शहर में 3 एकड़ जमीन का हस्तानान्तरण करने के लिए कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके लिए जिला पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है, निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है । गुरू गोविन्द सिंह महाराज जी के 350वें जयन्ती मनायी गयी, निश्चित रूप से इस जयन्ती से इस बिहार का नाम पूरे देश और दुनिया में रौशन हुआ है । उसमें नगर विकास विभाग ने भी 88 करोड़ रू0 की लागत से पूरे शहर में जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है । निश्चित रूप से यह काम सराहनीय है, इसके लिए नगर विकास विभाग को बधाई देते हैं ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात को जरूर रखना चाहूँगा । हमारे यहां समस्तीपुर जिला में जिला मुख्यालय में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है और समस्तीपुर में एक जमीन जो स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव मांगा था, जो आवास बोर्ड की जमीन है । मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए समस्तीपुर शहर स्टेशन के पास 60 एकड़ भूमि है, जिसपर एक प्रस्ताव लिया गया है । हम चाहेंगे कि नगर विकास मंत्री समस्तीपुर जिला से आते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की वह धरती है, वहां पर बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यातायात की दृष्टिकोण से उस जगह पर अगर मेडिकल कॉलेज जितवारपुर के हाऊसिंग बोर्ड की जमीन पर बन जाता है तो निश्चित

रूप से 2 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे । इसीलिए हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय आज के अपने जवाब में इसका जवाब देंगे ।

महोदय, मैं पेयजलापूर्त्ति पर बोलना चाहता हूँ । समस्तीपुर में डी0पी0आर0 बना है और समस्तीपुर इनका क्षेत्र है और वहां जो मुख्य दो गरीब बस्ती है, उसको छांट दिया गया है, जिसमें एक धर्मपुर का वार्ड 1, 2 एवं 9 आता है और एक बहादुरपुर आता है । हम चाहेंगे कि उस टेंडर को केंसिल करके उसको जो दो बड़ी गरीब बस्ती को छोड़ दिया गया है, उसको भी साथ लेने के बाद एक साथ टेंडर किया जाय । साथ ही हम चाहेंगे कि समस्तीपुर शहर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए तमाम घाटों का निर्माण किया जाय । बूढ़ी गंडक नदी के किनारे यह बसा हुआ है । वहां पर पार्क नहीं है, वहां पर एक बड़ा पार्क का निर्माण किया जाय । समस्तीपुर को हम चाहेंगे सर कि समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया जाय । इसलिए हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं और हम चाहेंगे कि शहर में जितना भी शिवरेज, ड्रेनेज है, उसकी व्यवस्था किया जाय । शहर में कचड़े की व्यवस्था होती है, उसको निकालना का काम किया जाय, क्योंकि समस्तीपुर शहर की जनता को आपसे बहुत अपेक्षा है क्योंकि वहां के स्थानीय सांसद भी रहे हैं और समस्तीपुर नगर विकास मंत्री उसी समस्तीपुर नगर क्षेत्र से आते हैं । इसलिए हम चाहेंगे कि इन तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाय । साथ ही हमारे कई साथी बता रहे थे कि स्थायी समिति होता है नगर विकास विभाग में । माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं, स्थायी समिति में शहर के विधायक को उसका सदस्य बनाया जाय ताकि शहर के विकास के मामले में विधायक अपनी बात रख सकें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका समय एक मिनट शाहीन साहेब कृपया ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, अब हम अन्त में यही कहना चाहेंगे कि समस्तीपुर शहर जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्षेत्र रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष कृपा दृष्टि बना रहता है । समस्तीपुर का विकास अपेक्षाकृत नगर का नहीं हो रहा है, स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करते हुये समस्तीपुर का विकास किया जाय, विभाग स्पेशल ध्यान दे।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब समाप्त करें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, एक योजना है सिटी बिजनेस प्लान एक केन्द्र सरकार की योजना है, इसका कई स्टेट में इसका लाभ लिया जाता है । मेरे जानकारी में उस योजना का प्रोजेक्ट नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार जी थे तो इनके सामने दिया गया था । इसमें 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। इसमें ग्रुप बनाकर के बिजनेस डेवलप किया जाता है । यह एक बड़ी योजना है, जो बिहार में इम्पलीमेंट नहीं हो रहा है । हम चाहेंगे कि विभाग के लोग केन्द्र सरकार से इसमें वार्ता

करके इसको कराये । मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : शुक्रिया । भारतीय जनता पार्टी, माननीय सदस्य, जिसका मैं नाम लूँगा, आसन आपसे आग्रह करता है कि आज आपके जिह्वा पर सरस्वती माँ का वास होना चाहिए । श्री संजय सरावगी, आपका समय 6 मिनट ।

श्री संजय सरावगी : एक दो मिनट बढ़ा दीजियेगा हुजूर ।

सभापति महोदय, माननीय अरूण सिन्हा जी ने जो कटौती प्रस्ताव दिया है नगर विकास विभाग पर, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, राज्य के शहरों की हालत बहुत खराब है, इसी पर दो लाईन कहना चाहता हूँ सभापति महोदय -

कितने हैं बैचेन नगर के लोग, वजीर को क्या मालूम,
मच्छर, बन्दर, कीड़े, जल-जमाव और
सड़क जाम से परेशान हैं लोग, वजीर को क्या मालूम ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, एक बात ईमानदारी से बताये कि ....

श्री संजय सरावगी : हुजूर, मेरा समय बर्बाद नहीं किया जाय .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : एक मिनट । माननीय मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : ईमानदारी से बोलियेगा, हमलोग जब जाते हैं तो दरभंगा में इनके घर के बगल से गुजरते हैं । तीन साल पहले उस सड़क की क्या स्थिति थी और आज कितनी शानदार स्थिति है, ईमानदारी से बोलिए ।

श्री संजय सरावगी : सर, जो सड़क बनी थी, वह तीन साल पहले बनी थी, उसके बाद एक भी सड़क नहीं बनी है । मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और चुनौती भी दे रहा हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब विषय पर आईए ।

श्री संजय सरागवी : सर, पूरे देश में शहरी आबादी 31 प्रतिशत है और राज्य में 11.5 प्रतिशत, देश में सबसे कम । पेयजलापूर्त्ति घर-घर पेयजल दिया जा रहा है, पूरे देश में 70.5 प्रतिशत औसत दिया जा रहा है और बिहार में 20 प्रतिशत और वह भी जो बन्द पड़ा हुआ है, वह भी देश में सबसे कम । सिवरेज सिस्टम पूरे देश में 32 प्रतिशत घरों को सिवरेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है और बिहार में 0.2 प्रतिशत मतलब देश में सबसे कम, यह हालत है बिहार के शहरों की यह स्थिति है सभापति महोदय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : पूरे भारत का आपने दौरा किया है क्या ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सर, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, यह प्रमाणिक आंकड़ा है, जो वेबसाईट पर डाला हुआ है, जो सर्वेक्षण केन्द्र सरकार कराते रहती है, उसका मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ।

सभापति महोदय, जो हालत है, जो हाल है राज्य के शहरों की । माननीय मुख्यमंत्री जी 22 दिसम्बर, 2015 को इस विभाग की समीक्षा किये थे और उसमें कहा गया था कि 15 शहर को विकास प्राधिकार बनायेंगे, 15 शहर बनेंगे स्मार्ट । प्राधिकार जो है, 15 जगह बनाया जायेगा । सवा साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, क्या हुआ, यह बहुत बड़ी समस्या है । नगर निकाय तो शहर के अन्दर काम कर लेता है लेकिन अंतिम बिन्दु तक नाले के निर्माण के लिए या शहरों के विकास के लिए विकास प्राधिकार होना बहुत जरूरी है । माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर बतायेंगे कि इस विकास प्राधिकार का क्या हुआ ? सभापति महोदय, भारत सरकार ने राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 11276 स्वीकृत इकाई की थी और

(व्यवधान)

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जब टोका-टोकी कर रहे हैं,

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्लीज,प्लीज, शांत रहिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, बताईए ......

टर्न-20/अंजनी/दि0 25.03.2017

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्लीज शांत रहिए, मैं आपको देख रहा हूँ ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, राजीव आवास योजना में 11 हजार 276 इकाई स्वीकृत हुई थी और इसकी परियोजना लागत आधारभूत संरचना के साथ 454 करोड़ थी और अभीतक इसकी आधी राशि भी खर्च नहीं हो पायी है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी को अपने जवाब में बताना चाहिए । शहर में 50 साल पहले महादलित परिवार आकर बसे, कहीं जमीन था बस गये लेकिन उनके पास जमीन का दाखिल खारिज कागज नहीं है, जिसके कारण उनका घर जो भारत सरकार बनाना चाहती है, वह घर नहीं बन रहा है । 22 तारीख की समीक्षा बैठक में यह भी तय हुआ था कि वासगीत पर्चा जो है, वह शहर के गरीबों को दिया जायेगा । कितना वासगीत पर्चा विभाग ने दिया, इसके संबंध में माननीय मंत्री जी को अपने जवाब में जरूर बताना चाहिए । सभापति महोदय, शहरी पेय जल योजना घर-घर सरकार का प्रावधान है, जिसके तहत 20 लाख 13 हजार परिवार बिहार में हैं और 20 प्रतिशत् आबादी अभी तो 2016-17 की योजना में जोड़ने की, घर-घर पहुंचाने की योजना थी, इस संबध में माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने नये घरों को 2016-17 में घर-घर पेय जल जोड़ा गया आपूर्त्ति के तहत । महोदय, वर्ष 2015-16 में एक लाख शौचालय भारत स्वच्छता अभियान के तहत और वर्ष 2016-17 में तीन लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 60-62 हजार मात्र शौचालय बना । 2539 वार्ड बिहार में हैं और उसमें कितने वार्ड ओ0डी0एफ0 हुए अभी तक, तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि

खुले शौच से कितने वार्ड मुक्त हुए । मैं तो जानता हूँ और जहां के माननीय मंत्री प्रभारी हैं, वहां एक भी वार्ड अभी तक ओ0डी0एफ0 नहीं हुआ, खुले शौच से मुक्त नहीं हुआ तो पूरे बिहार की क्या हालत होगी, यह इसी से पता चलता है सभापति महोदय ? सभापति महोदय, मेरे श्मशान घाट के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि शहर में श्मशान घाट में नागरिक सुविधा विकास करने का जिम्मा नगर विकास विभाग का है लेकिन मुझे बहुत दु:ख हुआ कि आज मैं नगर विकास विभाग की योजना पढ़ रहा था लेकिन कहीं भी ....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आसन आपसे कुछ कहना चाहता है ।

श्री संजय सरावगी : हुजूर, समय जरूर देख लिजियेगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : श्मशान, कब्रिस्तान की समस्या मौजूदा हुकूमत का निदान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से नहीं होता है तो आसन भी यह मानकर चलता है कि बहुत इसमें किसी से नहीं होगा । घबराइए मत ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, हम बता रहे थे कि आज जो नगर विकास विभाग का प्रतिवेदन है ....

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय.....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : इनको बोलने दीजिए ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मेरा समय देख लीजियेगा । नगर विकास विभाग का प्रतिवेदन हमारे पास है, एक रूपये का भी प्रावधान श्मशान घाटों के नागरिक सुविधा विकास के लिए नहीं किया गया है । न शव जलाने के लिए प्लेटफार्म, शव यात्रा में लोग जाते हैं न उसके लिए पानी का, न शेड की व्यवस्था और न लाईट की ही व्यवस्था है । बहुत खराब हालत है श्मशान घाटों का ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सरावगी जी, आप कृपया समाप्त करें ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, काट लिजियेगा दो मिनट । कुछ क्षेत्र की समस्या है, दरभंगा मिथिला का मुख्यालय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर घोषणा किया था और वह घोषणा की सूची में है कि दरभंगा को हम जल-जमाव से मुक्त करेंगे और जो रूद्राभिषेक ने डी0पी0आर0 बनाया था सिवरेज और ड्रेनेज का, उसको हम सहमति देंगे लेकिन तीन साल हो गये और अभी तक उस सिवरेज और ड्रेनेज योजना का कोई पता नहीं है । दरभंगा में हराई तालाब है, हराई तालाब में एक करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन साल पहले शिलान्यास किया था और अभी तक योजना प्रारम्भ नहीं हुआ । बस स्टेंड, पांच साल से राष्ट्रीय सम विकास योजना से ....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : एक मिनट सर ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका एक मिनट समाप्त हो चुका है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, सात करोड़ की लागत से बस स्टेंड बनकर तैयार है । पिछले दिनों समीक्षा बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तीन-चार दिन के अन्दर नगर निगम को स्थांतरण कर दिया जायेगा लेकिन आजतक राजस्व विभाग ने स्थांतरण नहीं किया, इसलिए दरभंगा, जो मिथिला का मुख्यालय दरभंगा है, उसपर विशेष ध्यान दिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए । आप बहुत ओबिडियेंट सदस्य हैं । आप बैठ जाइए । राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा । आप बैठ जाइए, धन्यवाद ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय....

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : सभापति महोदय,

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : एक सेंकेड रूक जाइए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, वरीय सदस्य हमारे संजय सरावगी साहेब हैं और अपने कविता के माध्यम से बिहार की शहरी विकास योजना पर अपना प्रकाश डाल रहे थे और हमलोग भी जानते हैं कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनको अधिकतर सफलता शहरों से मिलती है और शहरों के विकास के लिए देश में अनेक घोषणायें की लेकिन बिहार जैसा प्रदेश जो उनको भारी बहुमत देने का काम किया, बिहार के साथ काफी नाइन्साफी किया....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : हो गया । जनाब बैठ जाइए । आप भी बैठ जाइए । सरावगी जी हो गया । माननीय सदस्य श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा । आपका समय पांच मिनट है।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, आज मैं शहरी विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बजट के समर्थन में तथा विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सदन के माध्यम से महागठबंधन के नायक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ-ही-साथ इसके बाद मैं महागठबंधन के महानायक श्री लालू प्रसाद जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि अगर इनका स्नेह मुझे प्राप्त नहीं होता तो आज मुझे इस सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता । सभापति महोदय, इसके साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ सदन में बैठे अपने राजनीतिक गुरू माननीय मुन्द्रिका बाबू के प्रति, जिन्होंने मुझे राजनीतिक आदर्श के गुर सिखाने का काम किया ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह सब यहीं कहना था आपको ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : महोदय, आज मैं आभार प्रकट करता हूँ शहरी विकास मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री आदरणीय श्री कृष्णनंदन बाबू के प्रति जो इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, नगर विकास विभाग के द्वारा आज जो बिहार के नगरों के विकास का काम किया जा रहा है, वह काम काबिलेतारीफ है । आज नगर विकास का काम हर घर को सात निश्चय के द्वारा नल से जल देने का काम किया जा रहा है । उसे कल स्वर्णीम अक्षरों में लिखा जायेगा । महोदय, महागठबंधन के द्वारा आज बिहार के नगरों में, हर गली को पक्कीकरण करने का काम किया जा रहा है, वह भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा । महोदय, आज मैं शहरी विकास के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग का मुख्य काम लोगों को पेय जल उपलब्ध कराना है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अब लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने पर जोर दिया है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है । मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में हर घर को नल से शुद्ध जल देने की गांव-गांव में चर्चा हो रही है और इस पर तेजी से काम हो रहा है । गांव, कसबे सब जगह नल का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है । राज्य के आर्सेनिक, फलोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में पानी को शुद्ध करने की योजना पर काम चल रहा है । विभाग पूरी शक्ति और उर्जा से लोगों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और पी0एच0ई0डी0 मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक गरीब प्रदेश है और जिसकी आबादी करीब 11 करोड़ और क्षेत्रफल 94 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक है । हमारे राज्य की 85 प्रतिशत् आबादी गांव में रहती है ।

....क्रमशः....

टर्न-21/शंभु/25.03.17

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : क्रमशः........जहां आज भी परंपरागत स्रोतों जैसे कुआँ, तालाब और चापाकल पर ही पूर्ण निर्भरता है। ऐसे में नल का शुद्ध जल सपना जैसा प्रतीत होता है, परन्तु सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण यह सपना भी अब साकार होने लगा है। सुदूरवर्ती गांवों में भी बड़े-बड़े बोरिंग हो रहे हैं ताकि लोगों के घरों तक पानी पीने के लिए शुद्ध जल पहुंचाया जा सके। बिहार सरकार के इस साल के बजट में पानी के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की है, परन्तु इस मामले में केन्द्र की सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में केन्द्र सरकार ने अनुदान की

राशि 75/25 से घटाकर 50/50 प्रतिशत कर दिया है। वर्ष 2017-18 के लिए एलोकेशन की राशि भी केन्द्र ने काफी कम किया है जिससे यह साबित होता है कि केन्द्र में बैठे लोग बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : विरेन्द्र बाबू, एक मिनट समय है आपका।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : और हमारी योजनाओं को धरती पर उतरते नहीं देखना चाहते हैं। महोदय, मैं मगध के औरंगाबाद जिले से आता हूँ जो फ्लोराइड प्रभावित है। राज्य के पठारी, उप पठारी क्षेत्र के 3 हजार से अधिक बसावटें फ्लोराइड प्रभावित है। जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अपने दम पर 2 हजार करोड़ की योजना स्वीकृत की है। महोदय, मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूँ कि आप भी दाउद नगर से परिचित हैं और दाउद नगर आज तक नगर पंचायत है। महोदय, एक पेटीशन हाईकोर्ट में नगर परिषद् बनाने के लिए दिया गया था और हाईकोर्ट के द्वारा उसे नगर परिषद् का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूँ कि आप भी सदन से उसे नगर परिषद् का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय सदस्य श्री ललन पासवान- 2 मिनट आपका समय है, जिसमें कुछ आप बर्बाद कर चुके हैं।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, एक नंबर बात बोलते हैं पहले सुन लीजिए, सबके हित में है। सभापति महोदय, आज आवास बोर्ड एवं पी0एच0इ0डी0 का है। बिहार का डेढ़ सौ एम0एल0ए0 बिहार में डेरा खोज रहा है, कहीं कोई डेरा देनेवाला नहीं है। सत्तापक्ष द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ले चुके हैं।

श्री ललन पासवान : और डेढ़ सौ का न कहीं कोई घर है और न द्वार है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : पहले ही आ चुका है लिखित रूप में इनका आप तो मुँहजवानी बोल रहे हैं।

श्री ललन पासवान : भूखण्ड खाली है पूरे बिहार में यहां पटना में एक नहीं दो सौ, तीन सौ खाली होगा। पिछली सरकार ने दी थी कौटिल्य मार्ग में, माननीय चार सौ-पॉच सौ एम0एल0ए0 हैं। सभापति महोदय, मैं तो कहूंगा कि सरकार घोषणा करे, सरकार संवेदना के साथ करे, संवेदनहीन सरकार हो गयी है। माननीय एम0एल0ए0 का नोटिस नहीं लेगी तो बाकी विकास क्या करेगी सरकार ? इसलिए सभापति महोदय, आज सरकार ऐसी स्थिति में है कि नाली, गली हमलोगों का छीन ली और अब हमलोग ऐसी स्थिति में हो गये हैं कि एक चपरासी भी हमलोगों से बढ़िया है। चपरासी से बदतर हैं, जनता कोई नोटिस लेनेवाली नहीं है। उसमें आपकी भी संख्या है, आप भी उसमें शामिल हैं। हमलोगों को कोई पूछेगा नहीं, हम आग्रह करेंगे। सरकार कहती है पानी देंगे, नल से जल देंगे। 45

हजार गांव हैं बिहार में और 45 हजार गांव हैं, बजट क्या है सरकार का ? ऐसी स्थिति है नगर विकास विभाग की- हमारे यहां आज तक पानी नहीं मिला हम सासाराम लेकर आये थे हमारे यहां आज तक पानी नहीं मिला- नौहट्टा रोहतास, चेनारी, शिवसागर रोहतास के पहाड़ पर 213 गांव चुआरी का पानी पीता है आजादी के 70 साल गुजर गये, पशु और इंसान दोनों दो घूँट पानी के लिए तरसता है। समय मत देखिए सभापति महोदय, तनी हमारी गंभीर बात है और सदन के माध्यम से यह बात नहीं सुनी जायेगी तो इंसान मर रहा है और जानवर भी मर रहा है। सभापति महोदय, चुआरी का पानी पीती हैं। हमारी बहु बेटियॉं 10-10 कि0मी0 यादव का, पासवान का, राम का, सब दलित, आदिवासी पहाड़ पर रहता है, खरवार की, चेरों की जवान बहु बेटियॉं 10-10 कि0मी0, 16 कि0मी0 जाकर चुआरी का पानी लाकर अपना जीवन बसर करती है।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : उरांव का भी।

श्री ललन पासवान : हां उरावं का भी, मैंने तो कहा कि आदिवासी और मानव नहीं लगता है कि वहां आदि मानव रहता है। आदि मानव रहता है आजादी के 70 साल के बाद वहां इंसान आज भी गुलाम है पूरा कैमूर गुलाम है। सभापति महोदय, मेरे यहां रसूलपुर ढेलाबाग, अकबरपुर, नौहट्टा कई ऐसे पी0एच0इ0डी0 का टंकी है- पूरा का पाइप खराब है, कहीं गांव में पानी नहीं पहुंचता है, चालू हुआ है पी0एच0इ0डी0 मिनिस्टर जी कहते हैं। हमारे इलाके में अब गर्मी शुरू हुआ और टैंकर से पानी जायेगा और टैंकर से पानी जा रहा है तो सरकार कह रही है कि नल से जल देंगे। ये टैंकर से पानी जा रहा है हमारे यहां गर्मी में सिमान अभी बाकी है, किसानों से मैं कहकर उनका ट्रैक्टर लेकर टैंकर से पानी मैं भेज रहा हूॅं। अभी तक सरकार उसका पैसा नहीं दे पायी। ऐसे सरकार चलेगी तो ये सामाजिक न्याय है कि गैर सामाजिक न्याय है, अन्याय है कि न्याय है आप ही न्याय करियेगा। सभापति महोदय, मेरा चेनारी प्रखंड है पूरे बाजार पानी से पैक है। हम आग्रह करेंगे नगर विकास मंत्री जी से कि उसको नगर निगम में नगर पंचायत उसको बना दीजिए। ठेहुना भर पानी लगा है, दलित अकलियत की बड़ी आबादी है, पिछड़ों की आबादी है जाने का रास्ता नहीं है।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : आपका समय समाप्त। बहुत बोल लिये।

श्री ललन पासवान : बस लास्ट ही है महोदय। सभापति महोदय, आसन तो संज्ञान ले ही रहा है। मैं एक और बात कहकर के...........

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : समस्या में गंभीरता नहीं है माननीय सदस्य मुस्कुरा-मुस्कुरा के अपनी बातों को रख रहे हैं और दिल में इनको दर्द है, लेकिन प्रदर्शन उल्टा हो रहा है। आपका समय समाप्त।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, सुनियेगा सर, नौहट्टा रोहतास पहाड़ों पर रहनेवाले पशु और जानवर- मैं ईमानदारी से कह रहा हूॅं सच्चाई से कह रहा हूॅं वहां आज भी पीने का

पानी नहीं है। मैं सरकार से व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूँ कि रोहतास में सरकार विशेष व्यवस्था कराके वहां पानी टंकी और ड्रील से क्योंकि 3 सौ, 4 सौ फीट पर पानी वहां...

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : कृपया अब समाप्त कीजिए माननीय सदस्य। भारतीय जनता पार्टी माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी, प्रारंभ करें। 5 मिनट आपका समय है।

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं अरूण सिन्हा जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग हेतु प्रस्तावित 43 अरब 35 करोड़ 1 लाख 21 हजार की राशि से 10/- रू0 की राशि घटायी जाय। महोदय, किसी भी राज्य में विकास के लिए शहर के विकास के साथ-साथ गांव का विकास होना भी जरूरी है, परन्तु जब यहां शहर ही विकसित नहीं हो पा रहा हो तो गांव का क्या कहना है। महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग बजटीय आंकड़ा पर गौर करना चाहिए। महोदय, पटना में नुरूम योजना के तहत शुद्ध जलापूर्ति के तहत 420 करोड़ की लागत से 2010 में योजना बनायी गयी थी जिसका 2012 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग 150 कि0मी0 नयी पाइप लाइन बिछाते हुए 72 जल मीनार बनाने का लक्ष्य था, परन्तु सरकारी जल मीनार नहीं बन पाया है। महोदय, पटना सहित, समय नहीं है, मैं सबसे पहले माननीय सत्तापक्ष से कहना चाहती हूँ ये लोग बोल रहे हैं कि नगर विकास में काम हो रहा है।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : मैडम, आप इधर बोलिये।

श्रीमती आशा देवी : माननीय महोदय मैं जो भी कहूंगी सच कहूँगी। यहां जो सदस्य लोग बता रहे हैं कि नगर विकास में बहुत विकास हो रहा है- सब सदस्यों से मैं पूछना चाहती हूँ कि नगर परिषद् जो आपके क्षेत्र में पड़ता है वहां विधायक लोगों को कितना मान-सम्मान मिलता है, यह पहले बताएं। वहां पर चेयरमैन और कार्यपालक अभियंता के अलावे मैंने माननीय मंत्री जी से कितनी बार यह बात कही हूँ। क्रमशः

टर्न-22/अशोक/25.03.2017

श्रीमती आशा देवी : क्रमशः माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि विकास हो, पूरा देश में नाम हो कि बिहार में विकास हुआ है । 2005 में जो सरकार बनी थी उस समय पूरे देश के लोग जान रहे थे कि बिहार विहार हो गया लेकिन जब से महागठबन्धन हुआ है महोदय, तब से महाभारत बिहार में शुरू हुआ हैं महोदय, विकास नहीं हो रहा हैं, विनाश हो रहा हैं महोदय । इसलिए मैं माननीय सदस्य लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता का काम नहीं करियेगा, अभी 2005 से शुरू हुआ मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, अनुशंसा विधायक लोग करते

थे महोदय, वहां नली, गली बनता था महोदय, जनता का समस्या सौल्भ होता था महोदय अभी जो आपका नगर निगम में जल जमाव की जो स्थिति है महोदय, जब बारिश होती हैं महोदय पानी की निकासी नहीं है महोदय, मच्छड़ का प्रकोप बढ़ता जाता हैं, वहां की जनता को बहुत कठिनाई होती हैं महोदय इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूॅ कि पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद् में मच्छड़ छिड़काव का मशीन खरीदे, समय समय पर दवा का छिड़काव करें महोदय । अभी पटना में हमलोग रह रहे हैं महोदय , आवास में इतने मच्छड़ लगते हैं कि जनता को और सदस्य को टांग कर ले कर चला जायेगा महोदय, कोई दवाई का छिड़काव नहीं होता है, छिड़काव होता है, धुआं, ऐसा लगता हैं कि किरासन तेल डालकर छिड़काव होता है, सही दवा का छिड़काव हो महोदय ताकि जनता को लगे कि नहीं विकास हो रहा हैं, सरकार में खाली हवाबाजी बहुत ज्यादा हो रही हैं महोदय। अभी लोग कहते हैं कि केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, महोदय केन्द्र सरकार से नगर विकास में 50 प्रतिशत राशि मिलती हैं महोदय, 30 प्रतिशत राज्य सरकार देती हैं महोदय, 20 प्रतिशत नगर निगम देता हैं महोदय । यह स्थिति है महोदय, लेकिन माननीय सदस्य लोग को लगता हैं कि झूठ बोल देंगे तो बहुत कुछ हो जायेंगा, नहीं महोदय जो बात है सत्य कहें । अभी नगर परिषद् में लाईट लगता है महोदय, चैयरमैन और कार्यपकालक अभियंता के देख रेख में महोदय, वह लाईट छः महीना से ज्यादा नहीं चलता है महोदय, लाईट का रेट रहता है महोदय 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 25 हजार पर लाईट देते हैं....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्या, कृपया समय पर ध्यान देंगी, आप एक मिनट में समाप्त करेंगी ।

श्रीमती आशा देवी : जी, जी । मैं सही बात बता रही हूॅ महोदय, अभी दानापुर में जल मीनार बना हैं पाचं, दो खगौल में और तीन दानापुर में, खगौल का दो जल मीनार पूरा हो गया लेकिन दानापुर का तीन अधूरा पड़ा हुआ हैं महोदय । अभी लोग बोलते हैं कि कचड़ा उठाव में, कचड़ा उठाव में महोदय कार्यपालक अभियंता चेहरा और दबंगता देखकर घर का कचड़ा उठवाते हैं महोदय, गली साफ करते हैं महोदय, नाली साफ होता हैं महोदय । यह स्थिति बनी हुई है महोदय । मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूॅ, इसके पूर्व भी मंत्री जी को कितनी बार कह चकी हूॅ कि दानापुर के कार्यपालक अभियंता किसी की बात नहीं सुनता हैं महोदय

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती आशा देवी : चेयरमैन का भी नहीं सुनता हैं, वाईस चैयरमैन के अलावे किसी की बात नहीं मानता हैं, वहां पर दानापुर में लूट खसौट हो रहा हैं इस पर ध्यान दिया जाय ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय मंत्री, संज्ञान ले रहे हैं, गंभीर हैं ।

श्रीमती आशा देवी : एक सेकेन्ड महोदय, बोलने दिया जाय । दानापुर में 37,38,39,40 वार्ड में पानी की निकासी नहीं हैं, अभी नाला बन रहा हैं गोला रोड में महोदय, वहां लूट खसौट हो रहा है, वहां देंखा जाय महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय मंत्री जी इसको दिखलवा लेंगे ।

श्रीमती आशा देवी : जय हिन्द, जय भारत ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): राष्ट्रीय जनता दल अब मैं माननीय सदस्य डाक्टर...

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, ...

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ और आप । अब मैं माननीय सदस्य डा. मोहम्मद नवाज आलम साहब से आग्रह करता हूँ, इनका समय दस मिनट ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक मिनट । माननीय सदस्या आशा जी बोल रहीं थी कि महागठबन्धन जब से हुआ महाभारत हो रहा है, महोदय, महागठबन्धन में महाभारत होने वाला नहीं है महोदय, ये लोग शकुनी और कैकयी के रौल में नहीं रहें । ये लोग आशा मत लगायें ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): उनकी कल्पना को रोक दीजियेगा क्या ? आशा पर आकाश टीका है, स्वास तंत्र कब टूटे । इसको कैसे रोक दोगे आप ।

श्री डा. मोहम्मद नवाज आलम : सभापति महोदय, आज मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो विपक्ष के साथी कटौती प्रस्ताव लाये हैं उनका मैं विरोध करता हूँ । सभापति महोदय, बिहार की आबादी की जहां, बिहार की आबादी 100 प्रतिशत आबादी के लोगों में 10 प्रतिशत लोग जो हैं शहर में निवास करते हैं महोदय और 10 प्रतिशत आबादी की अभी तक जो संरचना हैं, यहां की जो सुख सुविधा मिली वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं अभाव रहा महोदय और उस कड़ी में, उस सुख सुविधा को बढ़ानेके लिए महगठबन्धन के मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जो हमारे जन-जन के नेता समाजिक न्याय के योद्धा, जिन्होंने गरीबों को आवाज दी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की एक सोच थी और एक संकल्प था, एक सोच था, एक विजन था ...

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, यह सदन है, कमर पर से हाथ उतार लें, अदब से बोलिये अपना भाषण ।

श्री डा. मोहम्मद नवाज आलम : जिस तरह से शहर से लेकर गांव तक जो है तमाम जगहों पर विकास की किरणें पहुंचाने का जो लक्ष्य था जो भी जनता की सोच थी उस सोच को कहीं न कहीं सर जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने सात निश्चय की घोषणा की महोदय, सात निश्चत में तीन निश्चय को निश्चित रूप से शहर में जो है किस

तरह से शहर के लोगों को लाभ पहुंचे, उनकी सुख सुविधा कैसे बढ़े, उसी कड़ी में तीन निश्चय लिया गया महोदय । एक निश्चय हर घर में नल का जल, हर घर में में नल का जल का में जो योजनायें ली गई उसका 89 योजनायें जो हैं स्वीकृत करने का काम किया गया महोदय । उसी तरह से दूसरी योजना थी हर घर तक पक्की नली, गली का निर्माण करेंगे, उन कार्यों को सर जमीन पर उतारने के लिए तमाम जगहों में डी.पवी.आर. और कई जगहों पर जो नगर निगम हैं उन जगहों पर काम शुरू है महोदय । शौचालय निर्माण, हर घर को सम्मान, एक ऐसी योजना थी महोदय जो गांव के मलिन बस्तियों में रहते थे, जो गरीब लोग थे, महागठबन्धन की जो सोच थी जो सरजमीन पर उतारने के लिए तमाम महानायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक सोच और एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ उन्होंने इस योजना को आठ लाख जो है शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा महोदय । 8 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य था महोदय, शौचालय निर्माण में 12 हजार रूपये जो दिये गये, 8 हजार रूपये राज्य सरकार के द्वारा आंवटित हैं, 4 हजार केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने लगी, महोदय, दुगनी राशि देकर कहीं न कहीं गरीब वंचित समाज को लाभान्वित करने का काम हमलोगों ने किया हैं । 140 शहरों में सर्वे का काम चल रहा है महोदय, 55 हजार 258 शौचालय का निर्माण किया गया महोदय, 96 हजार 470 जो है निर्माणाधीन है महोदय, इसी तरह से परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बस डीपो बनाने के लिए जो उपलब्धियां हमारा जो विजिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, जो संकल्प थी उसके लिए 33 हजार 100 बस टर्मिनल बनाने का कार्य 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया महोदय । 39 नगर निगम को बस स्टैण्ड निर्माण का काम किया जो इसकी प्रगति तेजी से है महोदय । पार्क के मामले में, न जाने अनेकों पार्क पटना से लेकर तमाम जगहों में लगभग 60 पार्क का निर्माण किया गया, उसमें बड़े-बड़े, जैसे बुद्धा पार्क, ईको पार्क, न जाने कई मलिन बस्तियों को जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं थी, लोग टहलना चाहते थे, स्वस्थ्य रहना चाहते उन पार्कों को बनाने का काम किया गया महोदय । सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही, महगठबन्धन की रही कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350 जयंति समारोह में जिस तरह से नगर निगम ने जो उपलब्धियसां हासिल की, जो काम किया है, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो , चाहे वहां के पेय जल की सुविधा के मामले में तमाम चीजों में कहीं न कहीं एक अच्छी पहल रही है महोदय लेकिन विपक्ष के साथी हमारे कुछ साथी कहते कि हमलोगों ने निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं आलोचना करनी चाहिए लेकिन जहां काम महागठबन्धन के साथियों ने किया, क्रमशः

टर्न-23/ज्योति
25-03-2017

क्रमशः

श्री मो0 नवाज आलम : आपके द्वारा भी कुछ योजनाओं पर जैसे पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के बारे में मैं अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ही पूर्व के मंत्री जो हैं प्रेम बाबू ने लिया था फौर एग्जाम्पुल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ, आरा , दरभंगा कई जगहों पर आपने सरजमीन पर नहीं उतारा । यह पूर्व की मंत्री की ली हुई योजनाएं थी । पिछली सरकार ने 2010-11 में नीति बनायी थी नागरिक की सुविधाा के लिए जीवन स्तर को सुधारने के लिए महोदय, उसमें श्रम पॉलिसी अर्बन एरिया के निदेशक के संबंध में हाउसिंग पॉलिसी रेट कंट्रोल ऐक्ट के मामले कौम्यूनिटी पार्टिसिपेशन के मामले में एक लौ बनाया था । बिहार स्टेट भेंडर का मामला, रिअल स्टेट का मामला सभी नीतियाँ जो हैं कागज में रह गयी । आज तमाम विपक्ष के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि हमलोगों ने जो नीतियाँ बनायी है जो संकल्प लिया है जो वीजन दिया है उसको हमने सरजमीन पर उतारा है । ठीक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कोई भी ताली नहीं बजा रहा है । जब अच्छी चीज बोलते हैं तो बैठे हो आप लोग । कमाल है ।

श्री मो0 नवाज आलम : ठीक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि और बहुत ही बड़े एक डा0 ए0पी0जे0 कलाम ने कहा था कि " To succeed in your mission you must have single minded devotion to your goal " अगर आप सचमुच में अपने मीशन पर जाना चाहते हैं तो आप अपने डिवोशन आप अपने तमाम गोल को सामने रखते हुए अपने काम को करेंगे वही वीजन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाई तेजस्वी जी का और महानायक हमारे लालू यादव की जो संकल्प और सोच है उसको आगे बढ़ाने की जरुरत है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): भाई तेजस्वी जी नहीं डिप्टी सी0एम0 तेजस्वी जी, आपके भाई नहीं हैं । उप मुख्यमंत्री कहो ।

श्री मो0 नवाज आलम : वह हमारे नेता हैं इसलिए डिप्टी सी0एम0 कह रहे हैं । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, मैं, सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं महोदय, कि जिस तरह से हमलोगों की सोच थी उसीतरह से हमलोगों ने विधि विभाग के मामले में अनेक कार्य किए हैं महोदय, विधि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं इनको इस सदन के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से महोदय, पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण करने की

योजना यह आपका सराहनीय कदम है । अदालतगंज में पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए जो आपके निर्माण का काम किया है वह सचमुच में सराहनीय है । आपने 43 कोर्ट में 16 व्यवहार न्यायालय को आपने पुनर्जीवित करने का काम किया है सचमुच में इतिहास के पन्ने में आपका यह सराहनीय कदम है । इसी तरह से आपने बिहार के 58 जेलों में लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्था की है यह सराहनीय कदम है । लेकिन एक सुझाव के रुप में आदरणीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप ए0पी0पी0 की बहाली होती है नियुक्ति है ए0जी0पी0 की होती है, पी0पी0 की होती है लेकिन पैनल जिला से आया हुआ है आपके कार्यालय में ल ंबित है आपके माध्यम से जाननाा चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चीज को जल्द से जल्द नियुक्ति करने का काम करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया समाप्त कीजिये । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मो0 नवाज आलम: मेरे जिले में महोदय, हमने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में रखा था । रोज न्यायालय बनते हैं लेकिन भोजपुर में पूरे शाहाबाद के इतिहास में भोजपुर का आरा शहर पुराना शहर है महोदय, वहॉ ब्रिटिश काल का 11 नाला है । उसकी उड़ाही नहीं होती है। रोज नाला बनते हैं रोज खराब होते हैं लेकिन आउट फौल नाला अगर 11 नाले को आउट फौल की उड़ाही कर दिया जाय तो निश्चित रुप से आरा को जल जमाव से निजात मिलेगा । आरा में नगर निगम में कर्मचारियों की कमी है । कर्मचारी की कमी वहॉ लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं और 700 कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, कृपया समाप्ति की ओर ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, एक बात कहते हुए कि लिखित बात को, भाषण को और मांग को सदन के पटल पर रखेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): दे दिया जाय ।

श्री मो0 नवाज आलम : बस एक चीज कहते हुए आपसे विदा लेंगे, गार्जियन हैं आपसे कुछ सीखना चाहते हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : नवाज आलम साहब, एक सेकेंड सुनो, विदा तुम्हारे दुश्मन लें हम नहीं चाहेंगें विदा लो ।

श्री मो0 नवाज आलम : आपसे महोदय, ‘‘ मंजिल से आगे, मंजिल से आगे मंजिल से आगे बढ़ना मंजिल तलाश कर , मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर मिल जाय तुझको दरिया तो समुन्दर तलाश कर महोदय, इसी बात को कहते हुए अपने तमाम साथियों का और सदन के माध्यम से कहना है कि आपने समय दिया ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : बहुत, बहुत शुक्रिया ।

जनता दल यूनाईटेड, मैं माननीय सदस्य से, श्री वशिष्ठ सिंह जी से, आग्रह करता हूं । आपका समय 10 मिनट , कृपया ध्यान देंगे ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुपूरक मांग के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में अपनी बात रखने के लिए मैं सदन में खड़ा हूँ । महोदय, अपने समय दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नमन करते हुए विभागीय मंत्री का आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, नगर विकास से इस बिहार राज्य के 2011 की जन गणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वालों की आबादी 11.3 है और उसके विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है । हमारी सरकार हमेशा नगर के विकास, शहर के विकास, गांव के विकास के बारे में चिन्तित रहती है, सोचते रहती है और उसको लगातार विकसित करने के लिए काम करते रहती है। महोदय, नगर विकास आज के दिनों में जिला मुख्यालय जैसे नगर की बात मैं करता हूँ जहाँ सभी रोड पर लाईट की व्यवस्था की गयी है । सफाई की व्यवस्था हो रही है । सभी गलियों का पक्कीकरण हो रहा है । हर घर तक नली एवं गली का पक्कीकरण हो रहा है । यह बिहार सरकार की देन है । सकारात्मक सोच है । महोदय, नगर विकास के सवाल पर मैं अपनी बात को रखने के लिए बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के लिए अगले पाँच साल में शहरी क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की और नली गली से जोड़ने का लक्ष्य सरकार रखी है । यह माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 7 निश्चय की घोषणा की थी उस 7 निश्चय की घोषणा में एक योजना यह भी है । महोदय, जब हर घर में पक्की नली गली जायेगी और उसके साथ ही साथ सभी गरीब गुरबा के घर में नल का जब जल जायेगा तो वैसे जो गरीब गुरबा का विकास होगा तो सरकार को दुआ देगा और वह जब दुआ हमलोगों के लिए काम करता है जो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है । महोदय, यही कारण है कि एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात करने वाले लोग, स्मार्ट सिटी की बात करने वाले लोग बिहार जैसे राज्य के एक भी शहर को पहली सूची में जोड़ाने का काम नहीं किया । यह बिहार के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं । ये बिहार के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं । बिहार के हक और हकूक को खाने वाले लोग हैं । ये बिहार के साथ इन्साफ नहीं करते हैं । ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं , इन लोगों की कथनी और करनी मे मेल नहीं है । ये लोग झांसे में डाल कर..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य थोड़ा सा । नेता विरोधी दल ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, भारत सरकार ने भागलपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया है और भारत सरकार चाहती है कि बिहार के और शहर शामिल हो पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, अब उसके तहत मापदंड जो होना चाहिए, क्रायटेरिया की कमी के

कारण नहीं हो पाया है, हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे मापदंड के मुताबिक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सुझाव अच्छा है माननीय सदस्य बोलिये ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, हमारी सरकार 16960 करोड़ रुपये के ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): तेजी करो, समय कम है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : हमारी सरकार ने 16960 करोड़ रुपये की अनुमानित व्यय पर पटना में मेट्रो रेलवे परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा है लेकिन अभी तक भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है । हम भारत सरकार से मांग करते हैं और विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी सरकार से जाकर.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आसन को न कहेंगे ।

श्री बशिष्ठ सिंह : आसन को, आसन को आग्रह करना चाहते हैं महोदय, कि आप अपनी सरकार में केन्द्र सरकार में जाकर और इस परियोजना को स्वीकृति दिलायें ताकि पटना की धरती पर मेट्रो रेल चल सके ।

टर्न-24/25.3.2017/बिपिन

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): ठीक है । आपका समय अब बहुत कम है । बोलिये ।

बशिष्ठ बाबू, सरकार को लम्बा-चौड़ा जवाब देना है । कोऑपरेट करो आप । आप तो हमारे यंग और इनर्जेटिक मेम्बर हैं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, जितना समय मिलेगा, उतना ही में हम बोल लेंगे ।

महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं महोदय, कि हमारी सरकार शहर के साथ-साथ गांव का भी विकास करना चाहती है । जहां पानी की टंकी में कचरा बैठने के चलते हमारे मुख्यमंत्रीजी ही का सोच हुआ कि हम सभी को नल और जल की व्यवस्था देने का काम करेंगे और पी.एच.इ.डी. विभाग आज के बजट में है, उसके माध्यम से सभी गरीब-गुरूवा को, गांव के गरीब-गुरूवा को नल का जल देकर के उनको स्वच्छ और सुन्दर बनाना चाहते हैं ताकि हमारा गरीब-गुरूवा का भी बेटा पानी अच्छा पीकर के विकसित हो और उसकी सोच विकसित हो ताकि इस बिहार से एक अच्छा चिंगारी निकले ।

सभापति : ठीक है । माननीय सदस्य, बहुत अच्छा । कृपया बैठ जाओ । हँसिये नहीं, आसन का मामला है । क्यों हँस रहे हो ?

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, एक मिनट समय दिया जाए महोदय । महोदय, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम इस बिहार को विकसित बिहार बनावें और विकसित बिहार बनाने में चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, उन सारे के विकास के

लिए काम करना चाहते हैं । हमारे विपक्ष के एक सदस्य जी ने कहा था कि ये जो है कि हवावाजों की सरकार है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह सरकार हवावाजों की नहीं, यह काम करने वालों की सरकार है । हवावाजों की सरकार देश में है जिसके कथनी और करनी में मेल नहीं है और झांसे में लाकर के अपनी सरकार तो जरूर बना लेते हैं और वैसे-वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिनके उपर 20-20 ठो केस है, वैसे लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं । हमारे नेता के उपर एक भी केस नहीं है । हमारे नेता जो कहते हैं उसको धरती पर करके उतारने का काम करते हैं महोदय । हमारा जो यह राज्य है बिहार, हमारा बिहार जो राज्य है, यह देश को दिशा देने का काम करता है । यह बिहार जो राज्य है, यह देश को दिशा देने का काम करता है महोदय । चाहे चम्पारण की धरती हो, चाहे गया, गया बुद्ध की धरती है, चाहे सम्राट अशोक की धरती हो, चाहे दसवें गुरू गोविंद सिंह की धरती हो..

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार की बात बोल रहे हैं । बैठिये ।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिहार की धरती जो है, इस देश को दिशा देने का काम किया है । देश को दर्शन देने का काम किया है और यह बिहार की धरती हिन्दुस्तान को ही नहीं, बल्कि इस मुल्क को शांति का पैगाम देने का काम किया है महोदय और मैं कहना चाहता हूं महोदय कि बिहार की मिट्टी से आवाज आ रही है और हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने और उसमें एक नम्बर का नाम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का है । हम मांग करते हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी । अनुपस्थित ।

श्री विजय कुमार खेमका । आपको पांच मिनट का समय है विजय जी ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास एवं आवास विभाग के 2017-18 के लिए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, आपके साथ-साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार जी, माननीय सचेतक अरूण जी, सदन में उपस्थित माननीय सदस्य के साथ-साथ पूर्णिया की जनता का आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, नगरों का विकास उस प्रांत का प्रतीक होता है । शहर के विकास से ही राज्य का चेहरा झलकता है । महोदय, बिहार में एक गाना बहुत प्रचलित हुआ । उस गाना का बोल था अध्यक्ष महोदय, जरा झलक दिखा जा । जो नगरों की स्थिति है, इस सरकार में आज शहर विकास की झलक देखने के लिए तरस रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा बिहार प्रदेश शहरों की कैसी नारकीय स्थिति है, माननीय विधायकों से भी छुपा हुआ नहीं है । महोदय, अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ता में बैठे विधायक चुप रह कर स्वीकार करते हैं और विपक्ष जो सरकार का अंग होता है, अध्यक्ष महोदय, आप भी आसन से दोहराते है, जो अंग होता है महोदय, वह सोई हुई सरकार को सदन में जगाने का काम करता है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो पूर्णतः सुप्तावस्था में है । महोदय, प्रदेश की शहरों की स्थिति, चाहे सड़क हो, नाला हो, पीने का पानी हो, सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय, कचरा प्रबंधन, जल जमाव, बेंडिंग जोन पर पुनर्वास, प्रदूषण से मुक्त शहर, मुक्तिधाम, स्लम बस्ती विकास से काफी दूर है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नगर परिषद एवं बिहार में नगर परिषद, नगर निगम, 12 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 84 नगर पंचायतें हैं । लगभग सभी की स्थिति दयनीय है और एक जैसी है । अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना की स्थिति जब दयनीय है तो फिर पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर जैसे नगर निगमों का तो कहना ही क्या है ? बनमंखी, कसबा जैसा अनेक नगर परिषद और नगर पंचायत विकास से अध्यक्ष महोदय, काफी दूर है । महोदय, सरकार कहती है कि नली-गली का विधायक अनुशंसा नही करे । सात निश्चय में विधायकों की कोई भूमिका नहीं रखी गई है । अध्यक्ष महोदय, नगर निगम बोर्ड के विधायक मात्र पदेन सदस्य हैं । इसलिए मैं नगर मंत्री से आग्रह भी करना चाहता हूं कि नगर निगम में, नगरपालिका में जो स्थायी समिति है, उसका विधायक को पदेन सदस्य बनाने की मैं मांग भी करता हूं । मैं जानता हूं, नगर निगम के जो मंत्री हैं, बड़े ही हँसमुख हैं, सारे सदस्यों की बात को सुनते हैं । लेकिन जब नगर को सुधारने की बारी आती है तो पता नहीं, कैसे ये सरकार लाचार हो जाती है ?

महोदय, मैं नगर निगम मंत्री का ध्यान आसन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । महोदय, नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-12(3) उपधारा-2 के अनुसार नगर निगम की योजना में शिलापट्ट पर विधायकों का नाम लिखना अनिवार्य है । परंतु महोदय, माननीय विधायकों का न नाम लिखा जाता है, न उन्हें उसके शिलापट्ट के शुभारंभ में या उद्घाटन में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है । मैं मांग करता हूं माननीय नगर मंत्री से कि आप इसका निर्देश जारी करें ।

महोदय, सात निश्चय के माध्यम से, महोदय, संरक्षण चाहता हूं महोदय, महोदय, सात निश्चय के माध्यम से नली-गली से जल घर-घर पहुँचाने की बात सरकार करती है । गठबंधन के हमारे भाई भी भीतर-ही-भीतर...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री विजय कुमार खेमका: महोदय, एक मिनट सिर्फ लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

महोदय, पूर्णिया नगर निगम में 40 वार्ड लगभग छोटी-बड़ी एक हजार सड़कें बनाने के लिए बाकी है । महोदय, तीन सड़क की ओर मैं नगर विकास मंत्री जी से ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । डूडा के द्वारा तीन सड़क का टेंडर हो गया जो वहां की लाइफ-लाइन है अध्यक्ष महोदय । वह तीनों सड़क 2015 में सी.एस. के लिए पटना आया हुआ है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह तीनों सड़क जीर्णोद्धार के लिए इंतजार कर रहा है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए । श्री सत्यदेव राम । श्री सत्यदेव राम जी, दो मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, शहर चमकता है, शहर चमकता है, यह सारे माननीय सदस्यों ने कहा, हम भी कह देते हैं । लेकिन उसी शहर में ऐसा जगह है जो महकता है और वह है स्लम बस्ती, वह है मलीन बस्ती और उस स्लम बस्तियों के लिए जो प्रावधान हुआ है महोदय, उससे तो वह कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता है, कभी भी उसका विकास नहीं हो सकता है ...

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, आसन पर महोदय बैठे हुए हैं । माननीय आप अध्यक्ष हैं, हमलोगों के अभिभावक हैं और संरक्षण भी है आपका ।

अध्यक्ष : आप बात कहिए ।

श्री ललन पासवानः बात कह रहे हैं । हमलोगों को माननीय सदस्यों का डेढ़ सौ से उपर माननीय सदस्यों का अभी तक मकान आवंटित नहीं हुआ है, मेरा तो हो गया है लेकिन डेढ़ सौ से उपर लोग हैं । अतः नगर विकास आवास मंत्री बैठे हुए हैं महोदय और कंकड़बाग में सरकार के ...

अध्यक्ष : आपको जब समय मिला था, आप बोल रहे थे, उस समय यह बात क्यों नहीं बोले ? नहीं, अब आप बैठ जाइए ।

टर्नः 25/कृष्ण/25.03.2017

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईये ।

श्री ललन पासवान : सर, भूखण्ड खाली है । पिछली सरकार ने कौटिल्य नगर में माननीय सदस्यों का मकान आवंटित किया था, दिया था जमीन । हम सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि 243 माननीय सदस्य अभी हैं और चार-साढ़े चार सौ पुराने सदस्य हैं । या तो मकान आवंटित कर दें या भूखंड ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप शहरों का विकास कर रहे हैं । साथ-साथ शहरों के अंदर स्लम बस्तियां है, जो मलीन बस्तियां हैं, उनके लिये विशेष कार्यक्रम की नीति आप को तैयार करनी होगी और वहां से भी महक से हटाना होगा । महोदय, स्वच्छता अभियान मिशन भारत में चलाया गया, बड़े-बड़े लोग झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवा लिये । महोदय, सच्चाई क्या है ? आज शहरों में सुबह उठते ही झाड़ू पकड़ता है, सफाई करता है, उस की चर्चा नगर विकास एवं आवास विभाग के रिपोर्ट में नहीं है । मैं मांग करता हूं कि नगर निगम के सारे कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से की जाय और मंहगाई को देखते हुये उनके वेतन का निर्धारण किया जाय ।

महोदय, मैं शहर का आदमी नहीं हूं, मैं देहात का आदमी हूं । आज आपदा प्रबंधन विभाग भी है । हमारा विधान सभा क्षेत्र सरयू नदी के किनारे पर है । महोदय, मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आधा दर्जन से अधिक गांव सरयू नदी में है और कुछ गांव उस पार भी है, हुलासगंज उस पार है । सारे लोग आ कर नदी के तटबंध पर बसे हुये हैं और उस के जीवन-यापन के सारे कार्य नदी उस पार होते हैं । गरीबी के कारण वे लोग छोटी नाव से उस पार जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि नाव उलट जाती है और वे डूब कर मर जाते हैं । महोदय, अभी 26 नवंबर को तीन महिलायें डूब कर मर गयी । मैं माननीय मंत्री,आपदा प्रबंधन विभाग से अपील करता हूं, हम ने लिख कर के भी दिया है, सरयू नदी के तटबंध पर बसे लोगों को एक-एक बड़ी नाव उपलब्ध करा दी जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी । आप दो मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे विधान सभा में अरेराज नगर पंचायत, 14 वार्ड है । मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं । वहां पर सोमेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है । लाखों, करोडों लोगों की आस्था का केन्द्र है । महोदय, सावन के महीने में लगभग एक महीना वहां प्रतिदिन लोग आते-जाते रहते हैं । महाशिवरात्रि के दिन और अनन्त चतुर्थदशी के दिन 3 से 4 लाख तीर्थयात्री आते हैं और वहां पर रूक कर के दर्शन करते हैं । वहां की स्थिति की ओर आप के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं । इस के पहले भी मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल कर के वहां के विकास के लिये आग्रह किया था । महोदय, वहां की समस्या बिजली की है । संयोग से यहां बिजली मंत्री जी भी बैठे हुये हैं । सावन के महीने में अरेराज मंदिर में काफी भीड़ लग जाती है, बिजली काट दिया जाता है । हम एस0डी0ओ0 से पूछे कि मंदिर में जब भीड़ है तो क्यों बिजली काट दी जाती है तो

उन्होंने कहा कि तार की स्थिति इतनी खराब है कि कहीं टूट गया तो हजारो लोग मर सकते हैं । महोदय, हम आप के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अरेराज महादेव की नगरी में कम से कम रोड, नाला और तीर्थयात्री जब आते हैं तो वहां स्वच्छता की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है । इन सब बातों की ओर ध्यान दिलाते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप सभी माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम इस सदन को संबोधित किये थे तो उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उस में शहरी सुविधायें दी जाय लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो पूर्व से हमारे शहर हैं, उन्हें जो शहरी आधारभूत संरचनायें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पायी है । इस के लिये हमें लगातार काम करने की आवश्कता है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे और हम दो-तीन बिन्दुओं को केवल सूत्र में अपनी बात कहना चाहते हैं । महोदय, जब ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को नहीं हटाया गया तो शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी विकास को हटाने का कोई तुक नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र में टोला और संपर्क निश्चय योजना लागू है, उसी तरह से शहर में नाली गली निश्चय योजना लागू है, जो बड़ी सडकें हैं, आप ने गली शब्द का प्रयोग किया है ।

महोदय, शहरी क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं, वे सड़क की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, नली की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं जो नगर निकाय में जो सशक्त समिति है, उस में पदेन सदस्य के रूप में माननीय सांसद और विधायकों को निश्चित रूप से एक्ट को संशोधित कर के उन्हें जोड़ा जाय।

महोदय, हमारे कटिहार में दो जल मीनार हैं, संयोग से यहां पी0एच0ई0डी0 मंत्री भी हैं, पी0एच0ई0डी0 के प्रधान सचिव भी बैठी हुई हैं, आप के द्वारा नगर विकास की सारी राशि से 6 करोड़ की लागत से आज से दो वर्ष पहले दो जल मीनार बन कर आप की ओर देख रहा है और अभी तक नगर विकास हैंड ओवर लेने की स्थिति में नहीं है और आप बात करते हैं कि आप हर घर को नल से पानी देंगे । दो वर्षो से बना हुआ जल मीनार को जब आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो पिछले अक्टूबर से लागू सात निश्चय योजना में आप क्या करेंगे, यह स्पष्ट रूप से झलक रहा है । हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अभी पूर्व के ध्यानाकर्षण में नगर विकास मंत्री ने कहा कि जो योजनायें स्वीकृत है और पारित हैं, सारी योजनाओं पर काम होगा लेकिन हम चाहेंगे कि आप उस पर अपने भाषण में सारी स्थिति को स्पष्ट करें क्योंकि बिहार अभी भी अनिश्चय की स्थिति में है ।

आज मोतिहारी में फरवरी से नगर परिषद् के सफाईकर्मी हड़ताल पर है, उस के संबंध में सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । जो नव प्रोन्नत नगर परिषद् है, नगर निगम हैं, उसमें जो कृषि के क्षेत्र शामिल किये गये हैं, आप कर ले रहे हैं, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । उसके लिये एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए । जो हमारे सीमांत और लघु कृषक हैं उन से आप संपत्ति-कर के लिये उसे कर की नोटीस दिये हैं, आप इन्टरेस्ट इम्पोज कर रहे हैं, वह कहां से देंग ? खेत बेच करके भी आप को संपत्ति कर नहीं दे पायेंगे । अंत में महोदय, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कटिहार नगर निगम के बगल के पड़तैली गांव में 500 एकड़ जमीन में आप का जो गंदा जल है, उस के लिये आप की कोई स्पष्ट योजना नहीं है, उसके कारण 500 एकड़ जमीन, जो सीमान्त और लघु कृषकों का है, वह जल से भरा हुआ है, वे खेती नहीं कर पा रहे हैं, सरकार इसको निश्चित रूप से देखें ।

अंत में इतना कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है । केन्द्र सरकार की 9 योजनायें बिहार में लागू है । शहरी विकास में लागू है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईये । माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी । आप एक से दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कीजिये । सरकार का उत्तर होगा ।

टर्न-26/राजेश/25.3.17

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूँ ।

महोदय, हम नगर विकास पर चर्चा कर रहे हैं । कौन सा नगर, कौन सी चर्चा ? नगर के लिये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें से मुख्य हैं सड़क, स्वच्छ जल, सफाई, रोशनी, परिवहन आदि । हमलोग पटना में रहते हैं, जो बिहार की राजधानी है और यहां इन मूलभूत सुविधाओं में से कौन सी सुविधा है, सब लोग जानते हैं ।

हरेक शहर में प्रत्येक दिन कचरा जमा होता है, यदि उसके निष्पादन की व्यवस्था नहीं होगी, तो वह कचरा उस शहर के लिये फांसी जैसी हो जायेगी । अन्य शहरों को हम छोड़ दें, राजधानी पटना में ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है, शायद ही किसी मुहल्ले में कचरा फेंकने का स्थल निर्धारित हो । कुत्ते, सूअर, गाय, कौआ आदि पशु पक्षी ही पटना नगर निगम के कचरा निष्पादन के उपकरण हैं क्योंकि जो कचरा ये पशु पक्षी खाकर समाप्त करते हैं, वही कचरा निष्पादित होता है । मरे हुए

लावारिश पशुओं की दुर्गंध से जब सारा मुहल्ला त्राहिमाम् हो जाता है, तब उसे उठाया जाता है ।

आईये सड़क पर । यहां की सड़कें जो पथ निर्माण के अंतर्गत हैं कुछ हद तक वे ही ठीक हैं, बाकी सड़कें जर्जर हैं । एक अजीब बात है कि पटना में कौन सी सड़क किस विभाग की है, यह कोई नहीं जानता ।

नालों की तो दुर्दशा की पूछें ही नहीं । नाले जाम रहते हैं । बरसात आने के पूर्व बंदरबांट के उद्देश्य से जून में कुछ नालों की सफाई की जाती है और नाला का कचरा वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है । जब बारिश होती है, तो वह कचरा फिर नाला में चला जाता है और करोड़ों करोड़ रूपये की बंदरबांट हो जाती है ।

महोदय, सबसे हास्यास्पद स्थिति है देश-दुनिया एडवांस हो रही है । आगे के पचास वर्षों का विजन लेकर चल रही है लेकिन बिहार के नगर निकाय खास कर पटना नगर निगम तो 2001 की जनगणना के आधार पर योजनाओं के बारे में निर्णय ले रहा है।

पटना नगर निगम में पिछले वर्षों में जितने भी निगम आयुक्त आये, उन सबका एक ही उद्देश्य रहा एपार्टमेंट तोड़ना । अन्य नगर निगमों को तो छोड़ दें ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ।

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, नगर निगम द्वारा कोई भी ऐसा स्थल विकसित नहीं किया गया जिसके प्लाट की बिक्री की जा सके । अन्य शहरों को देखा जाय, तो उन शहरों में कालोनी बनाने से पहले आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाती हैं परंतु हमारे यहां उल्टा होता है । पहले बेतरतीब कालोनी विकसित होने दी जाती है, फिर उस पर हथौड़ा चलाने का काम किया जाता है । इन सब बातों का एक ही मकसद है भयादोहन ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ।

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, राज्य के नगर निगम नरक निगम बन कर रह गये हैं । दशहरा, दिवाली, छठ, ईद का आकलन पहले करके सफाई नहीं की जाती बल्कि अंतिम सप्ताह में

रात दिन जग कर काम करने का प्रदर्शन किया जाता है । जो काम रूटीन में हो सकता है उसको विशेष बनाया जाता है ।

महोदय, नगर निकाय को होल्डिंग टैक्स लेने का अधिकार है जिसे वह जबरन वसूलते हैं परंतु जो कर्त्तव्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है, उसे साफ छोड़ दिया जाता है ।

अध्यक्ष: अब आपका भाषण समाप्त हुआ । सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वाद-विवाद में माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, समीर कुमार महासेठ जी, अभय कुमार सिन्हा जी, अजीत शर्मा जी, व्यासदेव प्रसाद जी, महेश्वर प्रसाद यादव जी, चन्द्रसेन प्रसाद जी, संजीव चौरसिया जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, संजय सरावगी जी, विरेन्द्र कुमार सिन्हा जी, ललन पासवान जी, श्रीमती आशा देवी जी, डा0 मो0 नवाज आलम जी, वशिष्ठ सिंह जी, विजय कुमार खेमका जी, सत्यदेव राम जी, राजू तिवारी जी, तारकेश्वर प्रसाद जी एवं श्रीमती बेबी कुमारी जी ने भाग लिया, मैं सभी का जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है, उसको विधि सम्मत देखी जायगी और साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग, चूंकि जितनी बड़ी बिहार की आबादी है, उसमें ग्रामीणों क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है, शहरी आबादी जितनी होनी चाहिए, शहरी आबादी कम है । मैं भाषण देने से पहले एक शेर से स्वागत करना चाहता हूँ, चूंकि हमारे विपक्ष के साथी जब टेलर देने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि भागने की तैयारी में है, तो आज कुछ आग्रह भी करुंगा ।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग, जब से यह सरकार बनी, पहले एन0डी0ए0 की सरकार थी, हमलोग महागठबंधन की सरकार में आये लेकिन ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री रहे, अब किस हालात में हमको मंत्रालय मिला, किस स्थिति में मंत्रालय मिला, उसको मैं एक शेर के द्वारा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ :

''कश्ती चलाने वालों ने जब पतवार दिये, हमें लहर-लहर तूफान मिले
और मौज-मौज मझधार मिले, फिर भी दिखाया है हमने,

फिर दिखा देंगे सबको , इन हालातों में भी आता है दरिया पार करने हमें।''

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी माननीय सदस्यों को, चूंकि आप लोगों ने जिस तरह से चलाया, कभी ठीक से बैठे नहीं, तो हालात तो गड़बड़ होगी ही । अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष और जिनके कुशल नेतृत्व में आज महागठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है, मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चूंकि पहली बार सत्ताधारी दल के सत्ताधारी पार्टी का कोई विधायक मंत्री है और पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर इस विभाग को चाहते हैं कि विभाग चूंकि शहरी एरिया, चूंकि शहर का जो क्षेत्र होता है, नगर निकाय जो होती है, वह आईना की तरह होती है और आईना धुंधला जब हो जायेगा, तो जो स्टेट की संस्कृति होती है, सुन्दरता होती है, उसकी खूबसूरती होती है, चूंकि देश विदेश के लोग शहर में ही आते हैं, उसकी संस्कृति की जो सुन्दरता होती है, वह केवल शहर से ही पता चलता है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार ने जिस तरह से गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से आगे कदम बढ़ाने का काम किया है, मैं पहले बताना चाहूंगा कि हमारे बिहार राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं, कार्यरत नगर निकायों की संख्या 140 है, जिसमें 11 नगर निगम हैं, 42 नगर परिषद् है और 87 नगर पंचायत हैं, सभी नगर निकायों में कुल वार्डों की संख्या 3323 है, आप बता रहे थे 2500 लेकिन 3323 है और अभी उत्क्रमण यानि प्रमोट जो किया जा रहा है, उसकी संख्या नगर परिषद् छपरा को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है, तीन नगर पंचायत बख्तियारपुर, बरबीधा एवं फतुहा को नगर परिषद् में उत्क्रमित किया गया है, साथ ही नगर पंचायत बारसोई एवं हरनौत का गठन किया गया है, नगर पंचायत महनार एवं बॉका को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने हेतु प्रारुप/अधिसूचना निर्गत की गयी है, पालीगंज को नहर पंचायत गठित करने हेतु प्रारुप प्रकाशन किया गया है, तो जिसतरह से आपलोगों ने कहा कि बिहार में अभी तक कोई काम नहीं हुए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परफौरमेंस ग्रांट जो होता है भारत सरकार का, जो हर स्टेट को अवार्ड दिया जाता है, परफौरमेंस अवार्ड दिया जाता है, उसमें बिहार को भी परफौरमेंस ग्रांट मिला है, तो यह एक तरह से अवार्ड हुआ, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि बिहार में काम नहीं हो रहा है, तो बिहार ने अच्छा काम किया है तभी तो अवार्ड मिला है, ग्रांट मिला है..............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कोई दया नहीं करती है, भारत सरकार कोई कृपा नहीं करती है, हर स्टेट का अपना अधिकार होता है, पैसा देना, यहॉं से जो टैक्स जाता है, फिर विकासात्मक कार्य में लौट कर आती है, तो कोई कृपा भारत सरकार नहीं करती है, यह हमारा अधिकार है और हर स्टेट का अपना अधिकार होता है, पैसा देना भारत सरकार का फर्ज है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान आज तक 1961 से अभी तक मास्टर प्लान नहीं बना था लेकिन हमारे आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में मास्टर प्लान, 2031 इस बार स्वीकृत हुई, जो बहुत बड़ी चीज है, चूंकि एन0जी0टी0 के द्वारा जो बड़े-बड़े भवन बनाये जा रहे थे, उसको रोक दिया गया था और विकासात्मक कार्य में जो बहुत सारी त्रुटियॉं हो रही थीं

क्रमशः

टर्न-27/सत्येन्द्र/25-3-17

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री(क्रमशः): इससे हमलोगों को बहुत फायदा होगा और इसका जो पूरे मास्टर प्लान का, महानगर का जो एरिया है, प्राधिकार का गठन किया गया है । पटना मास्टर प्लान का सीमा क्षेत्र निम्नवत है: उत्तर पश्चिम छोर में मनेर प्रखंड के रामपुर से खुसरूपपुर प्रखंड के हरदासपुर बिगहा तक है। दक्षिण में पश्चिम छोर में बिहटा प्रखंड के नत्थुपुर से फतुहा प्रखंड के नंदाचक होते हुए पूर्वी छोर दौलतपुर प्रखंड फतुहा तक है। पूरब में दक्षिण छोर में फतुहा प्रखंड के दौलतपुर से खुसरूपुर प्रखंड के हरदासपुर बिगहा तक है । पश्चिम में दक्षिण छोर में बिहटा प्रखंड से नत्थुपुर से मनेर प्रखंड के हल्दी छपरा तक है । माननीय सदस्यगण, बार-बार चूंकि दोनों सदन में माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न आते रहता था बस स्टैंड के संबंध में, आई0एस0बी0टी0 के संबंध में, हमलोगों ने आदरणीय हमारे नेता के नेतृत्व बस स्टैंड की स्वीकृति हुई और उस पर तेज गति से उसका टेंडर भी हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया है और कार्य प्रारम्भ भी हो रहा है । वह 331 करोड़ 61 लाख की लागत से पटना में आई0एस0बी0टी0 बन रहा है उसके अतिरिक्त राज्य के 39 शहरों में बस स्टैंड निर्माण की योजना हमने स्वीकृत किया है और 9 शहरों में भभुआ, नासरीगंज, मखदुमपुर, जहानाबाद, बांका, सुपौल, बेलसंड, कटिहार एवं बोधगया में निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 22 शहरों सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा, लहेरियासराय, चकिया, अरेराज, सीवान, मोतिहारी, सीतामढ़ी, डेहरी, डालमियानगर, दाउदनगर, नोखा, बिहारशरीफ, झाझा, बेगुसराय, नवगछिया, अरवल, मुंगेर, औरंगाबाद, सासाराम एवं पटना शहर स्थित मालसलामी बस स्टैंड का निर्माण कार्य

प्रगति पर है । (व्यवधान) तो कार्य चल रहा है वह तो बगल में प्रेम बाबू हैं उनसे पूछ लीजिये कि किस स्थिति में किस रेस में चल रहे थे, हम तो कम से कम 60 के स्पीड में चल रहे हैं, प्रेम बाबू 20 के स्पीड में चल रहे थे । बगल में प्रेम बाबू हैं पूछ लीजिये कि कितना के स्पीड में चल रहे थे । स्मार्ट सिटी के संबंध में महोदय मैं कहना चाहूंगा । स्मार्ट सिटी का प्रपोजल बिहार सरकार के द्वारा एक वर्ष पूर्व भारत सरकार को दी गयी थी और हमने स्वयं जाकर के शहरी विकास मंत्री आदरणीय बैंकया नायडू जी से जाकर भेंट किये थे और भेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पटना बिहार की राजधानी है इसलिए पटना में मेट्रो अतिआवश्यक है और पटना के लिए मेट्रो की स्वीकृति होगी और पुनः हमलोगों ने जितना फौर्मलिटी मांगा गया था, जितना पेपर मांगा गया था सभी फौर्मलिटी पूरा करने के काम किये वहां पर, उसके बाद भी एक वर्ष हो गये और फिर दो महीना पहले हम गये थे भारत के शहरी विकास मंत्री जी से भेंट करने के लिए उनको हमने कहा कि सर ,आप बगल में नागपुर है उसको 15 दिन में मेट्रो की स्वीकृति देते हैं, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति दे दिये लेकिन मुझे साल भर हो गया, एक वर्ष हो गया दौड़ते दौड़ते आखिर आप पटना के लिए क्यों नहीं मेट्रो की स्वीकृति देने का काम कर रहे हैं । हमने यह भी कहा कि इसका मतलब है कि हमारे साथ या तो दलगत भावना से प्रेरित होते हैं या बिहार के साथ शौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रक्रिया है और आदरणीय आपके जो नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार इतने अच्छे लीडर हैं चूंकि उनके साथ हम 17 वर्ष रहे हैं वह काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको इच्छाशक्ति भी है, भारत में बहुत कम लीडरों की होती है वह काम करने वाला व्यक्ति हैं इसलिए मैं शौतेलापन व्यवहार नहीं करता हूँ जो काम करेंगे वहां देंगे, प्रक्रिया है प्रक्रिया में लेट हो रही है । हमलोगों को पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठने के लिए भी कहा तो पदाधिकारी के पास भी बैठा और उनसे आग्रह भी किया जितना जल्दी हो सके वहां मेट्रो की स्वीकृति देने का काम करें तो मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि वे जल्द से जल्द मेट्रो ट्रेन की सैद्धांतिक सहमति दें जिससे कि हम यहां कार्य प्रारम्भ करें । हम इतना कहें कि यदि पैसा देना नहीं चाहते हैं बिहार सरकार को आप पैसा मत दीजिये सिर्फ सैद्धांतिक सहमति दीजिये, हम अपने पैसा से काम करवा लेंगे मेट्रो की लेकिन उसके बाद भी सैद्धांतिक सहमति नहीं देना मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार के साथ शौतेलापन व्यवहार है । महोदय, इस तरह की बात होती है, दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, हमारे माननीय सदस्य जितने लोग यहां अपनी अपनी क्षेत्रों की समस्या के बारे में बतलाया है, उनलोगों को भी डिटेल में बताने का हम काम करेंगे और हमलोगों ने सबसे (व्यवधान) हमलोगों ने सब जगह आपके झारखंड में बगल में जो सम्पत्ति शुल्क का जो होल्डिंग टैक्स था उसको बढ़ाने का काम किये हमलोग गरीब राज्य रहते हुए भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी

के नेतृत्व में हमलोगों ने होल्डिंग टैक्स 31मार्च ,2013 तक का सूद माफ कर दिये और यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है । महोदय, होल्डिंग टैक्स का जो सूद हमलोग माफ किये हैं, 31मार्च, 2013 तक होल्डिंग टैक्स का सूद पूरे बिहार में सभी नगर निकाय में माफ कर दिया है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । (व्यवधान) आपके समय में आया था लेकिन जमीन पर नहीं उतरा, हमलोग जमीन पर उतारने का काम किये । काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए सिर्फ हल्ला करने से काम नहीं चलेगा और आप लोग कहे थे (व्यवधान) सभी जगह जितने नगर निकाय हैं सभी जगह हमलोगों ने मास्टर प्लान बना रहे हैं सभी जगह । उसका भी कार्य चल रहा है दूसरा (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: प्रमोद जी, बैठिये मंत्री जी का सुन तो लीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रकाश पर्व में चूंकि हमलोग नोडल एजेंसी थे हमारा विभाग नोडल एजेंसी था...

अध्यक्ष: मंत्री जी और माननीय सदस्यगण, कृपया एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करें । मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: प्रकाश पर्व का नोडल एजेंसी हमलोग थे और मैं सदन के माध्यम से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूॅं ।

अध्यक्ष: कोई आदमी बैठे बैठे नहीं बोलिये, सदन का कार्य बाधित होता है ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: जब 350 वां गुरू गोविंद सिंह जयंती का शुभारम्भ हुआ (व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: प्रेम बाबू, बैठे बैठे बोलने के लिए नहीं कहे तो आप खड़े क्यों हो गये ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: 350 वां गुरूगोविन्द सिंह जी की जयंती जिस विजन और जिस इच्छा शक्ति से मनाया गया जिस विजन और इच्छा शक्ति से बिहार सरकार मनाने का काम किया यहां की गठबंधन सरकार ने और (व्यवधान) जिसकी चर्चा देश विदेश..

अध्यक्ष: फिर बोल ही रहे हैं आप लगातार कमेंट्री क्यों करते हैं ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: सभी जगह हुआ इतना ही महोदय, बिहार के जब आम जनता कोई दूसरे स्टेट में जाते हैं और जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं तो जिस तरह से बिहार के लोग जाते हैं तो उसको भगवान की तरह मानता है सिर्फ इसीलिए कि यहां के जो पर्व हुआ था इतना लोग सम्मान के दृष्टिकोण से मैं इसमें मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूॅं, पक्ष विपक्ष के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूॅं और बिहार के आम नागरिक को भी धन्यवाद देना चाहता हूॅं कि 350 वां जयंती में हर व्यक्ति यह समझ रहा था मैं भी उस पर्व में सम्मिलित हूॅं और उसी तरह से आस्था के साथ सभी लोग लीन हो गये थे, चाहे रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो या टेम्पू वाला हो या गाड़ी वाला हो इसका ज्वलंत उदाहरण...

श्री संजय सरावगी: हमलोग भी थे ।

अध्यक्ष: आपको शामिल कर के ही बोल रहे हैं । जब बिहार का हर नागरिक बोल रहे हैं शामिल था तो आप भी न थे उसमें ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, एक कहानी बताना चाहता हूँ । एक स्कूटर वाला जा रहा था न्यू मार्केट पटना , बगल से एक सरदार जी जा रहे थे बैग लेकर, वह उनसे पूछा कि स्टेशन किधर है तो उन्होंने कहा कहां जाना है, उसने कहा कि स्टेशन जाना है तो उस श्रद्धालु को उसने अपने मोटरसाईकिल पर चढ़ाकर के स्टेशन छोड़ने का काम किया और उसकी चर्चा इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी सराहना बिहार की हुई, मैं समझता हूँ यह विजन का काम है, इच्छाशक्ति का काम है और मैं स्वयं बताता हूँ महोदय, एक बजे रात में एक दिन गये बिना प्रोटोकोल के नियम को तोड़े हुए अंदर गये वहां पटना सिटी में और जब हम स्टाफ को चेक किये कि हमारा स्टाफ है कि नहीं है तो एक बजे रात में हमारे विभाग का स्टाफ खड़ा होकर काम करा रहा था और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि आजतक हमलोगों ने जीवन में इतनी भीड़, मेला में इतना भीड़ नहीं देखे थे (क्रमशः)

टर्न-28/मधुप/25.03.2017

...क्रमशः...

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : इतनी सुन्दरता के साथ मनाया गया तो मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका उसमें मौन समर्थन था, विकास में भी मौन समर्थन करने का काम कीजिये । जिस तरह से मीडिया में, बिहार का लोग खाता है तो बिहार का जपना चाहिये लेकिन जिस तरह से आपलोग बिहार के विरोध में बोलते हैं, उसका बहुत ही गलत संदेश दूसरे स्टेट में जाता है, केन्द्र में जाता है गलत संदेश । इसलिये ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जो सच्चाई है, वह बोलना चाहिये । हमेशा वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : हमलोग बिहार के विरोध में नहीं बोलते हैं, सरकार के गलत काम के विरोध में बोलते हैं ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : बोलते हैं न आखिर ।

महोदय, उसी तरह से बिहार सरकार के प्रशासन ने जो छठ पर्व इस बार मनाया, हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो भिन्न-भिन्न घाटों का निर्माण कराया गया, वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिये जो व्यवस्था की गई थी, जितनी व्यवस्था की गई थी, समझिये ऐतिहासिक थी, कहीं कोई घटना नहीं हुई ।

माननीय सदस्यगण, चूँकि मैं देखता हूँ कि कुछ ट्रेलर की सुगबुगाहट हो रही है तो मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों के लिये एक शेर कहना चाहता हूँ और शेर के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम शेर के माध्यम से रूकें ।

(व्यवधान)

हम बोलेंगे, अभी बैठिये तो । सुनियेगा तब न । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से -

तुम रूठे-रूठे से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की,
मैं जिंदगी गिरवीं रख दूँगा, तुम कीमत तो बताओ मुस्कुराने की ।

चूँकि ये लोग सब दिन भागने का काम करते हैं, रण छोड़ कर भाग जाते हैं जब सरकार का जवाब होने लगता है, आपलोगों की हिम्मत नहीं है सरकार की बात सुनने की । मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप रूकिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने मुस्कुराने के लिये कहा तो आप इतने तनाव में दिखने लगे ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, उसका भी जवाब दूँगा । आप स्थिर तो रहिये ।

महोदय, कालचक्र पूजा जिस तरह से बोधगया में मनाया गया, वह ऐतिहासिक था । वहाँ पर आयोजन में देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु आये थे, वहाँ पर जिस तरह से बिहार सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी रहने की, घूमने की, वह भी एक ऐतिहासिक था । बिहार सरकार जो-जो काम कर रही है यहाँ पर, सारे जगह देश-विदेश में इसकी चर्चाएँ होती हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सात निश्चय पर काम किया है, यह सात निश्चय को पूरा देश अपनाने का काम करेगा । सात निश्चय पूरा होने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समस्या जमीन पर रह जायेगी और सात निश्चय गाँव से लेकर शहर तक सब फुलफिल करने का काम करेगा ।

जहाँ तक माननीय सदस्य, सरावगी जी कह रहे हैं.....

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : सात निश्चय धोखा है, महोदय ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : नहीं-नहीं । अल्प-सूचित प्रश्न में जो उन्होंने उठाया था, उसका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिये । अल्प-सूचित प्रश्न में माननीय सरावगी जी ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहा था....

श्री ललन पासवान : माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, आवास विभाग का भूखण्ड खाली है कंकड़बाग में, सरकारी बाजार रेट पर माननीय सदस्यों को आवंटित कीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कोई दूसरा शेर भी है ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने विपक्ष के साथियों से, हमारे भारत में पशु शवदाह गृह उत्तर भारत में कहीं नहीं है, पहला पशु शवदाह गृह बिहार सरकार ने बनाने का काम किया, हमारे यहाँ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा उसका निर्माण कराया गया है । शहर में कहीं भी पशु मरेगा, उसको उठाकर लाकर शवदाह गृह में जलाया जायेगा । यह व्यवस्था की गई है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, कहीं कोई सुविधा विभाग की ओर से नहीं दी गई है, वेंडिंग जोन की सुविधा नहीं दी गई है । हमलोग सरकार के जवाब का बहिष्कार करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : आप बैठिये, हम उसी पर बोल रहे हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब से झारखंड अलग हुआ, माननीय सदस्य चले गये, मैं उन्हीं के प्रश्न का उत्तर दे रहा था । झारखंड बँटने के बाद कोई ऐसा स्कीम नहीं बना था जिससे कि काम तेज गति से हो लेकिन अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि अब नई आवास नीति लागू हो रही है, अभी जा रहा है प्रोपोजल, जल्द से जल्द स्वीकृति होगी और आवास नीति लागू होने के बाद सभी योजना जो आवास विभाग के हैं, वह चालू हो जायेगा । गरीब लोगों के स्लम बस्ती के लिये भी हमारी सरकार विचार कर रही है । जिस तरह से हमलोग पी0पी0पी0 मोड पर बनाकर गरीब-गुरबा के लिये भी हमलोग, कुछ दिनों की बात है, उसका टेन्डर निकालेंगे, वह भी काम होगा । बिहार सरकार अंतिम व्यक्ति तक के लिये विचार कर रही है कि किस तरह से उसको देखें ।

महोदय, उसका ज्वलंत उदाहरण बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतिहास कायम करने का काम किया, नदी में नाव का पतवार मांझी होता है, नाव खेवने का काम करता है लेकिन एक ऐसे मांझी जी थे जिनको पूरे बिहार का पतवार दे दिये चलाने के लिये, लेकिन वह चाहें कि बीच में ही डूबा दें तो धन्यवाद देते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, वे समझ गये हैं कि डूबाने वाला है, उसको बचाने का इन्होंने काम किया । जो सबसे अंतिम व्यक्ति था जिसके कल्याणार्थ, जिसको एक इतिहास कहिये, अपना कुर्सी-गद्दी किसी व्यक्ति को कोई दे दे लेकिन वह व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर, उनकी किस तरह से स्थिति बनाई गई, यदि उस समय नहीं चेता जाता तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हानि कर रहा था सरकार के लिये, इसका कारण क्या हुआ कि पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ा । आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी इलाज कराने के लिये विदेश जा रहे हैं, उनको किसी पर इतना

विश्वास नहीं हुआ बिहार की घटना लेकर, वे अपने बहन जो सर्विस कर रही है, इस्तीफा दिलाकर उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं । लोग विश्वास इस तरह से खो देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और जो लीडर, जो नेता विश्वास करे, उसपर खरा उतरना चाहिये ।

मैं आग्रह करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से नगर विकास एवं आवास विभाग काम कर रहा है, महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो अंतिम व्यक्ति गरीब-गुरबा हैं, उनके लिये आवास के बारे में, सभी के बारे में सरकार सोचेगी, जो विधि सम्मत होगा उसपर कार्रवाई करने का काम करेंगे, उसको करने का काम करेंगे ।

श्री समीर महासेठ जी की जो बात थी, मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र के किंग्स कैनाल का, वाट्सन कैनाल बनाने का, वह स्वीकृत होने जा रहा है । जल्द उसकी स्वीकृति होगी और उसका काम भी होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समय हो गया है ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय । साथ-ही, अरूण बाबू से आग्रह करेंगे कि कटौती प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करेंगे और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास पेपर है उसको प्रोसिडींग का पार्ट बना दिया जाय ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी द्वारा सदन पटल पर रखे गये सभी लिखित दस्तावेज उनके भाषण का अंश बनेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से घटायी जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

टर्न-29/आजाद/25.03.2017

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 43,35,01,21,000/- (तैंतालीस अरब पैंतीस करोड़ एक लाख एक्कीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 45 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य के आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है। गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्त्तन का कारण बनती है, साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गई हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद एवं 87 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनाएँ लागू की गई हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सात निश्चयों में से तीन निश्चय शामिल हैं, जो निम्नवत् हैः-

1. <u>मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना</u> :- राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार तक नल का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' प्रारम्भ की गयी है, जिसका विधिवत् शुभारम्भ दिनांक- 27.09.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 कुल 109 नगर निकायों के 2090 वार्डों में वासित परिवारों के नल को जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹71319.39279 लाख (सात सौ तेरह करोड़ उन्नीस लाख उनचालीस हजार दो सौ उनासी रु०) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी है।

2. <u>मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना</u> :- राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की नाली एवं गली से जोड़ने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना'' प्रारम्भ की गयी है, जिसका विधिवत् शुभारम्भ दिनांक- 28.10.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित कुल ₹19000.00 लाख (एक सौ नब्बे करोड़ रु०) मात्र कुल 140 नगर निकायों में जनसंख्या के आधार पर वितरित करते हुए आवंटित किया गया। नगर निकायों द्वारा वार्ड सभा की अनुशंसा के आधार पर दीर्घकालीन योजना तैयार की गयी है। प्राथमिकता सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

3. **प्रत्येक शहरी परिवार के घरों के लिए शौचालय निर्माण** :– राज्य के सभी शौचालय विहीन शहरी परिवारों को वर्ष 2018–19 तक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके तहत कुल ₹7.52863 लाख (सात लाख बावन हजार आठ सौ तिरेसठ रु०) परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराये जायेंगे।

अभी तक ₹64,305 (चौंसठ हजार तीन सौ पाँच रु०) व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा ₹1,18,646 (एक लाख अठारह हजार छः सौ छियालीस रु०) व्यक्तिगत शौचालय निर्माणाधीन है।

भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में केन्द्र के अनुदान राशि 4000/– रु० प्रति शौचालय तथा राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री ने अनुदान 1333/– प्रति शौचालय उपलब्ध कराने की नीति भारत सरकार द्वारा बनायी गयी थी। किन्तु इसके व्यापक महत्ता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8000/– रु० प्रति शौचालय सहायता राशि देने का निर्णय लिया।

ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय बनाने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है वैसे परिवार को सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक परिवार को एक–एक सीट उपयोग करने की सुविधा दी जाय, जिसकी साफ–सफाई भी उसी परिवार द्वारा की जायेगी। अबतक 45 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 73 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है।

साथ ही प्रत्येक शहर में व्यवसायिक केन्द्रों के एक किलोमीटर की परिधि में एक सार्वजनिक शौचालय बनाना प्रस्तावित है, जिसमें 05 सीट पुरूषों के लिए तथा 02 सीट महिलाओं के लिए होगी। इसके अतिरिक्त पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग मूत्रालय उपलब्ध होंगे। अबतक 18 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 43 सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है।

4. **नागरिक सुविधा** :– राज्य की राजधानी पटना में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पटना शहर के पहाड़ी मौजा में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल (ISBT) का निर्माण कुल ₹33161.00 लाख (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) मात्र की योजना से कराया जा रहा है। साथ ही 39 शहरों में बुडको द्वारा अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जा रहा है, जिसमें से 09 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

5. **श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह** :– माह दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 के मध्य सिखों के दशमेस गुरु श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की जन्म स्थली पटना साहिब में 350वीं जयंती समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया था। सफल आयोजन हेतु विभाग द्वारा कुल ₹8832.50797 लाख (अठासी करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार सात सौ संतानवे रु०) मात्र की योजनाओं को

स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त देश विदेश से आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आयोजन अवधि में मुफ्त रिंग बस सेवा सेवा उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर अन्य सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी। साथ ही श्रद्धालुओं के आवासन हेतु मुक्त टेंट सिटी का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएँ, हेल्प डेस्क, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का भी प्रबंध किया गया। आयोजन में देश विदेश से आये लाखों श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार द्वारा की गयी तैयारियों को अभूतपूर्व बताया तथा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सफल आयोजन हेतु बिहार सरकार की प्रशंसा की गयी।

6. **<u>छठ पर्व, 2016</u>** :– पटना शहर में छठ पर्व का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला प्रशासन, बुडको एवं पटना नगर निगम, पटना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नागरिक सुविधा से संबंधित कार्य यथा– छठ घाटों का निर्माण, चेंजिग रूम, अस्थायी शौचालय, अस्थायी पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग, सफाई व्यवस्था, छठ घाटों पर पहुँचने के लिए पहुँच पथ का निर्माण आदि कार्य कराये गये है। इस वर्ष छठ पर्व पर राज्य सरकार द्वारा की गयी तैयारियों एवं व्रतियों की सुविधा के लिए किये गये कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। विभाग आगे इससे भी बेहतर व्यवस्था के लिए कृतसंकल्पित है।

7. **<u>कालचक्र पूजा, 2017</u>** :– बौद्धो के धर्म स्थली बोधगया में कालचक्र पूजा, 2017 का सफल आयोजन माह जनवरी, 2017 में सम्पन्न हुआ, जिसमें देश–विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उक्त आयोजन को सफल बनाने हेतु बोधगया नगर क्षेत्र में अवस्थित सड़को के किनारे पेभर ब्लॉक लगाने हेतु कुल ₹81.96865 लाख की योजना स्वीकृत की गयी। साथ ही सफाई सहित अन्य नागरिक सुविधाएँ यथा– प्रकाश व्यवस्था, सी०सी०टी०वी० का अधिष्ठापन, स्ट्रीट लाईट की मरम्मति आदि कार्यों के लिए कुल ₹120.00 लाख आवंटित किया गया।

8. **<u>स्मार्ट सिटी योजना</u>** :– इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर का प्रस्ताव स्वीकृत है। भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु SPV का गठन कर लिया गया है। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 अनुपात में है। इसके लिए केन्द सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ₹8800.00 लाख (अठासी करोड़ रु०) स्वीकृत है। पटना शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

9. **<u>पटना मेट्रो रेल परियोजना</u>** :– इस परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति राज्य मंत्रिपरिषद् से प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

10. बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा नागरिक सुविधायें त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं :–
बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2017 लागू किया गया है, जो 01 फरवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

11. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के क्रम में 12 हजार से अधिक जनसंख्या वाले अर्हत्ता प्राप्त ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही कतिपय पूर्व से गठित नगर निकायों के उत्क्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में निम्नलिखित निकायों को उत्क्रमित/गठित किया गया है :–

(i) नगर परिषद्, छपरा को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया।

(ii) नगर पंचायत, बख्तियारपुर एवं फतुहा को नगर परिषद् में उत्क्रमित किया गया।

(iii) नगर पंचायत, बारसोई एवं हरनौत का गठन किया गया।

(iv) नगर पंचायत, बरबीघा को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना निर्गत की गयी।

12. वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्तावित बजटः– नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के व्यय वहन हेतु कुल ₹43,35,01,21,000.00 (तैंतालीस अरब पैंतीस करोड़ एक लाख इक्कीस हजार रुपये) का उपबंध माँग संख्या– 48 के अंतर्गत प्रस्तुत है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए ₹16,00,40,15,000.00 (सोलह अरब चालीस लाख पंद्रह हजार रुपये) तथा योजना व्यय के लिए ₹27,34,61,06,000/– (सताईस अरब चौंतीस करोड़ एकसठ लाख छः हजार रुपये) का प्रस्ताव है।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय।

(महेश्वर हजारी),
मंत्री,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार

- कश्ती चलाने वालों ने जब पतवार दी हमें,
  लहर लहर तुफान मिले और मौज-मौज मँजधार हमें।
  फिर भी दिखाया है हमने और फिर दिखा देंगे सबको,
  इन हालातों में भी आता है दरिया पार करने हमें।।

- ढलती उम्र में इश्क हो तो अचरज नहीं गालिब।
  पुरानी गेंदें ही ज्यादा रिवर्स स्वींग होती है।।

- तकाजा है वक्त का कि तुफान से जूझो।
  कहाँ तक चलोगे किनारे-किनारे।।

- हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम।
  वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता।।

- कुछ तो गुल खिलाए हैं, कुछ अभी खिलाने हैं।
  पर बाग में अब भी कुछ काँटे पुराने है।।

- तुम रूठे रूठे से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की।
  मैं जिन्दगी गिरवी रंग दूँगा, तुम कीमत तो बताओं मुस्कुराने की।।

- कुछ ऐसे भी मंजर हैं, तारीख की नजरों में।
  लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।।

मानननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य के आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है। गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्त्तन का कारण बनती है, साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गई हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद एवं 87 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगामी 4 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनाएँ लागू की गई हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सात निश्चयों में से तीन निश्चय शामिल हैं, जो निम्नवत् हैः–

1. **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना** :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार तक नल का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारम्भ की गयी है, जिसका विधिवत् शुभारम्भ दिनांक– 27.09.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 109 नगर निकायों के 2090 वार्डों में वासित परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹71319.39279 लाख (सात सौ तेरह करोड़ उन्नीस लाख उनचालीस हजार दो सौ उनासी रु०) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी है।

2. **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना** :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की नाली एवं गली से जोड़ने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" प्रारम्भ की गयी है, जिसका विधिवत् शुभारम्भ दिनांक– 28.10.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित कुल ₹19000.00 लाख (एक सौ नब्बे करोड़ रु०) मात्र कुल 140 नगर निकायों में जनसंख्या के आधार पर वितरित करते हुए आवंटित किया गया। नगर निकायों द्वारा वार्ड सभा की अनुशंसा के आधार पर दीर्घकालीन योजना तैयार की गयी है। प्राथमिकता सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

3. **प्रत्येक शहरी परिवार के घरों के लिए शौचालय निर्माण** :– राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जन्मदिवस 02 अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जारी किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी नगर निकाय में लागू की गयी है, इसके तहत निम्नलिखित कार्य किया जाना है :–

(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण। (ii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण।
(iii) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। (iv) ठोस कचरा प्रबंधन।
(v) सूचना, शिक्षा एवं जन–जागरूकता। (vi) क्षमता वृद्धि तथा प्रशासनिक कार्य।

(i) **व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण** – वैसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है, जिसके कारण वे खुले में शौच को मजबूर है, वैसे शौचालय विहिन सभी परिवारों को चार वित्तीय वर्ष 2015–2019 तक शौचालय उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है, जो वर्षवार इस प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष		**प्रति वर्ष शौचालय कक्ष**
2015–16	–	1 लाख
2016–17	–	2 लाख
2017–18	–	2 लाख
2018–19	–	2.52863 लाख
कुल	–	7.52863 लाख

चालू वित्तीय वर्ष में 64305 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 118646 व्यक्तिगत शौचालय निर्माणाधीन है।

- **राशि :**– व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में केन्द्र के अनुदान राशि 4000/– रु० प्रति शौचालय तथा राज्य से अनुदान 1333/– प्रति शौचालय उपलब्ध कराना प्रस्तावित था। किन्तु बिहार सरकार द्वारा इसकी महत्ता को देखते हुए 8000/– रु० प्रति ईकाई सहायता राशि दी जा रही है। योजना के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर हर पखवाड़े शिविर आयोजित किये जाते है, जिसमें चयनित किये गये पात्र लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाती है। उन्हें कार्यादेश निर्गत की जाती है तथा कार्यादेश के बाद नींव खुदाई का कार्य पूर्ण करने पर Geo Tag फोटोग्राफ के आधार पर 7500/– रु० RTGS के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है तथा निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने के बाद शेष राशि 4500/– रु० द्वितीय किश्त के रूप में लाभार्थी के खाते में दी जाती है।

(ii) **सामुदायिक शौचालय** – ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय बनाने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है वैसे परिवार को सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक परिवार को एक–एक सीट उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी देख–रेख का दायित्व परिवार के मुखिया की होगी। चालू वित्तीय वर्ष में 45 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 73 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है।

- **राशि :**– सामुदायिक शौचालय के निर्माण की अनुमानित लागत प्रति सीट ₹98000.00 (अंठानवे हजार रु०) है, जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रांश से ₹39200.00 (उनचालीस हजार दो सौ रु०) प्रति सीट अनुदान के रूप में प्राप्त होगा एवं शेष राशि नगर निकाय वहन करेगा।

(ii) **सार्वजनिक शौचालय** – अनुमानतः प्रत्येक शहर की जनसंख्या का 5 प्रतिशत लोग अन्य स्थानों

से शहर में आते हैं और दैनिक गतिविधियों के पश्चात् वापस चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक शहर में व्यवसायिक केन्द्रों के एक किलोमीटर की परिधि में सार्वजनिक शौचालय बनाना प्रस्तावित है, जिसमें 05 सीट पुरूषों के लिए तथा 02 सीट महिलाओं के लिए होगी। इसके अतिरिक्त पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग मूत्रालय उपलब्ध होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में 18 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 43 सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन हैं।

- **राशि** :– सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण PPP मोड में होना है। नगर निकायों द्वारा निजी संस्था को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा सार्वजनिक शौचालय के तीनों दीवारों पर विज्ञापन का अधिकार दिया जायेगा साथ ही सेवा शुल्क लेने का अधिकार दिया जायेगा।

- केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहरी परिवार के घरों में शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय ₹4000.00 (चार हजार रु०) स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इसे निश्चय योजना का अंग मानते हुए प्रति शौचालय ₹8000.00 (आठ हजार रु०) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक शौचालय निर्माण हेतु कुल ₹12000.00 (बारह हजार रु०) दिये जायेंगे। इस योजना के लिए राज्यांश मद में ₹160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रु०) का बजट प्रस्ताव है।

4. **नागरिक सुविधा** :– राज्य की राजधानी पटना में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पटना शहर के पहाड़ी मौजा में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के निर्माण के हेतु कुल ₹33161.00 लाख (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार की गारंटी पर हुडको से ऋण लेने की कार्रवाई बुडको द्वारा की जा रही है।

5. **श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह** :– माह दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 के मध्य सिखों के दशमेस गुरू श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की जन्म स्थली पटना साहिब में 350वीं जयंती समारोह का सफल आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया। विभाग द्वारा इस आयोजन में शामिल अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय कर इस आयोजन को सफल रूप से सम्पन्न किया गया। इस आयोजन में विभाग द्वारा कुल ₹8832.50797 लाख (अठासी करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार सात सौ संतानवे रु०) मात्र की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त देश विदेश से आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आयोजन अवधि में मुफ्त रिंग बस सेवा उपलब्ध करायी गयी। साथ ही आयोजन में शामिल अन्य विभागों द्वारा श्रद्धालुओं के आवासन हेतु टेंट सिटी का निर्माण, शौचालय की सुविधा, हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य सुविधायें, सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि का भी प्रबंध कराया गया।

6. **गैर योजना** :– पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के नगर निकायों को प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹46292.50 लाख (चार सौ बासठ करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) उपलब्ध कराया जा चुका है तथा द्वितीय किस्त विमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

7. **केन्द्र प्रायोजित योजना :–**

(i) **IHSDP (समेकित आवास एवं मलीन बस्ती का विकास कार्यक्रम) :–** IHSDP योजना के अधीन बिहार में 28 शहरों के लिए 32 परियोजनायें भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गयी है। इन 32 परियोजनाओं में कुल 28623 आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु कार्य चालू है। इसमें HPL के द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे 14 परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है। शेष 16 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर निकायों के माध्यम से सीधे लाभुकों के द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। इसके लिए शिविर के माध्यम से लाभुकों के बीच धनराशि उपलब्ध कराया जा रहा है। अबतक नगर निकायों के द्वारा कुल 47564.87 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है। कुल स्वीकृत 28623 आवासीय इकाईयों में से अबतक 11041 आवासीय इकाई का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(ii) **DAY-NULM (दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) :–** "दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)" योजना पूर्व से चयनित 42 नगर निकायों के अतिरिक्त राज्य के शेष नगर निकायों में भी लागू किया गया है। योजना के अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक (EST&P) के अन्तर्गत शहरी गरीब युवक/युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को प्रशिक्षणदाता संस्था द्वारा नियोजित एवं एक वर्ष तक अनुश्रवण भी किये जाते हैं। वर्ष 2015–16 से अब तक 27144 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 6179 का प्रशिक्षण जारी है। अभी तक 10415 प्रशिक्षणार्थी का Assesment एवं Certification हो चुका है, 228 का प्लेसमेंट हो चुका है। शहरी बेघरों हेतु रैन बसेरा (Shelter for Urban homeless) के लिए 48 नये रैन बसेरा (Homeless Shelter) विभिन्न नगर निकाय में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इनमें से 13 जगहों पर रैन बसेरा (Homeless Shelter) निर्माणाधीन है। इसके लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। पूर्व निर्मित रैन बसेरा की मरम्मति एवं चालू करने हेतु 6.00 लाख/प्रति रैन बसेरा की दर से 66 रैन बसेरा के लिए राशि विमुक्त की गई है। रैन बसेरा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे एरिया लेवल ऑर्गनाइजेशन [Area level organization (ALO)] से जोड़ा गया है। फुटपाथ दुकानदारों के हितों की देख–रेख हेतु "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017" एवं "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017" अधिसूचित किया गया है। सभी नगर निकाय में टाउन वेडिंग कमिटी [Town Vending Committee (TVC)] का गठन किया जा चुका है। सर्वेक्षित दुकानदारों को बसाने हेतु 482 वेडिंग जोन (Vending zone) चिन्हित किये गये हैं, जबकि मोतिहारी में एक वेडिंग जोन (Vending zone) निर्माणाधीन है। 42 शहरों में टाउन लेवल फेडरेशन [Town Level Federation (TLF)] का गठन किया जा चुका है।

(iii) **सबके लिए आवास (शहरी) HFA** – इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में दी गयी है। इस योजना के तहत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। HFA योजना के निम्नलिखित घटकों में कार्य जारी हैं :–

- **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण** – इस घटक के अन्तर्गत राज्य के सभी 140 नगर निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 51690 घरों का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से 12880 आवासीय इकाईयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आवास का निर्माण लाभूकों द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए ₹150000.00 (एक लाख पचास हजार रु०) भारत सरकार एवं ₹50000.00 (पचास हजार रु०) मात्र राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध करायी जा रही है। योजना की मिशन अवधि 2015–22 है। योजनान्तर्गत पुनः सभी नगर निकायों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

- **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी** – इस घटक के तहत पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIU) द्वारा आवास के निर्माण के लिए लिये गये ₹6.00 लाख (छः लाख रु०) तक के गृह ऋण पर ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।

(iv) **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना** :– यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 11 नगर निगम (पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर), 15 नगर परिषद् (बक्सर दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सिवान, छपरा, बगहा, बेतिया, एवं मोतिहारी) एवं नगर पंचायत बोधगया में कार्यान्वित की जानी है। इसके अन्तर्गत जलापूर्ति योजना, हरित स्थल/पार्क का विकास, फुटपाथ का निर्माण आदि कार्य किया जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्टेट ऐनुअल ऐक्शन प्लान (SAAP-I) में कुल ₹66420.00 लाख (छः सौ चौसठ करोड़ बीस लाख रु०) अनुमानित व्यय पर 14 जलापूर्ति योजना एवं 26 पार्क विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के SAAP-II में कुल ₹77520.00 लाख (सात सौ पचहत्तर करोड़ बीस लाख रु०) मात्र अनुमानित व्यय पर 07 जलापूर्ति योजना, 2 ड्रेनेज योजना एवं 20 पार्क विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। SAAP-I में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹6642.00 लाख (छियासठ करोड़ बयालीस लाख रु०) एवं इसके अनुपातिक प्रथम किस्त राज्यांश की राशि ₹3985.20 लाख संबंधित नगर निकाय/कार्यान्वयन एजेंसी को विमुक्त किया गया है। इसी प्रकार SAAP-II में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹7752.00 लाख (सतहत्तर करोड़ बावन लाख रु०) एवं इसके अनुपातिक प्रथम किस्त राज्यांश की राशि ₹4651.20 लाख (छियालीस करोड़ एकावन लाख बीस हजार रु०) संबंधित नगर निकाय/कार्यान्वयन एजेंसी को विमुक्त किया गया है।

(v) **स्मार्ट सिटी योजना** :– इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर का प्रस्ताव स्वीकृत है। भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु SPV का गठन कर लिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए ₹130930.00 लाख (तेरह सौ नौ करोड़ तीस लाख रु०) की स्वीकृति प्रदत्त की गयी है जिसमें 50:50 अनुपात में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी ₹92641.00 लाख (नौ सौ छब्बीस करोड़ एकतालीस

Optimized by www.ImageOptimizer.net

लाख रु०) की है तथा शेष राशि Convergence तथा PPP के तहत् स्वीकृत है। इसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ₹9000.00 लाख (नब्बे करोड़ रु०) वर्ष 2016–17 में विमुक्त की गयी है।

(vi) **पटना मेट्रो रेल परियोजना** :– इस परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति राज्य मंत्रिपरिषद् से प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(vii) **ADB संपोषित भागलपुर एवं गया जलापूर्ति योजना** :– भागलपुर जलापूर्ति योजना ₹49300.00 लाख (चार सौ तिरानवे करोड़ रु०) लागत पर स्वीकृत है। कार्यकारी एजेंसी बुडको को ₹9000.00 लाख (नब्बे करोड़ रु०) विमुक्त है। इस योजना पर अबतक ₹3430.00 लाख (चौंतीस करोड़ तीस लाख रु०) व्यय हो चुका है। गया जलापूर्ति योजना की स्वीकृति ₹37621.00 लाख (तीन सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख रु०) पर प्राप्त है। इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को 24×7 दिन स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

(viii) **NGRBA / नमामी गंगे योजना** :– यह योजना राज्य के गंगा नदी तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में कार्यान्वित है। इसके अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय एवं मुंगेर में Sewerage Scheme का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जबकि पटना में गंगा नदी तट का विकास योजना चालू है। पटना में 20 गंगा घाटों को विकसित करने का कार्य जारी है, जिसमें 12 घाटों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना पर लगभग ₹26227.00 लाख (दो सौ बासठ करोड़ सताईस लाख रु०) व्यय होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बेऊर सीवरेज एवं बेऊर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य तथा सैदपुर सीवरेज एवं सैदपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा करमलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति प्राप्त है।

(ix) **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना** :– राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जन्मदिन 02 अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जारी किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी नगर निकाय में लागू की गयी है, इसके तहत निम्नलिखित कार्य किया जाना है :–

(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण। (ii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण।

(iii) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। (iv) ठोस कचरा प्रबंधन।

(v) सूचना, शिक्षा एवं जन–जागरूकता। (vi) क्षमता वृद्धि तथा प्रशासनिक कार्य।

✦ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई प्रमुख घटक है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकायों को विशेष स्वच्छता अनुदान के रूप में निम्नलिखित कार्य हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है :–

- डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय
- कचरे के प्रबंधन हेतु कचरा निस्तारण स्थल का क्रय / विकास
- कचरे से कम्पोस्ट / बिजली बनाने की योजना में सहायता
- नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण
- सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलबध कराना।
- राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यापक पैमाने पर इन सभी घटकों पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के कुल 3323 वार्डों में से 2473 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण में आधे से अधिक वार्डों में आउट सोर्सिंग (Outsourcing) एजेंसी लगायी गयी है एवं शेष वार्डों में नगर निकाय कर्मियों को लगाया गया है।

7. **बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा नागरिक सुविधायें त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं :–**

नगर निकायों / जिला शहरी विकास अभिकरणों के बेहतर प्रशासन तथा नागरिक सुविधाओं में वृद्धि तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निम्नांकित पद सृजित किये गये है :–

(i)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	–	130
(ii)	नगर प्रबंधक	–	152
(iii)	कार्यपालक अभियंता	–	35
(iv)	सहायक अभियंता	–	70
(v)	कनीय अभियंता	–	201

8. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 के अंतर्गत वर्णित विभिन्न पदों के आलोक में "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली 2015" का गठन किया जा चुका है।

9. नगर निकायों के बेहतर प्रशासन हेतु कुल 108 कार्यपालक पदाधिकारी के पदों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। तथापि वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर पर्यवेक्षीय सेवा के 72 कार्यपालक पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। साथ ही नगर प्रबंधक के कुल 152 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित किया गया है।

10. बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2017 लागू किया गया है, जो 01 फरवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

11. **राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के क्रम में 12 हजार से अधिक जनसंख्या वाले अर्हत्ता प्राप्त ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने की कार्रवाई पर चल रही है। साथ ही कतिपय पूर्व से गठित नगर निकायों के उत्क्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में निम्नलिखित निकायों को उत्क्रमित/गठित किया गया है :–**

(i) नगर परिषद्, छपरा को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया।

(ii) नगर पंचायत, बख्तियारपुर एवं फतुहा को नगर परिषद् में उत्क्रमित किया गया।

(iii) नगर पंचायत, बारसोई एवं हरनौत का गठन किया गया।

(iv) नगर पंचायत, बरबीघा को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना निर्गत की गयी।

12. **सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अरबन रिफॉर्म्स (स्पर) प्रोजेक्ट की उपलब्धियाँ :**

(i) **ई० नगरपालिका (E. Municipality)** :– ई० नगरपालिका को 11 नगर निगमों, 42 नगर परिषदों तथा बोधगया एवं राजगीर नगर पंचायतों में लागू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत इन नगर निकायों में ऑनलाईन सेवाएँ जैसे जन्म–मृत्यु पंजीकरण, सम्पत्ति कर, भवन निर्माण योजना की स्वीकृति, निबंधन और अनुज्ञप्ति, सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकार अधिनियम, विधि प्रबंधन, अंकेक्षण प्रबंधन, बिहार विधान मंडल के प्रश्न और उत्तर, भण्डार/गोदाम प्रबंधन और सूचना तकनीकी मदद), विज्ञापन और होर्डिंग, किराया, पट्टा और सैरात, कार्यप्रवाह और दस्तावेज प्रबंधन पद्धति लागू की जा चुकी हैं कर्मियों के प्रबंधन की पद्धति को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।

(ii) **भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित नक्शा** :– वर्ष 2016–17 से पूर्व 23 शहरों का GIS Map बना लिया गया था जबकि वर्ष 2016–17 में 06 शहरों आरा, छपरा, सिवान, राजगीर, हाजीपुर और बिहारशरीफ के लिए GIS Map बनाने का कार्य ₹210.80 लाख (दो करोड़ दस लाख अस्सी हजार रु०) की लागत से पूर्ण किया जा चुका है। 28 शहरों सोनपुर, दिघवारा, रिविलगंज, अरवल, भभुआ, हिलसा, बक्सर, डुमरांव, जहानाबाद, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, मनेर, महनार, फतुहा, बीहट, खगड़िया, समस्तीपुर, मोकामा, सुलतानगंज, नवगछिया, बाढ़, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, कहलगाँव, तेघरा और बड़हिया शहरों के लिए GIS Map के कार्य हेतु ₹448.00 लाख (चार करोड़ अड़तालीस लाख रु०) की लागत से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 12 शहरों अररिया, बेनीपुर, फारबिसगंज, गोपालगंज, मधुबनी, मधेपुरा, मनिहारी, नरकटियागंज, बगहा, रक्सौल, सुपौल और शिवहर का ₹245.00 लाख (दो करोड़ पैंतालीस लाख रु०) की लागत के कार्य की निविदा प्रक्रिया में है, जिसका व्यय विभाग के ई–गवर्नेस बजट के तहत् वहन किया जायेगा।

(iii) **GIS आधारित प्रॉपर्टी सर्वे** :– GIS मैप में प्रोपर्टी के विवरण को समाहित करने का कार्य 02 शहरों पूर्णयाँ तथा कटिहार नगर निगम का वर्ष 2016–17 से पहले पूर्ण हो चुका है, जबकि वर्ष 2016–17 में 06 शहरों मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, जमालपुर, किशनगंज में ₹337.00 लाख (तीन करोड़ सैंतीस लाख रु०) की लागत से कार्य पूर्ण हो चुका है। 07 शहरों भागलपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, सासाराम और डेहरी डालमियानगर में ₹771.70 लाख (सात करोड़ एकहत्तर लाख सत्तर हजार रु०) की लागत से कार्य चल रहा है। 14 शहरों पटना, बोधगया, खगौल, फुलवारीशरीफ, दानापुर, आरा, छपरा, सिवान, राजगीर, हाजीपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, सीतामढ़ी और सहरसा शहरों के लिए कुल ₹1630.45 लाख (सोलह करोड़ तीस लाख पैंतालीस हजार रु०) लागत की प्रोपर्टी सर्वे का कार्य निविदा प्रक्रिया में है, जिसका व्यय AMRUT (अमृत) प्रोजेक्ट के तहत् वहन किया जायेगा।

(iv) **GIS आधारित मास्टर प्लान** :– पटना शहर का मास्टर प्लान पूर्व में ही बना लिया गया है जिसमें खगौल, फुलवारीशरीफ तथा दानापुर शहर भी शामिल है, जिसका अनुमोदन भी किया जा चुका है। 26 शहरों गया, बोधगया, नवादा, औरंगाबाद, डेहरी डालमियानगर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, आरा, छपरा, सिवान, हाजीपुर, बिहारशरीफ, जहानाबाद, बक्सर, बगहा और राजगीर का मास्टर प्लान बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया में है।

(v) **कस्टमाइज्ड बेव बेस्ड जी०आई०एस० एप्लीकेशन (Customised Web Based GIS Application)** :– Customised Web Based GIS Application की निविदा प्राप्त की जा चुकी है। इसके अंतर्गत पूरे राज्य के शहरों के लिए एक Software बनाया जायेगा जिसके द्वारा नागरिक Internet के माध्यम से GIS Map आधारित सूचना देख सकते हैं तथा सारे नगर निकाय इसका उपयोग योजना बनाने में कर सकते हैं। इस कार्य की अनुमानित लागत ₹700.00 लाख (सात करोड़ रु०) है।

(vi) **दोहरी लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System)** :– राज्य के सभी नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली ₹1450.00 लाख (चौदह करोड़ पचास लाख रु०) लागत से लागू की गयी है, जो कि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली पर आधारित है।

122 शहरों में वर्ष 2015–16 तक के लिये दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 09 शहरों हवेली खड़गपुर, लखीसराय, बड़हिया, शेखपुरा, बरबीघा, खगड़िया, गोगरी जमालपुर, जमुई और झाझा में वर्ष 2015–16 तक के लिये दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(vii) **आंतरिक अंकेक्षण** :– सभी नगर निकायों में ₹82.90 लाख (बयासी लाख नब्बे हजार रु०) की लागत से आंतरिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के लिये कराया जा रहा है, जिसमें से वर्ष 2014–15 के लिये आंतरिक अंकेक्षण का कार्य सभी नगर निकायों में पूर्ण किया जा चुका है तथा 2015–16 एवं 2016–17 का आंतरिक अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(viii) **SPUR (स्पर) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाएँ :–** भारत सरकार की विभिन्न मिशन योजनाओं यथा– स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, अमृत के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु 35 शहरों में लगभग ₹185700.00 लाख (अठारह अरब संतावन करोड़ रु०) राशि की ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाएँ, 15 शहरों में लगभग ₹109700.00 लाख (दस अरब संतानवे करोड़ रु०) राशि की इंटरसेपशन एवं डाइवरजन (I&D) सीवरेज योजनाएँ, 09 शहरों में लगभग ₹137100.00 लाख (तेरह अरब एकहत्तर करोड़ रु०) राशि की River Front Development योजनाएँ, 22 शहरों में लगभग ₹488700.00 लाख (अड़तालीस अरब सतासी करोड़ रु०) की सीवरेज योजनाएँ एवं 12 शहरों की ₹17429.00 लाख (एक अरब चौहत्तर करोड़ उनतीस लाख रु०) की लागत से शवदाह गृह, धोबीघाट तथा सामुदायिक शौचालयों की योजनाएँ बनायी गयी हैं इनमें से 05 शहरों गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया और सिवान की ₹40300.00 लाख (चार अरब तीन करोड़ रु०) की राशि की ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाएँ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत की जा चुकी है। 505 मलीन बसितयों में स्वीकृत आधारभूत संरचना कार्यों के अंतर्गत 11673 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सामूहिक विकास समिति द्वारा कराया गया एवं अन्य 956 व्यक्तिगत शौचालय निर्माणधीन है। मलीन बस्तियों में आधारभूत संरचना कार्यों हेतु ₹10703.00 लाख (एक अरब सात करोड़ तीन लाख रु०) की राशि 27 निकायों को स्थानांतरित की गयी थी जो लगभग पूरी राशि व्यय की जा चुकी है।

(ix) **अन्य उपलब्धियाँ :–**

- State level पर Revenue के Monitoring के लिये Revenue टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- सम्पत्ति कर Waiver Scheme का मंत्रीमंडल से अनुमोदन।
- राज्य के सभी शहरों में अपशिष्ठ प्रसंस्करण स्थापित करने हेतु एक Standard RFP तैयार कर सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

13. **विभाग की कई योजनाओं का कार्य बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लि० (BUIDCO) द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है, जो निम्नवत् हैं :–**

- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत कुल 39 बस स्टैण्ड निर्माण योजना में से कुल 09 बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल 21 बस स्टैण्ड निर्माण की योजनाएँ प्रगति पर है।
- राज्य के कुल 12 शहरों में एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- पटना शहर में 97 स्थानो पर ट्रैफिक लाईट सिस्टम का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
- जमालरोड, एस०पी० वर्मा रोड सहित पटना जंक्शन क्षेत्र से जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु एस०पी० वर्मा रोड से मंदिरी नाला तक नाला निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- फुलवारीशरीफ जलापूर्ति योजना, बोधगया जलापूर्ति योजना, लोहानीपुर जलापूर्ति योजना एवं खाजेकला जलापूर्ति योजना पूर्ण कर लिया गया है साथ ही पटना के 18 जोन में जलापूर्ति योंजना, झंझारपुर जलापूर्ति योजना, नौबतपुर जलापूर्ति योजना एवं भागलपुर जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर है।
- बोधगया, हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर में सिवरेज सिस्टम तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रगति पर है।
- एन०जी०आर०बी०ए० के तहत् पटना में गंगा तट का विकास कार्य प्रगति पर है।
- पटना में बुडको के सौजन्य से 141 बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है।

14. **बिहार राज्य आवास बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :–**

- दलपतपुर आरा के 16.50 एकड़ भूखण्ड पर 1054 फ्लैटों के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है तथा इसके प्रचार–प्रसार की कार्रवाई की जा रही है।
- बरारी, भागलपुर आवासीय कॉलोनी के 3.72 एकड़ भूखण्ड पर कुल 272 फ्लैटों के निर्माण हेतु पुर्ननिविदा की कार्रवाई अंतिम चरण में है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में बोर्ड की सम्पदाओं के आवंटन के लिए आरक्षण नीति लागू किया जा चुका है। जितवारपुर, समस्तीपुर में अर्जित भूखण्डों को आवासीय व्यावसायिक एवं आवासीय सह व्यवसायिक भूखण्डों में चिह्नित कर आरक्षण नीति के आधार पर आवंटित करने की प्रक्रिया की जा रही है तथा चहारदीवारी निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा का वित्तीय बीड खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

15. **नगर तथा क्षेत्रीय निदेशन संगठन (TCPO) की उपलब्धियाँ :–**

- पटना महायोजना 2031 वर्ष 2016–17 में अधिसूचित किया गया है, जो कि वर्ष 2031 तक के लिए तैयार किया गया है।
- पटना महायोजना 2031 को कार्यान्वित कराने के उद्देश्य से पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर के शहरों/अमृत योजना के तहत् चयनित शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने की निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :–
  - (i) इसके तहत् 05 शहरों यथा– आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, गया एवं सहरसा के आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है। इन आयोजना क्षेत्रों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
  - (ii) अमृत योजना के तहत् चयनित राज्य के शेष 22 शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप तैयार किया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्तावित बजट

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के व्यय वहन हेतु कुल ₹43,35,01,21,000.00 (तैंतालीस अरब पैंतीस करोड़ एक लाख इक्कीस हजार रुपये) का उपबंध माँग संख्या– 48 के अंतर्गत प्रस्तुत है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए ₹16,00,40,15,000.00 (सोलह अरब चालीस लाख पंद्रह हजार रुपये) तथा योजना व्यय के लिए ₹27,34,61,06,000/– (सताईस अरब चौंतीस करोड़ एकसठ लाख छः हजार रुपये) का प्रस्ताव है।

(ii) मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से तीन निश्चय नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। राज्य योजना व्यय के तहत "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के लिए ₹23000.00 लाख (दो सौ तीस करोड़ रु०) "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के लिए ₹31000.00 करोड़ (तीन सौ दस करोड़ रु०) तथा प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण योजना हेतु राज्यांश के रूप में ₹16000.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रु०) अर्थात् कुल ₹70000.00 करोड़ (सात सौ करोड़ रु०) का बजट प्रस्तावित है।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सहित DAY-NULM योजना में ₹22500.00 लाख (दो सौ पच्चीस करोड़ रु०), सबके लिए आवास योजना में ₹42575.92 लाख (चार सौ पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार रु०) AMRUT योजना में ₹63304.00 लाख (छः सौ तैंतीस करोड़ चार लाख रु०) तथा स्मार्ट सिटी मिशन योजना में ₹16000.00 लाख (एक सौ साठ करोड़ रु०) का प्रस्ताव है।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय।

(महेश्वर हजारी)
मंत्री
नगर विकास एवं आवास विभाग